R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2024-26

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 23 । अंक : 04
16 से 30 नवम्बर 2024
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

INVEST MADHYA PRADESH

मप्र में इन्वेस्ट सबसे बेस्ट

निवेश के लिए लगी होड़, 2,82,700 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले

विदेशी निवेशकों को लुभाने ब्रिटेन-जर्मनी जाएंगे सीएम डॉ. मोहन

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

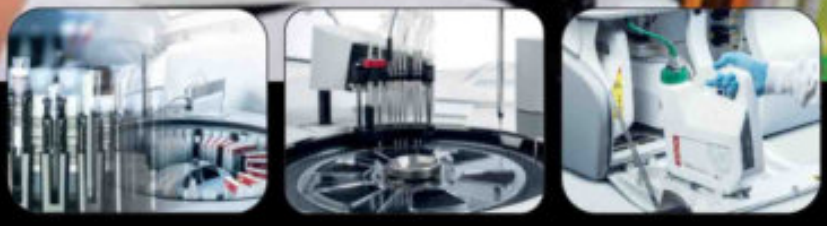

BA200

BioSystems

The Highest Flexibility

Address : M-179, Gautam Nagar,
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

तैयारी

9 | केंद्रीय योजनाओं की रिपोर्ट लेंगे...

केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन और उनका लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाने में मप्र, देश में लगातार अग्रणी बना हुआ है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश को कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं।

डायरी

10-11 | तबादले में किसकी...

मप्र सरकार ने 11 नवंबर को बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करते हुए 26 बड़े अफसरों के तबादले कर दिए। तबादले के बाद प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में कहा जा रहा है कि तबादले में किसकी चली है।

मप्र कांग्रेस

15 | युवा निकालेंगे कांग्रेस को...

मप्र में पिछले दो दशक से राजनीति के मझधार में फंसी कांग्रेस को अब युवा नेता निकालेंगे। इसके लिए आलाकमान ने युवा नेताओं को प्रदेश संगठन में उपाध्यक्ष, महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही अब इन युवा नेताओं...

राजपथ

16-17 | किसके हाथ लगेगी बाजी ?

मप्र की दो विधानसभा सीटों- विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव के लिए मतदान समाप्त होने के बाद अब सबकी नजर 23 नवंबर पर है, जिस दिन मतगणना होगी। बुधनी सीट पर 77.32 प्रतिशत और विजयपुर में 77.85 प्रतिशत मतदान हुआ है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की जो पहल की है उसके परिणाम स्वरूप मप्र में निवेश करने के लिए औद्योगिक घरानों में होड़ लग गई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि मप्र में अब तक 2,82,700 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। जो इस बात का संकेत है कि निवेशक यह मान रहे हैं कि मप्र में इन्वेस्ट... सबसे बेस्ट। रीजनल इंडस्ट्रीयल समिट की सफलता को देखते हुए अब मुख्यमंत्री भोपाल में होने वाली ग्लोबल...

राजनीति

30-31 | रेवड़ियों का चुनाव

मुफ्त, मुफ्त, मुफ्त... चुनाव आते ही किसी क्लीयरेंस सेल जैसा माहौल बन जाता है। रस्ते का माल सस्ते में की तर्ज पर राजनीतिक पार्टियां वादे पर वादा करती जाती हैं और अब तो ज्यादातर पार्टियां सरकार बनते ही उन वादों को पूरा करने में भी जुट जाती हैं। कई दशक पहले दक्षिणी राज्यों...

महाराष्ट्र

35 | असली बनाम नकली की जंग

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां कमर कसती हुई दिख रही हैं, जहां अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग सियासी मुकाबला बनता नजर आ रहा है। वहीं महाराष्ट्र चुनाव में असली और नकली का खेल भी देखने को मिलेगा, क्योंकि शिवसेना भी दो हैं और...

बिहार

38 | पीके के निशाने पर कौन ?

चर्चित चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की नवनिर्मित जन सुराज पार्टी ने राज्य में होने वाले चार विधानसभा उपचुनावों में तरारी सीट से सेना के रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल श्रीकृष्ण सिंह को उम्मीदवार बनाकर सियासी हलचल पैदा कर दी है।

6 -7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

पाक्षिक अक्स

वर्ष-23, अंक-04, पृष्ठ-48
16 से 30 नवंबर, 2024

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

प्रमुख संवाददाता

भावना सक्सेना-भोपाल, जय मतानी-भोपाल,
हर्ष सक्सेना-भोपाल,
दक्ष दवे-इंदौर, संदीप वर्मा-इंदौर,
विपिन कंधारी-इंदौर, गौरव तिवारी-विदिशा,
ज्योत्सना यादव-गंजबासौदा, राजेश तिवारी-उज्जैन,
टोनी छाबड़ा-धार, आशीष नेमा-नरसिंहपुर,
अनिल सोडानी-नई दिल्ली, हसमुख जैन-मुंबई,
इंद्र कुमार बिन्नानी-पुणे।

प्रदेश संवाददाता

पारस सरावगी (इंदौर)
09329586555
नवीन रघुवंशी (इंदौर)
09827227000 (इंदौर)
धर्मेन्द्र कथूरिया (जबलपुर)
098276 18400
श्यामसिंह सिकरवार (उज्जैन)
094259 85070
सुभाष सोमानी (रतलाम)
089823 27267
मोहित बंसल (विदिशा)
075666 71111

क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी, फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

अपनी बात

कब हटेगा तबादलों से बैन...?

भोपाली शायर बशीर बद्र का एक शेर है...

अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा
मगर तुम्हारी तरह कौन मुझ को चाहेगा..

शायर ने यह शेर किस संदर्भ में लिखा है यह तो वे ही बता सकते हैं। लेकिन मप्र के अधिकारी-कर्मचारी इस शेर को तबादलों पर लगे बैन के संदर्भ में गुनगुना रहे हैं। अधिकारी-कर्मचारी व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि प्रदेश सरकार तबादलों पर से बैन इसलिए नहीं हटा रही है कि उसे यहां (वर्तमान पदस्थापना) के लिए हमारे जैसा कर्मचारी कहां मिलेगा। दरअसल, प्रदेश में नई सरकार को बने 11 माह से अधिक हो गए हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक तबादलों पर से बैन नहीं हटाया है। अगले महीने-अगले महीने कहते-कहते साल पूरा होने जा रहा है। उधर, जबसे प्रदेश में नए प्रशासनिक मुखिया आए हैं, उन्होंने तो समन्वय में भी फाइलें जाने पर रोक लगा दी है। इससे यह हो रहा है कि मंत्री और विधायक भी तबादले नहीं करा पा रहे हैं। जबकि मंत्री और विधायक तबादले करवाकर ही अपनी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ाते हैं। आलम यह है कि प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के धनाधन तबादले हो रहे हैं। पिछले दिनों ही 26 आईएएस के तबादलों के बाद एक और बड़ी सूची आने वाली है। प्रदेश में भले ही आईएएस और आईपीएस के ट्रांफसर हो रहे हों, लेकिन कर्मचारियों को फिलहाल कोई भी राहत मिलते नहीं दिख रही है। अभी मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सभी अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक लगी है। वहीं, नई तबादला नीति भी अब तक नहीं आ पाई है। ट्रांसफर से भी सरकार ने प्रतिबंध नहीं हटाया है। प्रदेश के सरकारी विभाग में कार्यरत कर्मचारी अभी नई तबादला नीति की बाट जोह रहे हैं। प्रदेश में जुलाई से तबादलों पर प्रतिबंध हटने की खबर आ रही है। लेकिन अब तक तबादला नीति नहीं आ पाई है। वहीं, मोहन सरकार मतदाता सूची का काम और बीच में कर्मचारियों के ट्रांसफर करने के पक्ष में नहीं है। जानकारों का कहना है कि मोहन सरकार तबादले की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन करने में जुटी हुई है। अब मंत्रालय में ई-फाइलिंग सिस्टम पर काम चल रहा है। इस दौरान सरकार ने सभी विभागों को ऑनलाइन फाइलें भेजने को कहा है। अभी कई विभाग ऑफलाइन फाइलें भेजते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने अब मंत्रालय में पदस्थ तृतीय श्रेणी लिपिकों की पदस्थापना की प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर दी है। नई तबादला नीति तैयार है, बस मुख्यमंत्री की मुहर लगना बाकी है। हालांकि तबादलों पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी और अगले साल ही इस पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का मानना है कि साल के बीच में तबादले करने से शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ेगा और इससे अव्यवस्था फैलेगी। अब सरकार का कहना है कि तबादलों का सबसे ज्यादा असर स्कूल शिक्षा विभाग पर पड़ेगा। अगर अभी तबादले हुए तो बड़ी संख्या में शिक्षकों का तबादला होगा, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। सूत्रों के मुताबिक अब मार्च या अप्रैल में ही तबादलों पर से रोक हटने की उम्मीद है। तबादलों को लेकर कहा जा रहा है कि एक जिले से अन्य जिले में ट्रांसफर करने का अधिकार विभागीय मंत्री को मिलेगा, जबकि एक जिले में से उसी जिले में अन्य जगह पर टांसफर का अधिकार प्रभारी मंत्री को दिया जाएगा। राजपत्रित अधिकारियों का तबादला सीएम समन्वय से हो सकते हैं।

- राजेन्द्र आगाल

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

मास्टरप्लान को तरसा भोपाल

मप्र की राजधानी भोपाल का मास्टर प्लान 20 सालों से अधर में है। अब तक चार बार भोपाल के मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी हुआ, लेकिन अमलीजामा पहनाने से पहले ही इतने अड़ंगे आए कि सरकार को न चाहते हुए भी इसे रद्द करना पड़ा। सरकार को जल्द से जल्द इसे तैयार कराना चाहिए।

● **धीरज वर्मा,** भोपाल (म.प्र.)

मजबूती दिखाए कांग्रेस

कांग्रेस आलाकमान ने युवा नेताओं को प्रदेश संगठन में उपाध्यक्ष, महासचिव की जिम्मेदारी तो सौंप दी है, लेकिन कांग्रेस को अभी और मजबूती दिखानी होगी। अब केवल युवाओं के सहारे ही मप्र में पिछले दो दशक से राजनीति के मझधार में फंसी कांग्रेस निकल सकती है।

● **मृदुल मीणा,** इंदौर (म.प्र.)

विकास को मिलेगी गति

मप्र के एक्सप्रेस-वे और हाईवे के किनारे इंडस्ट्रियल रीजन तैयार किए जाएंगे। प्रारंभिक चरण में दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर के साथ पांच एक्सप्रेस-वे और हाईवे का चयन किया गया है। इनके आसपास करीब 24 हजार एकड़ शासकीय भूमि चिन्हित की गई है। इससे मप्र में विकास को गति मिलेगी।

● **रूपाली सिंह,** बैतूल (म.प्र.)

सिंहस्थ में उभरेगी मप्र की छवि

महाकाल महालोक बनने के बाद से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन आते हैं। निरंतर धार्मिक आयोजनों का क्रम जारी रहता है। उज्जैन की पहचान साधु-संतों से है। हर 12 साल पर यहां एक बार सिंहस्थ कुंभ मेला का भव्य आयोजन होता है। सिंहस्थ-2028 को लेकर भी तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार भी कुंभ मेले को ऐतिहासिक रूप देने की तैयारी की जा रही है। देश के कोने-कोने से यहां आने वाले साधु-संतों के ठहरने, कथा, भागवत जैसे धार्मिक आयोजनों के लिए सरकार पूरी व्यवस्था करने में जुटी है। प्रदेश सरकार ने साधु-संतों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का मन बनाया है। इससे जहां एक तरफ प्रदेश में पर्यटकों का आवागमन होगा, वहीं देश में मप्र की छवि भी उभरेगी।

● **नेहा सारण,** रायसेन (म.प्र.)

केंद्र सरकार की योजनाओं का डंका

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा समाज के शोषित, वंचित, पीड़ित व सर्वहारा वर्ग के हितों में अनेक ऐतिहासिक एवं कल्याणकारी निर्णय लिए गए हैं। महिला सशक्तिकरण के साथ ही नौजवानों की बेहतरी के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। विकसित भारत का सपना संजोए भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर भाजपा के सदस्यता अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। कांग्रेस को भी भाजपा की तरह मजबूत बनना होगा।

● **अभिषेक मिश्रा,** राजगढ़ (म.प्र.)

शिकार न बनें महिलाएं

डायन बिसाही सदीयों क्रूर कुप्रथा भारत के 12 राज्यों में अधिक है, इसमें झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मप्र, छत्तीसगढ़, उप्र, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और असम शामिल हैं। यह क्रूर प्रथा कम आय वाले इलाकों और ऐसे समुदायों में जहां सामाजिक, आर्थिक असमानता के अलावा लैंगिक असमानता हावी है, में जिंदा है। इस प्रकार की प्रथाओं पर अंकुश लगाने के सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। जिससे महिलाओं को शिकार न बनना पड़े।

● **अंकुर जायसवाल,** ग्वालियर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

एन बीरेन सिंह से त्रस्त भाजपा

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से भाजपा आलाकमान परेशान हो चला है। राज्य में मैती-कुकी समुदायों के मध्य विवाद बीते डेढ़ बरस से शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। 2023 से जारी हिंसा में दो सौ से अधिक नागरिक मारे जा चुके हैं और 65 हजार के करीब विस्थापना का शिकार हो चुके हैं। बीरेन सिंह मैती समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन पर आरोप है कि वे अपने समुदाय को कुकी समुदाय के खिलाफ उकसाते भी हैं और मैती उपद्रवियों को संरक्षण भी देते हैं। राज्य के हालात बेहद विकट हैं, इतने विकट कि तमाम आलोचनाओं के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक मणिपुर का दौरा करने नहीं गए हैं। खबर गर्म है कि अब भाजपा आलाकमान ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन का फैसला कर लिया है। खबर यह भी जोरों पर है कि नए मुख्यमंत्री की शपथ के बाद ही प्रधानमंत्री राज्य का दौरा करेंगे। राज्य के 19 भाजपा विधायकों ने पार्टी आलाकमान को बीरेन सिंह के खिलाफ पत्र तक लिख डाला है। सूत्रों का कहना है यह पत्र केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर ही लिखा गया है ताकि बीरेन सिंह को हटाए जाने की कवायद शुरू की जा सके। चर्चा जारों पर है कि विधानसभा के स्पीकर थोंगम बिस्बजीत को पार्टी नेतृत्व नया मुख्यमंत्री बनाने पर विचार कर रहा है।

कमजोर पड़ती ममता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की छवि एक बेहद तेजतर्रार और लड़ाकू नेता की रही है। पश्चिम बंगाल में दशकों से सत्ता में काबिज वामपंथियों को अपनी इसी लड़ाकू स्टाइल की बदौलत ममता 2011 में सत्ता से बेदखल कर पाई थीं। लेकिन अब उनकी छवि ऐसी नेता की बनने लगी है जिसके नियंत्रण से हालात तेजी से फिसल रहे हैं। कोलकत्ता रेप केस के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने धरना-प्रदर्शन और बेमियादी हड़ताल कर ममता बनर्जी की आयरन लेडी वाली छवि को ध्वस्त करने का काम किया है। कोलकत्ता के सत्ता गलियारों में कानाफूसी का दौर इस बात को लेकर चल रहा है कि यदि ऐसे ही हालात रहे तो 2026 के विधानसभा चुनाव पार्टी कैसे जीत पाएगी? चर्चा ममता के भतीजे और उनके वारिस कहलाए जाने वाले अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली को लेकर भी जमकर होने लगी है। ममता के पुराने सहयोगियों को अभिषेक सख्त नापसंद हैं। ऐसे में कमजोर पड़ती ममता बनर्जी पर उनके सहयोगी दबाव बनाने लगे हैं कि वे पार्टी मामलों में अभिषेक के हस्तक्षेप को कम करें। चर्चा तो यह भी है कि यदि हालात ज्यादा बिगड़ते तो तृणमूल के कई बड़े चेहरे भाजपा की शरण में जा सकते हैं।

संघ के ब्रह्मास्त्र से बेचैन कांग्रेस

कांग्रेस नेता राहुल गांधी जातीय जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बना पाने में सफल रहे हैं। उनकी रणनीति इसके जरिए दलित और ओबीसी मतदाताओं को साधने की है जिसमें वे आम चुनाव के दौरान सफल होते दिखे भी हैं। महाराष्ट्र में मराठाओं और दलितों ने भाजपा के खिलाफ एकजुट हो मतदान किया जिसका नतीजा रहा कि एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 31 पर पराजित हो गया। उप्र में भी भाजपा की सीटें 62 में से घटकर मात्र 37 रह गईं। अब दलित, ओबीसी और आदिवासियों को साधने के लिए और राहुल की जातीय जनगणना की काट के लिए भाजपा ने इन जातियों को भी हिंदुत्व के बैनर तले लाने की कवायद जोर-शोर से शुरू कर दी है। पहली बार संघ के दबाव में आकर हिंदुओं के 13 मठों में से सबसे बड़े मठ जूना अखाड़ा ने दलित और आदिवासी समाज के संतों को मान्यता देने का निर्णय ले डाला है। खबर गर्म है कि जूना अखाड़ा इन समाजों के 71 संतों को महामंडलेश्वर की उपाधि देने जा रहा है ताकि इन्हें भी हिंदू एकता का पाठ पढ़ाया जा सके। भाजपा और संघ के तरकश से निकले इस ब्रह्मास्त्र का कितना असर होगा और कांग्रेस इसकी काट कैसे करेगी यह देखा जाना बाकी है।

विकास नहीं हिंदुत्व ही सर्वोपरि

प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में केंद्र की सत्ता संभालने के बाद सबका साथ, सबका विकास का नारा दिया था। बीते 10 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री हर मंच से यही दावा करते हैं कि उनके शासनकाल में देश में अद्भुत विकास हुआ है लेकिन जब और जहां कहीं भी चुनाव होते है प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुत्व का मुद्दा गर्मा वोट मांगने की कवायद शुरू कर देते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की घोषणा बाद एक बार फिर से विकास बेचारा हाशिए में जा पड़ा है और भाजपा और संघ एक बार फिर से हिंदुत्व को आगे कर मतदाताओं को रिझाने में जुट गए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने दशहरा संबोधन में हिंदुओ को संगठित होने का आव्हान करते हुए यहां तक कह डाला कि दुर्बल रहना अपराध है जिसे भगवान भी पसंद नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी ने भी महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित करते हुए हिंदुओं से एक रहने की अपील की। उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे सरीखे बयान ने तो राजनीति पहले ही गर्मा दी है।

आखिर खड़गे को क्या हुआ

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते रोज मुंबई में उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना उन पर कटाक्ष करके कांग्रेस के लिए एक और मुश्किल खड़ी कर दी है। खड़गे ने कहा था कि कई नेता साधु के वेश में रहते हैं और अब राजनेता बन गए हैं। कुछ तो मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। उन्होंने भाजपा को संबोधित करके कहा कि उनके नेता सफेद कपड़े पहनें। या अगर वे संन्यासी हैं तो गेरुआ कपड़े पहनें, और राजनीति से बाहर हो जाएं। खड़गे के इस बयान का सीधा अर्थ यह लगाया जा रहा है कि कांग्रेस कह रही है कि गेरुआ और भगवा वस्त्र यानी साधु के कपड़े पहनने वालों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। दरअसल कांग्रेस का इतिहास रहा है कि पार्टी में मुल्ला और मौलाना अगर होते थे तो साधु और संतों को भी पर्याप्त सम्मान मिलता रहा। शायद यही कारण रहा कि मुस्लिम लीग के सामने हिंदुओं की पार्टी के रूप में कांग्रेस को मान्यता दी गई।

ये कमरा क्यों बंद रहता है... ?

फिल्म 'मैं तुलसी तेरे आंगन की' के गीत- ये खिड़की जो बंद रहती है... आपने सुना ही होगा। इसी तरह प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक अधिकारी के कक्ष को लेकर भी चर्चा है कि ये कमरा क्यों बंद रहता है? दरअसल, मामला यह है कि पुलिस मुख्यालय में स्थित इस कक्ष में अन्य कक्षों की तरह वैसे तो सामान्य कामकाज होता रहता है, लेकिन जब लंच होता है तो इस कक्ष में कुछ ऐसा होता है जिसकी चर्चा अब आम हो गई है। सूत्रों का कहना है कि दोपहर डेढ़ बजे के करीब जब लंच होता है तो सारे अधिकारी-कर्मचारी लंच के लिए रवाना होने लगते हैं। अधिकतर अधिकारी तो अपने घर चले जाते हैं, जबकि कर्मचारी पीएचक्यू में ही लंच करने में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन जिस कक्ष की चर्चा हो रही है, उस कक्ष में बैठने वाले साहब लंच टाइम में जरूरी काम में जुट जाते हैं। बताया जाता है कि लंच टाइम में ही एक विभागीय अधिकारी साहब के कक्ष में आती हैं और करीब एक-सवा घंटे तक उसी कक्ष में रहती हैं। कहा जा रहा है कि साहब की मीटिंग का वही समय है और उस दौरान गंभीर चर्चा होती है। अंदर साहब क्या करते हैं, यह तो किसी को नहीं पता, लेकिन हर कोई अपने-अपने तरीके से अनुमान लगाने में जुट जाता है। इस मीटिंग को लेकर पीएचक्यू में तरह-तरह की चर्चा चल रही है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जब सभी अधिकारी-कर्मचारी लंच के बाद अपने ऑफिस की ओर लौट रहे होते हैं, उस समय साहब लंच के लिए घर की ओर रवाना होते हैं।

जलवा हो तो ऐसा...

सत्ता का रसूख ही कुछ ऐसा होता है कि मंत्री बनते ही नेता जलवेदार हो जाते हैं। हर मंत्री की कोशिश होती है कि वह अपने को दूसरे से कुछ इस तरीके से अलग दिखाए कि उसका जलवा चर्चा में रहे। लेकिन प्रदेश सरकार के एक मंत्री तो ऐसे हैं जिनका जलवा देखकर हर कोई यह कहने को मजबूर हो जाता है कि जलवा हो तो ऐसा हो।

माननीय राजनीतिक घराने से आते हैं और युवा अवस्था से ही राजनीति में सक्रिय हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने को हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और इसके लिए वैसा दिखावा भी करते हैं। वर्तमान में माननीय के पास प्रदेश सरकार में महत्वपूर्ण विभाग है। ऐसे में मंत्रीजी के शौक भी निराले हैं। उनको जानने वालों का कहना है कि वे अपने आपको सरकार के मुखिया से भी ऊपर दिखाने की होड़ में लगे रहते हैं। इसी के तहत उन्होंने अपने आसपास ऐसा कौकस बुन रखा है कि जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है। दरअसल, माननीय जहां भी जाते हैं उससे पहले उनके वॉकी-टॉकी से लैस निजी सहायक ऐसा प्रदर्शन करते हैं जैसे कोई बड़ी राजनीतिक हैसियत का आगमन हो रहा है। मंत्रीजी का तामझाम देखकर लोग यहां तक कहने लगे हैं कि ये भले ही राज्य के मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन भोपाल के मुख्यमंत्री तो बन ही गए हैं।

नहीं छूट रहा एमपी-02 का मोह

मप्र कैडर के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इन दिनों अपनी एक अजब-गजब मांग के लिए चर्चा में हैं। इन साहब के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अफसरशाही की सारी सुख-सुविधाओं को भोगा है। लेकिन रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे साहब की मांग सुनकर हर कोई हैरान है और उनके सहयोगी कह रहे हैं कि इतना लंबा प्रशासनिक अनुभव होने के बाद भी साहब ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं। दरअसल, साहब के पास इस समय दोहरा चार्ज है। साहब के पास पहले से जो विभाग था, उस विभाग की तरफ से साहब को सारी सुविधाएं मिली हैं। वहीं साहब को जो दूसरी जिम्मेदारी मिली है, उसके लिए भी वे दोहरी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। साहब की जिस मांग से लोग हैरान है, वह है एमपी-02 सीरीज वाली गाड़ी। दरअसल, साहब विवादों में रहने वाले एक मंडल की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। ऐसे में साहब ने मांग की है कि उनके पास डबल विभाग है, इसलिए दो गाड़ी दी जाए। यहां तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने अपनी मांग में यह भी जोड़ा है कि उन्हें जो भी वाहन दिया जाए, वह एमपी-02 वाला होना चाहिए। जबकि नियमों में इसका प्रावधान नहीं है। मंडल में पदस्थ रहने वाले अफसरों को नियम के अनुसार वाहन मिलता है। लेकिन साहब ने साफ-साफ शब्दों में कह दिया है कि उन्हें वाहन कोई भी दो, लेकिन वह एमपी-02 सीरीज वाला ही होना चाहिए। बता दें ये साहब प्रशासन की सबसे बड़ी कुर्सी के भी दावेदार थे।

आखिर वह अफसर कौन ?

जबसे नए प्रशासनिक मुखिया ने कमान संभाली है, अफसरों की आए दिन क्लास लगती रहती है। ऐसी ही एक क्लास में प्रशासनिक मुखिया उखड़े-उखड़े नजर आए और उन्होंने 4-5 अफसरों की तरफ देखते हुए कहा कि आप लोग अपर मुख्य सचिव बन गए, लेकिन बाबू जो पुटअप करता है उसी पर साइन कर देते हो। मुख्य सचिव की यह बात सुनकर अफसर एक-दूसरे का मुंह ताकने लगे। दरअसल, सूत्रों का कहना है कि कुछ अफसर ऐसे हैं जो मंत्रालय में तत्परता से काम करने की बजाय बाबुओं के भरोसे काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक एसीएस ने अपने बाबू द्वारा लिखी गई नोटशीट को हस्ताक्षरित कर अनुमोदन के लिए प्रशासनिक मुखिया के पास भेज दिया था। जब बड़े साहब ने उक्त नोटशीट को पढ़ना शुरू किया तो उसमें कई तरह की खामियां सामने आईं। जिसके बाद साहब समझ गए कि विभागीय प्रमुख ने इस नोटशीट को पढ़ा नहीं है। फिर क्या था, उन्होंने बैठक में इसको लेकर नाराजगी जताई। अब लोग इस पड़ताल में जुट गए हैं कि वह अफसर कौन थे जो एसीएस बन गए लेकिन नोटशीट नहीं पढ़ते।

जो लालाजी करें, वही सही

प्रदेश के कमाऊ विभागों में शामिल एक विभाग में इन दिनों अजब-गजब माहौल है। आलम यह है कि विभागीय मंत्री की आड़ में उनके खासमखास मनमानी करने में जुटे हुए हैं। यह सब मंत्री और उनके पुत्र की शह पर हो रहा है या उनकी पीठ पीछे, यह तो मंत्रीजी ही जानें, लेकिन जिस तरह का माहौल है, उससे तो लोग यही कह रहे हैं कि सबकुछ मंत्रीजी और उनके पुत्र के संरक्षण में चल रहा है। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश के दो बड़े शहरों में एक ही जाति के दो अफसर पदस्थ हैं। जिन्हें लोग लालाजी कहते हैं। बताया जाता है कि जब विभागीय अधिकारी-कर्मचारी किसी छापेमारी में अवैध गतिविधियों में जुटे हुए वाहनों को पकड़ते हैं तो उसे छुड़ाने आने वाले लोगों से कहा जाता है कि लालाजी से संपर्क करें। सूत्र बताते हैं कि प्रदेश के दो बड़े शहरों में पदस्थ ये दोनों लालाजी अपने तरीके से बातचीत कर मामले को निपटाते हैं और मुंह मांगी रकम मिलने के बाद आरोपियों को भी क्लीन चिट दे देते हैं। बताया जाता है कि ये दोनों लालाजी मंत्रीजी के खासमखास हैं। इनके कारनामों में मंत्रीजी की मिलीभगत है कि नहीं यह तो नहीं पता, लेकिन मंत्रीजी की साख गिर रही है।

अब घर बैठे हो रही जमीन रजिस्ट्री

नवाचारों के लिए ख्यात मप्र में सरकार ने संपदा 2.0 लॉन्च किया है। इसका फायदा यह हो रहा है कि लोगों को अब घर बैठे रजिस्ट्री करवाने की सुविधा मिलना शुरू हो गई है। दरअसल 10 अक्टूबर से प्रदेश में लागू किए गए रजिस्ट्री के नए सॉफ्टवेयर संपदा 2.0 के तहत राजधानी सहित प्रदेशभर में रजिस्ट्री शुरू हो गई है। संपदा के नए सॉफ्टवेयर की वजह से सेवा प्रदाता का काम बढ़ गया है। उन्हें स्लाट बुक करने के लिए रजिस्ट्री के अधिक दस्तावेज अपलोड करने पड़ेंगे। क्रेता, विक्रेता और गवाहों का सही डाटा भी संपदा के सॉफ्टवेयर में अपलोड करने के बाद ही स्लाट बुक होगा।

जमीन, मकान-दुकान आदि की रजिस्ट्री को लेकर मप्र सरकार की इस अनूठी पहल की सर्वत्र सराहना हो रही है। अब आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर राज्य में प्रॉपर्टी की खरीदी-बिक्री कर सकेंगे। इसकी रजिस्ट्री के लिए आपको राजधानी भोपाल या अपने स्थानीय शहर में आने की जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कुशाभाऊ इंटरनेशनल कनवेंशन सेंटर में इसे लॉन्च किया है। इस सॉफ्टवेयर से प्रदेश के सभी जिलों को कनेक्ट किया गया है। संपदा 2.0 के लॉन्च के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संपदा 2.0 की शुरुआत आम लोगों की सुविधा के लिए हो रही है। इससे करप्शन पर भी लगाम लगेगा। उन्होंने कहा कि मप्र का आदमी जहां भी रहेगा, वह आसानी से अपनी प्रॉपर्टी बेच और खरीद सकता है। ऐसा विदेश से भी वह बैठकर कर सकेगा। इससे लोगों का समय भी बचेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब मप्र में नामांतरण के लिए पटवारी के घर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि पहले नामांतरण के लिए सालों लगा जाते थे अब हफ्ते दो हफ्ते में काम हो जाएगा। संपदा 2.0 का मतलब ये है कि राज्य में अब ई-पंजीयन और ई-स्टेम्पिंग की शुरुआत हो गई है। अब राज्य में पूरी तरह से पेपरलेस और फेसलेस रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद आपको रजिस्ट्री कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब रजिस्ट्री कराने वाले लोगों के पास तीन विकल्प होंगे। पहला यह कि आप दस्तावेजों के बिना कार्यालय आएं और वीसी के माध्यम से रिमोट रजिस्ट्रेशन करा लें। दूसरे दस्तावेजों के लिए 24×7 उपलब्ध फेसलेस पंजीयन की सुविधा भी होगी। तीसरी विकल्प ये है कि आप स्लाट बुक कराकर निर्धारित तारीख और समय पर रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाएं। जमीन की रजिस्ट्री के लिए पेपर देने की अब कोई जरूरत नहीं है। अब पक्षकारों की जानकारी सीधे आधार से और भूमि-संपत्ति की जानकारी भू-अभिलेख और स्थानीय निकाय पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है। ई-मेल, वॉट्सएप और डिजिलॉकर के जरिए भी दस्तावेज उपलब्ध होंगे।

सरकार का दावा है कि अब संपदा पोर्टल एवं मोबाइल एप के माध्यम से मॉडल डीड सहित अन्य दस्तावेज तैयार करने, स्टाम्प ड्यूटी की गणना, स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान और स्लाट बुकिंग अब एकदम आसान होगा। इसके साथ ही अब पहचान के लिए गवाह की जरूरत नहीं होगी। कलेक्टर गाइडलाइन दरें, स्टाम्प शुल्क, पूर्व पंजीकृत दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। अहम ये है कि इस योजना के लॉन्च होने पर कई लोगों ने विदेश से ही बैठे-बैठे अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री कराई।

संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर का लाभ यह है कि इससे पंजीयन की व्यवस्था सुगम, सरल और भ्रष्टाचार मुक्त बनेगी। लोग घर बैठे अपनी प्रॉपर्टी को बेच भी सकेंगे और रजिस्ट्री करा सकेंगे। इस प्रणाली से प्रदेश ही नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के बाहर से भी ऑनलाइन रजिस्ट्रियां कराई जा सकेंगी। रजिस्ट्री करवाने वाला खुद डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट कर सकेगा। पोर्टल से ही डॉक्यूमेंट लिखा और भेजा जाएगा। अब कागज या स्कैनर पर साइन के बजाय आधार नंबर डीड को सत्यापित करेगा। पक्षकारों की पहचान आधार व पैन नंबर से होगी। प्रॉपर्टी की पहचान नक्शे पर गाइडलाइन लोकेशन की जियो टेगिंग से होगी। जियो टेगिंग से नक्शे का चयन होते ही, प्रॉपर्टी का मूल्यांकन व स्टाम्प ड्यूटी की जानकारी आ जाएगी। रजिस्ट्री करवाने रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा (हालांकि यह अनिवार्य नहीं है)। वीडियो केवाईसी या सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से रजिस्ट्री करवा सकेंगे। पेपरलेस प्रणाली है। रजिस्ट्री के बाद डॉक्यूमेंट पीडीएफ में मेल या वाट्सएप पर ही दोनों पक्षों को मिल जाएंगे। गवाहों की आवश्यकता नहीं होगी। यह सॉफ्टवेयर निगम, राजस्व, पंचायती राज, टीएंडसीपी व अन्य विभागों के साथ सर्वर टू सर्वर जुड़ा होगा। रजिस्ट्री के पहले या बाद में यह डेटा विभागों में एक्सचेंज हो सकेगा।

● **सुनील सिंह**

ठगी में लगेगी लगाम

भूमाफियाओं की ठगी से लोगों को बचाने के लिए पंजीयन विभाग ने संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है, इसके लागू होते ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री का पूरा काम संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर पर हो रहा है। नई व्यवस्था के बाद इस धोखाधड़ी पर अंकुश लग गया है। गौरतलब है कि मप्र में रजिस्ट्री से संबंधित ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे। अब ऐसे साइबर ठगी के मामले को लेकर पंजीयन विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। जिसका तोड़ संपदा-2.0 के इंतजार के साथ हो रहा है। यह संपदा-2.0 रूपी हथियार न केवल पक्षकारों को बल्कि पंजीयन विभाग के अफसरों को भी राहत प्रदान करेगा। रजिस्ट्री के समय आधार कार्ड, पैन कार्ड व बायोमैट्रिक्स से छेड़छाड़ कर पक्षकार की पहचान बदलने के मामले तेजी से बढ़े हैं। अब पंजीयन विभाग का दावा है संपदा-2.0 में इस तरह के ठगी के मामले रुकेंगे।

केंद्रीय योजनाओं की रिपोर्ट लेंगे मुख्यमंत्री

केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन और उनका लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाने में मप्र, देश में लगातार अग्रणी बना हुआ है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश को कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास की जो गंगा प्रवाहित हो रही है उसमें प्रदेश के विभागों का कितना योगदान है उसका हिसाब-किताब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंत्रियों और अधिकारियों से लेंगे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री दिसंबर में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले राज्य की केंद्रीय योजनाओं की छमाही समीक्षा करेंगे। इस समीक्षा में खासतौर पर भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के लक्ष्यों पर ध्यान दिया जाएगा। सभी विभागों से यह रिपोर्ट ली जाएगी कि केंद्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को कितना हासिल किया गया है। इस समीक्षा में संबंधित विभागों के मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे, जो योजनाओं की प्रगति और चुनौतियों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार की जिन योजनाओं के क्रियान्वयन में मप्र देश में अग्रणी है उसमें पीएम स्व-निधि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम आवास योजना, कृषि अवसंरचना निधि, प्रधानमंत्री मातृ-वंदना योजना, पीएम स्वामित्व योजना, नशामुक्त भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और स्वच्छ भारत मिशन शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री अन्य योजनाओं को गति देने में लगे हुए हैं। इसलिए वे विभागों में चल रही केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रिपोर्ट लेंगे। उधर, वित्त विभाग सभी विभागों का लेखा-जोखा तैयार कर रहा है। इसमें आवंटित राशि के उपयोग के साथ यह भी देखा जाएगा कि किस-किस विभाग ने भारत सरकार से बजट में प्रस्तावित राशि प्राप्त कर ली है और आगे उसे प्राप्त करने की क्या कार्ययोजना है। विभागीय समीक्षा के बाद मंत्रियों और अधिकारियों को लंबित परियोजनाओं की राशि स्वीकृत कराने के लिए दिल्ली भेजा जाएगा।

दरअसल, सभी विभागों में भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। इनके लिए जो लक्ष्य निर्धारित हैं, वे पूरे हुए या नहीं, इस पर संबंधित विभाग के मंत्री और अधिकारियों से रिपोर्ट ली जाएगी। गौरतलब है कि मप्र को वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार से 44,891 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता का प्रविधान किया गया है। इसके अलावा, केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 95,753 करोड़ रुपए की राशि 14 किस्तों में दी जानी है, जिसमें से दीपावली से पहले 14,000 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। सरकार ने जुलाई 2024 में पूर्ण बजट पेश किया था, और सभी विभागों को लेखानुदान और पूर्ण बजट की राशि मिलाकर आवंटन किया जा चुका है। इस वित्तीय सहायता का उपयोग राज्य की विकास योजनाओं और परियोजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे आवंटित बजट का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करें ताकि निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जा सके। अब मुख्यमंत्री स्वयं इस बजट उपयोग की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही, राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट की तैयारी भी प्रारंभ कर दी है। उपसचिव स्तर के अधिकारियों की बैठकें शुरू हो गई हैं, जिनमें प्रत्येक विभाग से उनकी योजनाओं में आवंटित बजट और उसके उपयोग का विवरण लिया जा रहा है। इसका उद्देश्य अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करने में योजना और खर्च की स्थिति का स्पष्ट आंकलन करना है।

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सभी विभागों से पिछले छह माह का लेखा-जोखा लेंगे और आगामी माह की कार्ययोजना पर चर्चा करेंगे। इस समीक्षा में विशेष रूप से उन विभागों पर ध्यान दिया जाएगा जो आवंटित राशि का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाए हैं। ऐसे विभागों से राशि समर्पित कराकर उन विभागों को दी जाएगी जिनकी योजनाओं और परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य बजट का अधिकतम और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना और प्रदेश की विकास योजनाओं को गति देना है। केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में मप्र देश में अव्वल है और मुख्यमंत्री की कोशिश है कि यह प्रगति और रफ्तार पकड़े। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 8 लाख 40 हजार 940 आवास निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध 8 लाख 20 हजार 575 आवास बनाए जा चुके हैं। योजना में उपलब्धि 97.58 प्रतिशत है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में 37 लाख 98 हजार 709 आवास निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध 36 लाख 25 हजार 20 आवास बनाए जा चुके हैं। योजना में उपलब्धि 95.43 प्रतिशत है। जल जीवन मिशन में 83 लाख 27 हजार 582 के लक्ष्य के विरूद्ध 72 लाख 89 हजार 228 नल कनेक्शन (हर घर-नल से जल) प्रदाय कर 87.53 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की जा चुकी है। आयुष्मान भारत योजना में 4 करोड़ 70 लाख 96 हजार 914 आयुष्मान कार्ड जारी करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 4 करोड़ 2 लाख 22 893 आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। योजना में उपलब्धि का प्रतिशत 85.83 है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 72 हजार 994 किलामीटर ग्रामीण सड़क बनाने के लक्ष्य के विरूद्ध 72 हजार 965 किलामीटर सड़क निर्माण किया जा चुका है।

● **जितेंद्र तिवारी**

शिवराज सिंह के नेतृत्व में बना है मॉनीटरिंग ग्रुप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक निगरानी समूह का गठन किया है। सूत्रों के अनुसार, इस समूह का मुख्य काम मोदी सरकार द्वारा घोषित योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना है। जानकारी के अनुसार, इस समूह की पहली बैठक 18 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें विभिन्न सचिवों ने भाग लिया था। इस ग्रुप की बैठक हर महीने होगी। सूत्रों ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह का मॉनीटरिंग ग्रुप बनाया हो। इससे पहले 2014 और 2019 में भी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अन्य केंद्रीय मंत्रियों को इसी तरह की जिम्मेदारी दी थी। इस ग्रुप का मकसद सरकार द्वारा घोषित योजनाओं की समीक्षा करना और उनकी खामियों के बारे में बताना है। जानकारी के अनुसार, इसको लेकर संबंधित अधिकारियों द्वारा विस्तृत रिपोर्ट मांगी जाती है।

तबादले में किसकी चली?

मप्र सरकार ने 11 नवंबर को बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करते हुए 26 बड़े अफसरों के तबादले कर दिए। तबादले के बाद प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में कहा जा रहा है कि तबादले में किसकी चली है। जिस तरह मुख्यमंत्री सचिवालय से दो प्रमुख सचिवों को हटाया गया है और अन्य अफसरों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, उससे यह बात तो साफ है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन के समन्वय से ये तबादले हुए हैं। हालांकि जिस तरह कुछ अफसरों को साइडलाइन किया गया है, उससे यह साफ है कि इस तबादले में मुख्य सचिव की चली है।

ऊर्जा विभाग के एसीएस 1991 बैच के आईएएस मनु श्रीवास्तव को खेल व युवक कल्याण विभाग का जिम्मा दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि मनु श्रीवास्तव विभाग में काम नहीं कर रहे थे और दिनभर मीटिंग-मीटिंग खेल रहे थे। इस कारण इनका विभाग बदला गया। वहीं 1993 बैच के आईएएस एसीएस नीरज मंडलोई से नगरीय विकास का प्रभार लेकर उन्हें ऊर्जा विभाग दे दिया गया है। बताया जाता है कि बड़े विभाग से मंडलोई की विदाई के पीछे कुछ पेंच थे। गौरतलब है कि मंडलोई परिश्रमी अधिकारियों में गिने जाते हैं। 1994 बैच के आईएएस अधिकारी प्रमुख सचिव संजय शुक्ल को मुख्यमंत्री सचिवालय से हटाकर गृह निर्माण, अधोसंरचना विकास मंडल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। संजय शुक्ला हार्डवर्कर अधिकारी हैं। उनकी काबिलियत को देखकर इस बड़े विभाग की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। वे पहले भी इस विभाग में रह चुके हैं। उनके पास लगभग सभी विभागों में काम करने का अनुभव है। साथ ही विभागीय मंत्री के साथ उनकी ट्यूनिंग को देखते हुए उन्हें नगरीय प्रशासन विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैलाश विजयवर्गीय को नीचा दिखाने के लिए राजनीति का खेल खेला है। क्योंकि जब विजयवर्गीय इंदौर में महापौर थे, उस समय संजय शुक्ला इंदौर नगर निगम आयुक्त थे। परंतु अब इन्हें ब्रीफिंग करके यहां भेजा गया है, जिससे अब विभाग में उनके काम भी नहीं हुए।

उमाकांत हुए पावरफुल

इस तबादले के बाद 1996 बैच के आईएएस अधिकारी उमाकांत उमराव पावरफुल प्रमुख सचिव बन गए हैं। क्योंकि प्रमुख सचिव श्रम विभाग को खनिज साधन विभाग, पशुपालन व डेयरी विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है तथा खनिज निगम का प्रबंध संचालक तथा संचालक भौमिकी व खनिकर्म का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हालांकि इनके बारे में कहा जाता है कि ये काम लटकाने में माहिर हैं। वहीं 1997 बैच के राघवेंद्र सिंह पांचवी मंजिल के निशाने पर थे। इसलिए पहले उन्हें साइडलाइन किया गया फिर मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव जैसे दमदार पद से मुक्त किया गया। हालांकि उन्हें अब औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग और सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। वहीं मप्र गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के आयुक्त मनीष सिंह को परिवहन विभाग का अपर सचिव, मप्र राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रबंध संचालक तथा इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी भोपाल का कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इन्हें दो माह पहले ही हाउसिंग बोर्ड में पदस्थ किया गया था। लेकिन उन्हें वहां से हटा दिया गया। हालांकि मनीष सिंह काम करने वाले अफसरों में हैं। इसलिए सीएम ने सीएस को जो काम सौंपा है, यानि सड़क परिवहन निगम को चालू करना, उसके लिए उन्हें यहां पदस्थ किया गया है। सिंह के पास इसका अनुभव भी है, क्योंकि नगर निगम में रहते हुए उन्होंने बीसीएलएल बस सेवा शुरू की थी। पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव और पर्यावरण आयुक्त तथा एप्को के महानिदेशक गुलशन बामरा को जनजाति कार्य विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। बामरा ईमानदार और कर्त्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं, इसलिए उन्हें बमुश्किल स्वतंत्र प्रभार दिया गया है।

कलेक्टरों के ट्रांसफर अभी नहीं

प्रदेश में कलेक्टरों और पुलिस के तबादले फिलहाल अभी नहीं होंगे। इसकी वजह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जा रहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान है। मतदाता सूची का कार्य 7 जनवरी 2025 तक चलेगा। इस अवधि तक जिलों में अधिकारियों के थोकबंद तबादले नहीं होंगे। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य पूरा होते ही जनवरी महीने में ही प्रदेश में फिर बड़ी सर्जरी होगी। जिसमें दो दर्जन से ज्यादा जिलों के कलेक्टर से लेकर अन्य अधिकारियों के थोकबंद तबादले होंगे। जिनमें नायब तहसीलदार, तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं। फिलहाल मैदानी अधिकारी चुनाव कार्य की वजह से नहीं हटाए गए हैं। सरकार यदि जिलों में कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकार, तहसीलदार का तबादला करती है तो चुनाव आयोग से सहमति की औपचारिकता पूरी करनी होगी। फिलहाल मैदानी अधिकारियों पर अगले दो महीने तक तबादले का कोई संकट नहीं है। हालांकि इस बीच विशेष वजह से एक-दो जिलों के अधिकारियों को हटाया भी जा सकता है। उधर, संभावना जताई जा रही है कि जनवरी में पुलिस के थोकबंद तबादले होंगे।

पांडे जी लेकर डूब गए

जनजाति कार्य विभाग, अनुसूचित जाति के प्रमुख सचिव तथा आयुक्त आदिवासी विकास डॉ. ई. रमेश कुमार अब सिर्फ अजा कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव ही रहेंगे। बताया जाता है कि उन्हें पंचायत विभाग के एक पांडे जी लेकर डूब गए। दरअसल, पांडे जी इनके लिए व्यवस्थापक थे। जिससे इनकी खूब बदनामी हुई। यहां बता दें कि साहब अपने डायवोर्स के कारण भी विवादों में रहे हैं। 2001 बैच के

आईएएस अधिकारी के शौक निराले थे। इसलिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के सचिव, उद्योग आयुक्त, लघु उद्योग निगम के एमडी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे डॉ. नवनीत मोहन कोठारी को पर्यावरण विभाग का सचिव एवं पर्यावरण आयुक्त तथा महानिदेशक एप्को का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। 2007 बैच के आईएएस अधिकारी शहडोल संभाग के आयुक्त श्रीमन शुक्ल को आयुक्त आदिवासी विकास मप्र भोपाल बनाया गया है। पूर्व मंत्री के दामाद इन साहब को भोपाल आना था, इसलिए इन्हें इस विभाग में पदस्थ किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक प्रियंका दास को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग का अपर सचिव बनाया गया है। प्रियंका दास को स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ हुए बहुत दिन हो गए थे।

भुगतना पड़ा खामियाजा

मप्र खनिज निगम के प्रबंध संचालक तथा खनिज साधन विभाग के पदेन अपर सचिव तथा प्रशासन एवं खनिकर्म, संचालनालय भौमिक एवं खनिकर्म के संचालक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे अनुराग चौधरी को पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का अपर सचिव बनाया गया है। बताया जाता है कि अनुराग चौधरी का पांचवी मंजिल से अच्छा संबंध नहीं था। हालांकि जब वे ग्वालियर में कलेक्टर बने थे तो पांचवी मंजिल के एक पावरफुल अधिकारी को चंद दिनों में हटाकर कलेक्टर बने थे, जिसका खामियाजा अब उन्हें मिला है।

पुरुषोत्तम को बड़ी जिम्मेदारी

2012 बैच के प्रमोटी आईएएस अधिकारी पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के उपसचिव कुमार पुरुषोत्तम को प्रबंध संचालक कृषि विपणन बोर्ड, सह आयुक्त मंडी मप्र भोपाल बनाया गया है। पुरुषोत्तम 4 जिलों की कलेक्टरी कर चुके हैं। वे हार्डवर्कर अफसरों में गिने जाते हैं। वे बहुत दिनों से नई पदस्थापना का इंतजार कर रहे थे। उनकी कार्यक्षमता को देखते हुए कृषि विपणन बोर्ड जैसी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जहां वरिष्ठ अफसर पदस्थ होते थे। वहीं भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की विकअ की सह आयुक्त सह संचालक तथा पर्यावरण नियोजन व समन्वय संगठन एप्को की कार्यपालन संचालक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही डॉ. सलोनी सिडाना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मिशन संचालक, मप्र पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लि. के प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। सिडाना जूनियर अधिकारी हैं, लेकिन उन्हें बड़े विभाग दिए गए हैं। यह उनके लिए चुनौती भरा होगा, क्योंकि उन्हें इन विभागों को संभालना मुश्किल होगा।

मप्र के डीजीपी के लिए 21 को दिल्ली में होगी यूपीएससी की बैठक

तीन नामों की बनेगी पैनल

मप्र में जल्द ही नए डीजीपी की नियुक्ति होगी। इसे लेकर 21 नवंबर को नई दिल्ली में यूपीएससी की बैठक होने वाली है। जिसमें यूपीएससी के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित कोई सदस्य, केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, राज्य के मुख्य सचिव, वर्तमान डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह भाग लेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने डीओपीटी को 9 नामों का पैनल भेज दिया है। माना जा रहा है कि इस पैनल में से जिन तीन नामों का आखिरी पैनल बनेगा, उसमें वर्ष 1988 बैच के आईपीएस अफसर एवं डीजी होमगार्ड अरविंद कुमार, इसी बैच के पुलिस हाउंसिंग कारपोरेशन के चेयरमेन कैलाश मकवाना और वर्ष 1989 बैच के डीजी ईओडब्ल्यू अजय शर्मा का नाम शामिल है। इन अफसरों के नाम की चर्चा भोपाल से लेकर दिल्ली तक चल रही है। तीनों ही अफसर भी अपने-अपने दावे के साथ मजबूती से इस पद तक पहुंचने का प्रयास भी कर रहे हैं। क्योंकि मप्र में अभी तक नियमानुसार ही डीजीपी का चयन होता आया है। तीन नामों का पैनल बनने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जिसे चाहेंगे उसे पुलिस महानिदेशक की कमान सौंप सकते हैं। गौरतलब है कि 30 नवंबर को मौजूदा डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना रिटायर हो रहे हैं। इसलिए शासन का लक्ष्य है कि इससे पहले ही नए अफसर का चयन किया जाए। उधर, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 28 से 30 नवंबर तक डीजी-आईजी कांफ्रेंस आयोजित होना है। इस कांफ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल होंगे। इस कांफ्रेंस के दौरान ही डीजीपी सुधीर सक्सेना रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में यह माना जा रहा है कि उनकी जगह पर पुलिस मुख्यालय के ओएसडी प्रदेश पुलिस की तरफ से लीड कर सकते हैं। जो प्रदेश पुलिस का पक्ष और यहां पर जो कामकाज किए गए उनकी जानकारी प्रधानमंत्री, गृहमंत्री के सामने प्रस्तुत करेंगे। अब देखना यह है कि डीजीपी सुधीर सक्सेना के रिटायरमेंट होने से कितने दिन पहले सरकार नए डीजीपी बनने वाले अधिकारी को पुलिस मुख्यालय के ओएसडी के रूप में नियुक्त करती है।

● राजेंद्र आगाल

कोर्ट जाने की सुगबुगाहट

इधर, प्रशासनिक वीथिका में यह चर्चा जोरों पर है कि तीन अधिकारियों की पैनल में शामिल जिन दो अफसरों को डीजीपी बनने का मौका नहीं मिलेगा, वे कोर्ट जाने को भी तैयार हैं। हालांकि इसमें कितनी सत्यता है, यह तो भविष्य में पता चलेगा। जानकारों का कहना है कि शायद ही कोई अधिकारी इस राजनीति में फंसने की कोशिश करे। क्योंकि अगर वह ऐसा करते हैं तो शेष नौकरी के दौरान उनके सामने परेशानी खड़ी हो सकती है।

अब जनता सीधे चुनेगी 'अध्यक्ष'

डॉ. मोहन यादव सरकार त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव प्रणाली में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में जिला पंचायत, जनपद पंचायत अध्यक्ष और नगर परिषदों के अध्यक्षों का चुनाव डायरेक्ट प्रणाली अर्थात् जनता से कराया जाएगा। महापौर और नपा अध्यक्षों को जनता सीधे वोट देकर सदन में भेजती है उसी तरह चुनाव कराए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी प्रस्ताव की तैयारियों में जुट गए हैं। जानकारी के अनुसार जल्द ही इस संबंध में सरकार चुनाव प्रणाली में बदलाव के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव ला सकती है। इसके बाद प्रस्ताव पास कर विधानसभा में सदन के पटल पर रखा जाएगा। बहुमत से पास होने के बाद पंचायती राज अधिनियम में बदलाव कर इसे राजपत्र में प्रकाशित कराकर लागू किया जा सकता है। इसके बाद चुनाव आयोग ये चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करा सकता है।

प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जिला और जनपद पंचायत चुनाव होते हैं, उनमें अभी तक अध्यक्ष का चुनाव गैर दलीय आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें हॉर्स ट्रेडिंग अर्थात् धनबल और बाहुबल खूब चलता है और सदस्यों की खरीद-फरोख्त भी होती है। मप्र की डॉ. मोहन यादव सरकार इस पर लगाम लगाने की तैयारी में जुट गई है। संभव है आगामी दिनों में जिला, जनपद और नगर परिषदों के अध्यक्ष के चुनाव डायरेक्ट होंगे, अर्थात् जनता इन्हें सीधे चुन सकती है। सरकार की तरफ से कैबिनेट में जल्द ही इस आशय का प्रस्ताव लाया जा सकता है। मप्र में फिलहाल कुल 52 जिला पंचायत हैं। इनमें भाजपा समर्थित अध्यक्ष 40, कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष 10, गोंगपा समर्थित अध्यक्ष 1 और सीधी जिला पंचायत में कोर्ट केस के कारण चुनाव नहीं हुए थे। बता दें कि 2019 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनने के बाद चुनाव में बदलाव किया गया था। सरकार ने चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली यानी निर्वाचित पार्षदों के जरिए कराने का फैसला लिया था। इसके बाद शिवराज सरकार ने इस फैसले को पलट दिया था।

सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनकी कैबिनेट के सदस्य जिला पंचायत और जनपद पंचायत अध्यक्ष के चुनाव सीधे जनता से कराने को लेकर राजी हैं। चुनावी प्रणाली और प्रक्रिया में जो बदलाव किया जाएगा उसमें दलीय आधार पर ही चुनाव होंगे। जैसे महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशियों को राजनीतिक पार्टियां मेनडेट जारी कर अपना प्रत्याशी घोषित करती हैं, खुलकर चुनावी कैम्पेन होता है, ठीक उसी तरह जिला और जनपद पंचायत अध्यक्षों के चुनाव भी कराए जाएंगे। जनता से सीधे चुनकर आने वाले जनप्रतिनिधि जिनमें सांसद, विधायक, महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष शामिल हैं। वे जनता के प्रति सीधे तौर पर जवाबदेह होते हैं और जनहितैषी कार्यों के प्रति उनकी रिस्पांसबिलिटी भी होती है। वहीं, गैरदलीय और अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले चुनावों में धनबल और बाहुबल से चुनाव जीतने वाले अध्यक्ष जनता के प्रति उदासीन हो जाते हैं। वे चुनाव में किए गए खर्च को लेकर ज्यादा चिंतित होते हैं। जिला पंचायत और जनपद पंचायत के सदस्य भी दम से अध्यक्ष के सामने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की बात नहीं कर पाते। चूंकि सदस्यों की खरीद-फरोख्त खूब होती है, इसलिए कई सदस्य तो जुबान भी नहीं खोल पाते। इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है और विकास कार्य बाधित होते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में जनता से सीधे चुनकर आने वाले अध्यक्षों पर दबाव नहीं होगा और वे विकास कार्यों पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे।

दरअसल, पंचायत के चुनाव वास्तव में गैरदलीय आधार पर कराए जाते हैं। राजनीतिक दल सीधे उम्मीदवारों को टिकट प्रदान नहीं करते, बल्कि उन्हें समर्थन देते हैं। इस कारण इन चुनावों में जोड़-तोड़ और खरीद-फरोख्त ज्यादा होती हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि ये चुनाव सीधे कराए जाए तो जनप्रतिनिधियों की जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ेगी। पंचायती राज और नगर निगम मामलों के जानकारों का मानना है कि यदि सरकार जिला जनपद और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट करने पर विचार कर रही है तो इसके लिए पहले नगर पालिका और पंचायत राज अधिनियम में संशोधन होगा। विधानसभा सत्र के दौरान पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय आवास और विकास विभाग की ओर से अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने लाया जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद कानून में विधानसभा से संशोधन होगा। जानकारों के मुताबिक डायरेक्ट चुनाव कराने का फैसला अच्छा है। इस व्यवस्था से सौदेबाजी और धमकी देने पर रोक लगेगी। फिलहाल जो व्यवस्था से चुनाव हो रहे हैं उससे सही आदमी चुनकर नहीं आ पाता। चुनाव में बदलाव होने से लोकप्रिय व्यक्ति चुनाव जीतेगा। सीधे चुनाव जीतकर जो व्यक्ति आता है उसकी जवाबदारी ज्यादा होती है। उसे पता होता है कि अगली बार चुनाव जीतने के लिए जनता के बीच जाना है तो काम करना होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष के चुनाव सीधे कराने के लिए सरकार की तैयारी को लेकर अभी अधिकारी और मंत्री खुलकर बोलने से बच रहे हैं।

● **अरविंद नारद**

अभी भी सामने आते हैं हॉर्स ट्रेडिंग के मामले

पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद से ही इसके चुनाव को दलीय प्रणाली से दूर रखा गया था। मंशा यह थी कि गांव के चुनाव में दलीय राजनीति हावी न हो पर ऐसा नहीं हो सका। ग्राम से लेकर जिला पंचायत के चुनाव गैरदलीय आधार पर होते हैं पर सियासी दलों की अप्रत्यक्ष रूप से इनमें पूरी घुसपैठ होती है। सदस्य से लेकर अध्यक्ष बनाने तक में सियासी दलों के नेता पूरी तरह सक्रिय रहते हैं। जिला और जनपद पंचायत के चुनाव में सदस्य सीधे जनता से चुने जाते हैं और इसके बाद वह अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। हर जिला पंचायत और जनपद पंचायत में दस से लेकर पंद्रह वार्ड होते हैं। इनमें जीतने वाले सदस्य जिला पंचायत की तस्वीर तय करते हैं। सीधे चुनाव न होने से अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए जमकर खींचतान होती है और सदस्यों की खरीद फरोख्त के आरोप भी लगते हैं। पिछली बार के चुनाव में भोपाल, दमोह, खंडवा में ऐसे नजारे देखने को मिले थे जहां कम सदस्य संख्या होने के बाद भी चुनाव परिणाम चौंकाने वाले रहे थे। भोपाल में तीन सदस्य होने के बाद भी भाजपा ने अपना समर्थित अध्यक्ष बना लिया था तो दमोह में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। हालांकि वे बाद में भाजपा में शामिल हो गईं थीं।

मप्र भाजपा का कौन होगा अध्यक्ष ?

मप्र में भाजपा अब जल्द ही अपना नया प्रदेश अध्यक्ष चुनने वाली है। बस राज्य के दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने के बाद। बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव हो रहा है, जिसके नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। इसके बाद भाजपा संगठन की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भाजपा अपना नया प्रदेश अध्यक्ष सूबे की जातीय समीकरण को साधते हुए चुनेगी। पार्टी दो फॉर्मूले पर चुनाव करा सकती है। पहला फॉर्मूला है जातिगत समीकरण और दूसरा फॉर्मूला है क्षेत्रीय संतुलन।

जानकारी के अनुसार मप्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का फैसला दिसंबर के पहले सप्ताह में हो जाने की उम्मीद है। 23 नवंबर को दो विधानसभा सीट बुधनी एवं विजयपुर उपचुनाव के नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। इसके अलावा संगठनात्मक चुनाव के तहत बूथ, मंडल एवं जिला अध्यक्ष के चुनाव भी संपन्न हो जाएंगे। इसके बाद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव करवा सकती है। आम सहमति से अध्यक्ष चुनाव हो जाता है तो उसके नाम की घोषणा हो जाएगी। इसके लिए जिन लोगों के नाम चल रहे है उनमें कुछ प्रदेश संगठन में पदाधिकारी, तो कुछ सांसद एवं विधायक है। इसके लिए प्रदेश के दो एसटी सांसदों, दो वैश्य वर्ग से विधायक के अलावा चार सामान्य वर्ग के वरिष्ठ नेताओं एवं दो एससी वर्ग के नेताओं के नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। भाजपा का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा इसकी तस्वीर अभी भले ही साफ नहीं है, लेकिन दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। जिन वरिष्ठ नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल माना जा रहा है, उसमें सामान्य वर्ग से उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, पूर्व मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधायक रामेश्वर शर्मा, सांसद आलोक शर्मा के अलावा सिंधी समाज से वर्तमान प्रदेश कार्यालय प्रभारी महामंत्री एवं विधायक भगवानदास सबनानी एवं बैतूल से विधायक हेमंत खंडेलवाल, एसटी वर्ग से दो बार की सांसद हिमाद्री सिंह एवं राज्यसभा सदस्य डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी का नाम आगे है।

मप्र भाजपा अध्यक्ष के लिए पार्टी क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को विशेष महत्व देगी। ऐसे में अध्यक्ष की रेस में चार ब्राह्मण वर्ग के नेताओं का नाम शामिल है। वर्तमान में प्रदेश सरकार में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल विंध्य क्षेत्र के कद्दावर नेताओं में शामिल हैं। वह पांच बार के विधायक हैं। वह उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जो पहली बार विधायक बनते ही सरकार में मंत्री बनाए गए थे। शुक्ल 2003 से लगातार चुनाव जीत रहे है। प्रदेश सरकार में गृहमंत्री रहे डॉ. नरोत्तम मिश्रा 6 बार के विधायक रहे हैं। पार्टी आलाकमान के साथ अच्छे संबंधों एवं प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं में पकड़ रखने वाले मिश्रा का नाम काफी पहले से इस पद के लिए चर्चा में है। उन्हें पार्टी का संकटमोचक भी कहा जाता है। लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी द्वारा न्यू ज्वाइनिंग टोली की कमान डॉ. मिश्रा के हाथ में थी। प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को भाजपा में शामिल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से तीन बार के विधायक रामेश्वर शर्मा की छवि कट्टर हिंदूवादी नेता की है। हिंदूवादी छवि के चलते संघ की भी पसंद है। इसके साथ ही वह प्रोटेम स्पीकर के पद पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकार्ड भी अपने नाम करवा चुके हैं। वह पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के करीबी भी हैं। राजधानी भोपाल से महापौर रह चुके आलोक शर्मा वर्तमान में राजधानी से सांसद हैं। पार्टी ने उन्हें दो बार उत्तर विधानसभा से टिकट देकर मैदान में उतारा था, लेकिन दोनों बार उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी हैं। शर्मा पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। वहीं सिंधी समाज से आने वाले भगवानदास सबनानी का नाम भी चर्चा में है। सबनानी वर्तमान में पार्टी के प्रदेश कार्यालय महामंत्री के साथ पहली बार के विधायक हैं। सरल, सहज छवि की वजह से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के करीबी हैं। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक हैं। प्रदेश में सदस्यता के मामले में डेढ़ करोड़ सदस्य बनाकर लक्ष्य को पीछे छोड़ने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हाल ही में उनका दिल्ली में सम्मान किया।

वहीं, सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी भी अध्यक्ष की रेस में शामिल हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं। आदिवासी वर्ग से आने वाले डॉ. सोलकी पूर्व में प्रोफेसर थे। उनकी छवि पढ़े-लिखे होने के साथ ही आदिवासी अंचलों में इस वर्ग के लोगों के लिए काम करने को लेकर है। संघ से जुड़े होने के नाते भी उनका नाम इस पद के लिए आगे आया है। शहडोल संसदीय सीट से दूसरी बार सांसद बनी हिमाद्री सिंह का नाम भी चर्चा में है। हिमाद्री की छवि पढ़ी-लिखी महिला के साथ ही आदिवासी वर्ग के लिए काम करने वाली नेता की रही है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में भाजपा ने न केवल विधानसभा चुनाव में 163 सीटें जीतीं बल्कि लोकसभा चुनाव में भी 29 सीटें जीतने में कामयाब रही। ऐसे में उन्हें केंद्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।

● **विकास दुबे**

संगठन चुनाव के चलते टलीं निगम-मंडलों में नियुक्तियां

प्रदेश में मोहन सरकार 11 महीने का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। इस बीच भाजपा संगठन की ओर से निगम, मंडलों में खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने की कवायद की गई, लेकिन एक भी नेता को एडजस्ट नहीं किया गया है। अब भाजपा संगठन चुनाव की वजह से निगम मंडलों में नियुक्तियां अगले साल फरवरी तक टल गई हैं। यानी भाजपा के वे नेता जो निगम, मंडल एवं अन्य संस्थाओं में कुर्सी के इंतजार में बैठे हैं उन्हें और इंतजार करना पड़ सकता है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि जो नेता भाजपा की पिछली सरकारों में मंत्री पद का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें अब फिर से नियुक्तियां नहीं मिलेंगी। हालांकि कुछ नेता इसमें सफल भी हो सकते हैं। मौजूदा स्थिति में भाजपा के संघ से जुड़े नेता ही सरकार में नियुक्ति के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। जिन्हें फिलहाल सफलता मिलने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। इतना तय है कि जनवरी तक भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा।

निगम-मंडलों में नियुक्ति नए साल में

पिछले 11 माह से निगम-मंडलों में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष बनने की आस लगाए भाजपा नेताओं को अभी करीब 4 माह तक इंतजार करना पड़ सकता है। इसकी वजह है भाजपा संगठन का चुनाव। पार्टी सूत्रों के अनुसार, संगठन चुनाव को देखते हुए निगम-मंडलों में नियुक्तियां टाल दी गई हैं। मप्र में भाजपा संगठन चुनाव की डेडलाइन के अनुसार 15 दिसंबर तक 1078 मंडलों के अध्यक्ष घोषित होंगे। 15 जनवरी 2025 तक जिलाध्यक्षों का चुनाव हो जाएगा। जनवरी अंत तक सभी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव हो जाएगा। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि फरवरी 2025 में ही अब निगम-मंडलों में राजनीतिक नियुक्ति हो पाएगी।

गौरतलब है कि प्रदेश में मोहन सरकार 11 महीने का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। इस बीच भाजपा संगठन की ओर से निगम, मंडलों में खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने की कवायद की गई, लेकिन कुछ ही नियुक्तियां हो पाईं। अब भाजपा संगठन चुनाव की वजह से निगम-मंडलों में नियुक्तियां अगले साल फरवरी तक टल गई हैं। यानी भाजपा के वे नेता जो निगम, मंडल एवं अन्य संस्थाओं में कुर्सी के इंतजार में बैठे हैं उन्हें और इंतजार करना पड़ सकता है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि जो नेता भाजपा की पिछली सरकारों में मंत्री पद का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें अब फिर से नियुक्तियां नहीं मिलेंगी। हालांकि कुछ नेता इसमें सफल भी हो सकते हैं। मौजूदा स्थिति में भाजपा के संघ से जुड़े नेता ही सरकार में नियुक्ति के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। जिन्हें फिलहाल सफलता मिलने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। इतना तय है कि जनवरी तक भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। इसके बाद ही नेताओं को सरकार में एडजस्ट किया जाएगा।

भाजपा में निगम मंडलों के लिए कई नेता दावेदार हैं। 2020 में जिन सीटों पर कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल हुए थे, उन सीटों पर भाजपा के पूर्व विधायक भी निगम मंडलों के लिए दावेदारी कर रहे हैं। साथ ही पिछले विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव के दौरान भी दूसरे दलों से जो नेता भाजपा में आए थे, वे भी निगम मंडलों में नियुक्ति चाहते हैं। भाजपा संगठन के पास सरकार में नियुक्ति पाने के दावेदार नेताओं की सूची लंबी है। पिछली बार ही तरह इस बार भी संघ की ओर से भी कुछ नेताओं के नाम सामने आएंगे। हालांकि संघ खुले तौर पर किसी भी नेता का समर्थन या विरोध नहीं करता है। लेकिन संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों की सिफारिश जरूर होती है। सत्ता और संगठन अब तक जिन नामों को तय कर चुके हैं, उनमें पांच संघ व संगठन के बताए जा रहे हैं तो तीन कांग्रेस से आए चेहरे हैं। एक सिंधिया समर्थक नेता की भी लॉटरी पहली सूची में ही खुल सकती है। इस सूची में प्रदेश भाजपा के पूर्व कोषाध्यक्ष बैतूल से दो बार के विधायक व पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल का नाम तय माना जा रहा है, तो पूर्व उपाध्यक्ष विनोद गोटिया भी इस सूची में शामिल बताए जा रहे हैं। संघ से जुड़े पूर्व संभागीय संगठन मंत्री को शैलेंद्र बरुआ और आशुतोष तिवारी को फिर से निगम-मंडल की कुर्सी मिल सकती है। संगठन से हटाने के बाद दोनों को सरकार ने मंत्री पद का दर्जा देते हुए निगम-मंडल में बैठाया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने फरवरी में इनकी नियुक्ति भी निरस्त कर दी। निगम मंडल के भरोसे जिन भाजपा नेताओं की नाराजगी दूर की गई है, उनमें बुधनी उपचुनाव के प्रबल दावेदार पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत ताजा नाम है। 2005 में मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान के लिए राजपूत ने ही अपनी विधायकी छोड़ी थी। अभी भी टिकट मांग रहे थे। वहीं विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान करीब आधा दर्जन नेताओं के टिकट काटते समय भी पार्टी ने निगम-मंडल में पद देने का वादा किया था। इनमें प्रदेश मीडिया प्रभारी रहे डॉ. हितेश वाजपेयी व लोकेंद्र पाराशर के अलावा दमदार प्रवक्ता पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के नाम भी प्रमुख हैं।

संगठन पूर्व पूरा होते ही नया क्राइटेरिया बनाकर सदस्यता में अच्छा काम करने वालों को भी मौका मिलना है। पिछले चुनावों के दौरान दूसरे दलों से बड़ी संख्या में नेता भाजपा में शामिल हुए थे। ऐसे नेताओं को निगम मंडलों में पद देकर उपकृत किया जा सकता है। संगठन स्तर पर इसकी सूची भी तैयार हो चुकी है। कुछ नामों को लेकर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। फिलहाल सरकार की नियुक्तियों को लेकर संगठन में चर्चा एवं बैठकों का दौर खत्म हो चुका है। नए अध्यक्ष के चुनाव बाद इस पर निर्णय होगा। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर भाजपा को मजबूती देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कट्टर समर्थक रहे पूर्व विधायक दीपक सक्सेना प्रमुख हैं। चार बार के विधायक सक्सेना द्वारा छोड़ी गई सीट से ही उपचुनाव जीतकर कमलनाथ पहली बार विधायक बने थे। पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी का नाम भी तय माना जा रहा है। इन दोनों के अलावा ग्वालियर से सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल को जगह मिलने की पूरी उम्मीद है। इनका 2023 में टिकट काटा गया था।

● **लोकेश शर्मा**

सुरेश पचौरी राज्यपाल के लिए लगा रहे जोर

लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर समर्थकों को साथ लेकर भाजपा में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी राज्यपाल के लिए जोर लगा रहे हैं। पचौरी लगातार दिल्ली में सक्रिय हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। भाजपा सूत्रों ने बताया कि सुरेश पचौरी को राज्यपाल बनाने पर केंद्रीय नेतृत्व सहमत नहीं है। विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान दलबदल करने वाले कांग्रेसी दिग्गजों के साथ ही अपने नाराज नेताओं को मनाने के लिए भी भाजपा ने निगम-मंडल व प्राधिकरणों के पदों का भरोसा दिलाया था। यही वजह थी कि अपनी पार्टी की सरकार आने के बाद भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछली सरकार द्वारा बनाए गए 46 निगम-मंडलों के अध्यक्ष व उपाध्यक्षों की नियुक्ति निरस्त कर दी थी। ये सब भी अब तक आस लगाए बैठे हैं कि उन्हें सरकार सम्मान वापस करेगी। सूत्रों की मानें तो इनमें से कुछ को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी दोबारा पद व रुतबा देने का मन बना लिया है। निगम-मंडलों के लिए बनाई गई छोटी सूची में करीब एक दर्जन चेहरे लगभग तय कर लिए गए हैं। इस सूची में संघ और संगठन का तालमेल बनाया गया है तो कांग्रेस से आकर भाजपा को लोकसभा में वलीन स्वीप का मौका देने वाले पूर्व कांग्रेसी भी शामिल हैं।

युवा निकालेंगे कांग्रेस को मझधार से

मप्र में पिछले दो दशक से राजनीति के मझधार में फंसी कांग्रेस को अब युवा नेता निकालेंगे। इसके लिए आलाकमान ने युवा नेताओं को प्रदेश संगठन में उपाध्यक्ष, महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही अब इन युवा नेताओं को संभाग और जिलों का प्रभार देकर उन्हें सक्रिय किया जाएगा। ये नेता कांग्रेस संगठन को मजबूत करेंगे। युवा नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष व महासचिव इसलिए बनाया गया है, ताकि वे भागदौड़ और परिश्रम कर पूरे प्रदेश में संगठन को जिलों का प्रभार सौपेंगी। इसके अलावा कुछ पदाधिकारियों को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में काम सौंपा जाएगा और कुछ को फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का प्रभार दिया जाएगा। वहीं पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं को भी संगठन में जिम्मेदारी दी है, ताकि वे युवाओं को सहयोग कर सकें।

गौरतलब है कि जीतू पटवारी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के करीब 10 महीने बाद अब उनकी टीम बनकर तैयार हो गई। प्रदेश कार्यकारिणी में युवा और वरिष्ठ नेताओं के बीच संतुलन बैठाने की कोशिश की गई है। पार्टी ने युवा नेताओं को जहां प्रदेश उपाध्यक्ष और महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी है, वहीं 55 साल से अधिक उम्र के नेताओं और दिग्गजों को कार्यकारिणी सदस्य, स्थाई आमंत्रित सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य बनाकर उनका मान-सम्मान बरकरार रखने की कोशिश की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष और महासचिवों की औसत उम्र 40 से 55 साल है। पार्टी को आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में सगठन का विस्तार करना है। जिलों से लेकर गांवों तक जनता के बीच पार्टी की पैठ बनानी है।

संगठन के गठन के बाद पीसीसी चीफ पटवारी पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर जल्द ही इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने अभी प्रदेश सचिव, अनुशासन समिति और राजनीतिक मामलों की सलाहकार समिति की घोषणा नहीं की है। जीतू पटवारी ने कहा, जल्द ही इनकी घोषणा की जाएगी। इनमें वर्तमान सूची में शेष रहे कई साथियों को भी जिम्मदारी मिलेगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी बनाने के बाद अब विभागों के अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। पार्टी ने अन्य पिछड़ा वर्ग और आदिवासी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों को महासचिव बना दिया है। इनके स्थान पर नई नियुक्तियां बुधनी और विजयपुर, विधानसभा के उपचुनाव के बाद होंगी। वहीं, जिला इकाइयों में भी परिवर्तन प्रस्तावित हैं। जिन नेताओं को कार्यकारिणी में स्थान नहीं मिल पाया है, उन्हें सचिव, सह-सचिव बनाकर संगठन में समायोजित किया जाएगा। वरिष्ठ नेताओं की भूमिका अब मार्गदर्शक की रहेगी। वैसे तो इसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के समर्थकों को स्थान देकर संतुलन बनाने का प्रयास किया है। पिछड़ा वर्ग विभाग के अध्यक्ष सिद्धार्थ कुशवाहा को उपाध्यक्ष तो आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष रामू टेकाम और किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर को महासचिव बनाया है। इन तीनों के स्थान पर नई नियुक्ति की जाएगी। सिद्धार्थ कुशवाहा और दिनेश गुर्जर विधायक हैं। वहीं, रामू टेकाम को दूसरी बार बैतूल संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ाया गया था पर वे हार गए।

प्रदेश संगठन के गठन के बाद अब पटवारी का फोकस संगठन की मजबूती पर रहेगा। संगठन की सक्रियता भी कम है, जबकि पार्टी का फोकस आदिवासियों पर रहता है। पार्टी करीब 50 ब्लॉक अध्यक्षों को 10 माह में हटा चुकी है। अब कुछ जिला अध्यक्षों को भी बदलने की तैयारी है। दरअसल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पहले ही कह चुके हैं कि जो पदाधिकारी संगठन के कामकाज के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं या निष्क्रिय हैं, उनके स्थान पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जाएगा। पार्टी के मंथन में इसे लेकर सहमति भी बन चुकी है। इनमें वे अध्यक्ष भी शामिल होंगे, जिन्हें तीन वर्ष से अधिक समय पदस्थ रहते हो चुके हैं। साथ ही उन जिलों में भी नई नियुक्ति की जाएगी, जहां समन्वय बनाने को लेकर समस्या आ रही है।

उधर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सबको साथ लेकर चलने के साथ अंचल और जातिगत संतुलन बनाने का प्रयास किया है। पार्टी में काम करने वाले कई वरिष्ठ और युवा नेता हैं। सबकी उपयोगिता है और जो रह गए हैं, उन्हें आगे समायोजित करेंगे। पार्टी ने सभी वरिष्ठ नेताओं को जीतू पटवारी की टीम में शामिल तो किया है पर इनकी भूमिका मार्गदर्शक की होगी। इन्हें प्रदेश स्तरीय हर बैठक में बुलाया जाएगा और अनुभव का लाभ लिया जाएगा। ऐसे नेताओं में डॉ. गोविंद सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, रामेश्वर नीखरा, राजा पटेरिया, नरेंद्र नाहटा, चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी, कैलाश कुंडल, मुजीब कुरैशी, रामसेवक गुर्जर, साजिद अली सहित अन्य शामिल हैं।

● **प्रवीण सक्सेना**

जिलों में आयोजित होंगे प्रशिक्षण शिविर

प्रदेश संगठन की मजबूरी के लिए कांग्रेस कुछ जिलों में तीन दिन तो कुछ में एक दिन के प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने जा रही है। इसमें बूथ, सेक्टर, मंडलम और जिलास्तर के कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसमें बताया जाएगा कि भाजपा सरकार की नीतियों, विकास के वादों के बीच कांग्रेस को कौन से मुद्दे उठाने चाहिए, कहां पर उठाने चाहिए, इसके लिए जनता को अपने भरोसे में कैसे लें, संगठन को कैसे मजबूत बनाएं। प्रशिक्षण आयोजित करने की जिम्मेदारी सेवादल को दी गई है। इसमें जिला, प्रदेश व कुछ जगह राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी प्रशिक्षण देंगे। दिसंबर में महासम्मेलन होगा। सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष योगेश यादव ने बताया कि कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और संगठन की मजबूती के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाने का निर्णय लिया गया है। दीपावली के बाद यह प्रारंभ हो जाएंगे। नीमच, राघौगढ़, रीवा सहित अन्य जगहों पर ये आयोजन तीन-तीन दिन के होंगे। जबकि, अन्य जिलों में एक-एक दिन के शिविर रखे जाएंगे। इनमें बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति-नीति के साथ भावी योजना के बारे में बताने के साथ भाजपा द्वारा लगाए जाने वाले आरोपों का उत्तर देने के तरीके, संगठन को मजबूत करने समन्वय बनाने और बूथ प्रबंधन के बारे में बताएंगे।

मप्र की दो विधानसभा सीटों- विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव के लिए मतदान समाप्त होने के बाद अब सबकी नजर 23 नवंबर पर है, जिस दिन मतगणना होगी। बुधनी सीट पर 77.32 प्रतिशत और विजयपुर में 77.85 प्रतिशत मतदान हुआ है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां अपनी-अपनी जीत के दावे कर रही हैं। अब देखना है, बाजी किसके हाथ लगेगी।

किसके हाथ लगेगी बाजी?

विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अपने रणनीति कौशल का लोहा मनवा चुके मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को हुए उपुचनाव में भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए भी मोर्चा संभाला। वैसे तो रणनीति तौर पर भाजपा दोनों सीटों पर मजबूत स्थिति में है, लेकिन पार्टी को भितरघात और बगावती तेवरों का सामना करना पड़ा। इसलिए ये चुनाव उपरोक्त तीनों नेताओं के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं हैं। हालांकि कांग्रेस को भी भितरघात और बगावत का सामना करना पड़ा। बुधनी से भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव का जहां पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे तो कांग्रेस के बागी और समाजवादी पार्टी से नामांकन भरने वाले अर्जुन आर्य कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार राजकुमार पटेल के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है।

गौरतलब है कि मप्र में नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने। लेकिन, भाजपा की ओर से इस बार उन्हें मुख्यमंत्री पद नहीं सौंपा गया। ऐसे में उनके केंद्र में जाने की चर्चा शुरू हुई। साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से टिकट दिया गया और वे रिकॉर्ड जीत दर्ज कर सांसद चुने गए। इसके बाद केंद्र की मोदी सरकार में उन्हें पंचायत एवं ग्रामीण विकास व कृषि मंत्री बनाया गया। सांसद बनने के कारण शिवराज को विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ा, इससे एक बार फिर बुधनी सीट पर उपचुनाव की स्थिति बनी। इस उपचुनाव में भाजपा ने रमाकांत भार्गव पर भरोसा जताया है।

बुधनी में अब तक हुए दो उपचुनाव में भाजपा ने अजेय बढ़त बनाए रखी है, जबकि कांग्रेस तीसरे उपचुनाव में जीत की उम्मीद कर रही है। बुधनी विधानसभा में दोनों उपचुनाव भाजपा शासनकाल में हुए थे। तीसरा उपचुनाव के दौरान भी प्रदेश में भाजपा की ही सरकार है। अगर, भाजपा इस बार भी जीतती है तो वह 3-0 की अजेय बढ़त बना लेगी। वहीं, अगर कांग्रेस जीतती है तो मुकाबला 2-1 हो जाएगा। बता दें कि इस बार उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी दस्तक दी। अभी तक मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होता आया है। लेकिन, इस बार समाजवादी पार्टी से कांग्रेस के बागी नेता अर्जुन आर्य ने अपना नामांकन दाखिल किया है। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है।

मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस बुधनी विधानसभा सीट का लगभग 20 साल तक नेतृत्व किया है, उस पर हो रहे उपचुनाव में इस बार मुकाबला दो पुराने दिग्गज नेताओं के बीच है। बुधनी विधानसभा सीट से भाजपा ने विदिशा के पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को चुनावी मैदान में उतारा है तो कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता राजकुमार पटेल को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की ओर किरार समाज से आने वाले पूर्व विधायक राजकुमार पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है, बुधनी में किरार समाज के वोटरों की संख्या 50 हजार से अधिक है। राजकुमार पटेल 1993 में बुधनी से विधायक रहे चुके हैं और उनकी किरार समाज में गहरी पैठ मानी जाती है। वहीं पिछले 20 साल से बुधनी सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे शिवराज सिंह चौहान भी किरार समाज से ही आते हैं। वहीं भाजपा ने विदिशा के पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को उम्मीदवार बनाया है। शिवराज सिंह चौहान के विदिशा से लोकसभा चुनाव में उतरने से भाजपा ने रमाकांत भार्गव का टिकट काट दिया था, ऐसे में रमाकांत भार्गव को बुधनी से टिकट मिलना शिवराज सिंह चौहान की पंसद बताया जा रहा है और बुधनी में अब फिर शिवराज सिंह चौहान

भाजपा का मुद्दा विकास

मप्र की दोनों सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग हुई। भाजपा ने दोनों सीटों पर विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा तो कांग्रेस के मुद्दे अलग हैं। कांग्रेस विजयपुर में कुपोषण, गरीबी और क्षेत्र के पिछड़ेपन को मुद्दा बना रही है। बुधनी में कांग्रेस को यह उम्मीद है कि लोग शिवराज सिंह चौहान को बतौर मुख्यमंत्री वोट देते रहे हैं। इस बार शिवराज न तो मुख्यमंत्री हैं और न ही बुधनी से उम्मीदवार, ऐसे में मुकाबला आसान है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि जमीन अब कांग्रेस की है। बुधनी विधानसभा सीट से 6 बार शिवराज सिंह चौहान विधायक रहे। 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 2006 में उपचुनाव लड़ा और जीते। इसके बाद 2008, 2013, 2018 और 2023 में जीत दर्ज की। 18 साल बाद हो रहे चुनाव में शिवराज बुधनी से उम्मीदवार नहीं हैं। भाजपा ने बुधनी सीट से पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर पार्टी भाजपा सरकार और शिवराज सिंह चौहान द्वारा कराए गए विकास कार्यों के नाम पर वोट मांग रही है। यहां कांग्रेस ने पूर्व विधायक राजकुमार पटेल को प्रत्याशी बनाया है। 1993 में राजकुमार बुधनी से विधायक चुने गए थे। 1998 में उनके बड़े भाई देवकुमार पटेल भी इसी सीट से विधायक रहे। कांग्रेस यह मानकर चल रही है कि पटेल परिवार की बुधनी में पकड़ है।

की ही प्रतिष्ठा दांव पर है।

श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर हुआ उपचुनाव एक हाईप्रोफाइल मुकाबला है। भाजपा ने विजयपुर विधानसभा सीट से कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे। वहीं कांग्रेस ने भाजपा से कांग्रेस में आए सहारिया जाति के बड़े नेता मुकेश मल्होत्रा को मैदान में उतारा है। 2023 विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर भाजपा से बगावत करने वाले मुकेश मल्होत्रा निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे और 44 हजार वोट हासिल कर तीसरे नंबर थे। ऐसे में अब जब भाजपा ने कांग्रेस से पार्टी में आए रामनिवास रावत को और कांग्रेस ने भाजपा से आए मुकेश मल्होत्रा को चुनावी मैदान में उतारा तो पूरी सियासी लड़ाई कांटे की हो गई। मुकेश मल्होत्रा जिस सहरिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे हैं उसकी आबादी 70 हजार है और सहारिया जाति के वोटर्स का रूख जीत-हार तय करता है। हालांकि भाजपा ने अपने पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी को सहरिया विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। विजयपुर में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों का विरोध उनकी ही पार्टी के मूल कार्यकर्ता कर रहे हैं। रामनिवास रावत लंबे समय तक कांग्रेस के दिग्गज चेहरे रहे और अब उनके भाजपा में आने से, भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं ने खुद को उपेक्षित महसूस किया और चुनाव में बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई। चुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने लिए भाजपा रामनिवास रावत के नामांकन के जरिए एकजुटता का शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। विजयपुर में भाजपा की असली चुनौती पार्टी को एकजुट करना था।

प्रदेश में 13 नवंबर को श्योपुर जिले की विजयपुर और सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा सीटों के उपचुनावों में मतदान हुआ। भाजपा-कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का चयन करते समय जातीय समीकरणों पर विशेष ध्यान दिया है। भाजपा ने कांग्रेस से पार्टी आए छह बार के विधायक रामनिवास रावत को मैदान में उतारा है। वहीं, कांग्रेस ने इस सीट पर आदिवासी नेता मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया है। इस सीट पर आदिवासी वोटर निर्णायक हो सकते हैं। कांग्रेस ने इसी वजह से एक आदिवासी नेता पर भरोसा जताया है। विजयपुर विधानसभा सीट के लिए दोनों ही प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों के लिए दोनों पार्टियों ने खूब प्रचार किया। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए रामनिवास रावत अब प्रदेश सरकार में वन मंत्री हैं। उनके भाजपा में आने का फायदा पार्टी को लोकसभा चुनावों में मिला भी था। ऐसे में अब कांग्रेस ने आदिवासी नेता के तौर पर मल्होत्रा को टिकट देकर भाजपा के सामने एक चुनौती पेश की है। भाजपा इस सीट को अपने पास रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खुद ही चुनाव प्रचार की बागड़ोर अपने हाथ में ली। वह खुद विजयपुर गए और रावत का नामांकन भरवाया। विजयपुर विधानसभा में 2 लाख 55 हजार मतदाता हैं। इनमें से करीब 65 हजार यानी 20 प्रतिशत से अधिक मतदाता आदिवासी समुदाय से आते हैं। जाटव मतदाता भी 40 हजार के करीब हैं। कुशवाह और धाकड़ समाज से 25-25 हजार वोटर हैं। इन चार समाजों के करीब डेढ़ लाख मतदाता ही किसी भी उम्मीदवार की जीत-हार तय करते हैं। विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का परिणाम प्रमुख रूप से आदिवासी, जाटव, कुशवाह और धाकड़ समाज के वोटरों पर ही तय होगा।

ग्वालियर अंचल के विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में कांग्रेस ने प्रदेश के सभी नेताओं को विजयपुर के चुनावी रण में उतार दिया था। दूसरी तरफ कांग्रेस से यह सीट छीनने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ मोर्चा संभाला। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी उपयोग विजयपुर में करने के संकेत स्टार प्रचारकों की सूची से दिए। कांग्रेसियों का मानना है कि आदिवासियों ने सदैव कांग्रेस को संबल प्रदान किया है। विजयपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रामनिवास रावत व कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा नामांकन दाखिल करते समय अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर चुके हैं। दोनों ही उम्मीदवार अपने मूल राजनीतिक दल को छोड़कर चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक रावत विजयपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से चुनाव लड़ते रहे हैं, पहली बार भाजपा से चुनाव मैदान हैं। उनके प्रतिद्वंद्वी मल्होत्रा का भी यह दूसरा चुनाव है। पहला चुनाव भाजपा से विद्रोह कर निर्दलीय लड़ चुके हैं। इस बार कांग्रेस के टिकट पर भाजपा को चुनौती देने के लिए मैदान में उतरे हैं।

● **कुमार विनोद**

पटवारी के लिए अग्निपरीक्षा

मप्र में लगातार चुनाव हार रही कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष पद पर युवा चेहरे पर दांव लगाया लेकिन कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। जीतू पटवारी को अध्यक्ष बने लगभग 1 साल पूरा होने जा रहा है इस दौरान लोकसभा के बाद छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अपने 15 वर्ष के राजनीतिक सफर में जीतू पटवारी फर्श से अर्श पर पहुंचे हैं, लेकिन हार की हैट्रिक पटवारी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। जीतू पटवारी बुधनी और विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंककर हार को जीत में बदलने की कोशिश करने में लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पटवारी के लिए यह किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है। अगर वे दोनों सीटें हारे तो अध्यक्ष की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। मप्र में कांग्रेस पार्टी पहले विधानसभा 2023 में सत्ता से बाहर हुई। 2024 लोकसभा चुनाव में मप्र की 29 की 29 लोकसभा सीट गंवा बैठी। इसके बाद अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की सीट गंवा बैठी। अब एक बार फिर से कांग्रेस जीतू पटवारी को आजमा रही है। 13 नवंबर को बुधनी और विजयपुर विधानसभा उपचुनाव हो चुका है। 23 नवंबर को इसके परिणाम आएंगे। यहां भी हार का सिलसिला कायम रहा तो पटवारी की कुर्सी खतरे में आनी तय है। मप्र कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष महज 47 वर्ष के जीतू पटवारी को अध्यक्ष की कुर्सी मिलने का मुख्य कारण राहुल गांधी का करीबी और ओबीसी वर्ग से होना माना जाता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का उन्हें क्षेत्र में प्रभारी बनाया गया था।

रेडीमेड गारमेंट का हब बनेगा इंदौर

मिनी मुंबई के रूप में ख्यात इंदौर और उसके आसपास तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा है। दरअसल, इन दिनों मप्र में औद्योगिक विकास की नई लहर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में औद्योगिक विकास की जो पहल की है उसके परिणाम स्वरूप मप्र में निवेश करने के लिए औद्योगिक घरानों में होड़ लग गई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि इंदौर में गारमेंट उद्योग लगाने के लिए कई कंपनियों ने इच्छा जाहिर की है। इसको देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि इंदौर आने वाले समय में रेडीमेड गारमेंट का हब बन सकता है।

औद्योगिक विकास को साझा जिम्मेदारी मान रही मोहन यादव सरकार प्रदेश में नए निवेश के लिए अवसर पैदा करने के साथ नई यूनिट्स के शिलान्यास पर फोकस कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कह चुके हैं कि ऐसे कामों में न केवल सरकार की भूमिका है, बल्कि स्थानीय व्यवसायों, समाज और शिक्षा संस्थानों का भी सक्रिय रूप से शामिल होना आवश्यक है। यह समावेशी विकास की दिशा में एक ठोस कदम है, जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का प्रयास करता है। इसी के चलते प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मोहन सरकार ने औद्योगिक इकाइयों का भूमिपूजन किया है। सरकार ने इंडस्ट्रीयल कॉन्क्लेव के जरिए औद्योगिक इकाइयों के भूमिपूजन और लोकार्पण का सिलसिला उज्जैन से शुरू किया है, जो जबलपुर, ग्वालियर, सागर के बाद रीवा में हुई कॉन्क्लेव तक जारी रहा है। अब शहडोल, नर्मदापुरम और नीमच में इंडस्ट्रीयल कॉन्क्लेव की तैयारी में सरकार जुट गई है।

कपड़ा मिलों की पहचान रहा इंदौर अब रेडीमेड गारमेंट का हब बनने जा रहा है। इंदौर से 110 किमी दूर बदनावर के पास पीएम मित्र (प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल) पार्क प्रोजेक्ट में गुजरात और कोलकाता की दो कंपनियों ने 2500 करोड़ रुपए का निवेश करने में रुचि दिखाई है। इनमें से एक गुजरात की अरविंद मिल कंपनी है, जो कि वस्त्र निर्माण की इकाई लगाने की तैयारी में है। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने जमीन का निरीक्षण भी किया है, वहीं कोलकाता की एक अन्य कंपनी भी यहां होजयरी के कई बड़े ब्रांड के लिए होजयरी वस्त्रों के निर्माण का प्लांट भी लगाएगी। इसके साथ ही यहां पर प्रदेश सहित देशभर से कई छोटी-बड़ी 22 कंपनियां भी आने की तैयारी में हैं। इसका फायदा रोजगार के सृजन से होगा। पीएम मित्र पार्क का काम इसी वर्ष जनवरी में शुरू हुआ है, जिसे आगामी ढाई वर्ष में पूरा किया जाना है। करीब दो हजार एकड़ में बन रहे इस पार्क की लागत लगभग 1600 करोड़ रुपए है। एमपीआईडीसी के कार्यकारी निदेशक राजेश राठौर ने बताया कि पीएम मित्र पार्क का काम तेजी से चल रहा है। एप्रोच रोड, वाटर लाइन आदि का काम किया जा रहा है। पिछले कुछ समय में तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और मप्र की 22 से अधिक छोटी-बड़ी कंपनियों ने पीएम मित्र पार्क का विजिट किया और निवेश में रूचि दिखाई है। इसमें से कुछ कंपनियों के साथ बातचीत अंतिम दौर में है। आने वाले समय टेक्सटाइल से जुड़ी अन्य बड़ी कंपनियां भी विजिट करने आने वाली हैं। अभी तक 22 से अधिक कंपनियों ने पीएम मित्र का विजिट किया है। इन कंपनियों द्वारा यहां 9462 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने की संभावना है, जिससे 25 हजार से अधिक लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा।

गुजरात की ख्यात कपड़ा कंपनी अरविंद मिल्स जल्द ही इंदौर में बड़ा निवेश करने जा रही है। एमपीआईडीसी (मप्र इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन) के साथ कंपनी की बातचीत फाइनल हो चुकी है। कंपनी बदनावर के पास भैंसोला में बन रहे पीएम मित्र पार्क में बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करेगी, वहीं इंदौर के पास रेडीमेड गारमेंट यूनिट भी डालेगी। इस तरह कुल 1500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। राजस्थान की भी कुछ कंपनियां जो झालावाड़ बेस्ड हैं, वे मंदसौर, नीमच क्षेत्र में निवेश करने जा रही हैं।

एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक राजेश राठौर ने बताया कि अरविंद मिल्स से प्रारंभिक चर्चा हो चुकी है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उद्योग विभाग की टीम के साथ बेंगलुरू और कोयम्बटूर सहित अन्य शहरों में निवेशकों से मिले थे। दक्षिण भारत की कई इंडस्ट्रीज ने यहां आने की संभावनाएं जताई है। राठौर ने बताया कि 44 करोड़ की लागत से देवी अहिल्या गारमेंट सिटी का निर्माण होगा। इससे 30 हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा। मप्र में निवेश के लिए कई बड़ी कंपनियों ने रूचि दिखाई है। जानकारी के अनुसार गुजरात की अरविंद मिल्स 1500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। वहीं बेस्ट कार्पोरेशन 620 करोड़ रुपए, आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड भीलवाड़ा 850 करोड़ रुपए, ओस्वाल ग्रुप भीलवाड़ा 650 करोड़ रुपए, निहार स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड 580 करोड़ रुपए, पाशा पोलिटेक्स प्रालि 827 करोड़ रुपए, निहार इंडस्ट्रीयल इंटरप्राइजेस लिमिटेड, लुधियाना 550 करोड़ रुपए केयरफिट इंडस्ट्रीयल प्रालि 600 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही हैं।

● **विकास दुबे**

पीथमपुर में बनेंगे वंदे भारत स्लीपर कोच और इलेक्ट्रिक बसें

पीथमपुर में पिनेकल मोबिलिटी कंपनी 600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। शुरुआत में 500 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जैसे ही पूरी क्षमता के साथ वर्किंग शुरू होगी, 500 लोगों को और रोजगार मिलेगा। यानी एक हजार लोगों को कंपनी रोजगार देगी। 48 एकड़ में बनने वाले इस प्लांट का 23 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वर्चुअली शुभारंभ कर चुके हैं। जिसमें इलेक्ट्रिक बसों और ट्रकों का निर्माण होगा। यह प्लांट 2 साल में तैयार होगा। जिसके बाद इसमें इंडस्ट्रीयल ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। खास यह है कि पिनेकल इस प्लांट के साथ ही एक अन्य प्लांट भी सेक्टर-7 में बना रही है, जहां पर वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर कोच को तैयार किया जाएगा। बता दें, पिनेकल कंपनी के इन दो नए प्लांट्स के अलावा पीथमपुर में पहले से ही तीन प्लांट वर्किंग में हैं।

मर्जी से मरना चाहते हैं 23 आदिवासी परिवार

उन्नति होगी, इच्छामृत्यु की मांग गलत

सतपुड़ा लैंड सर्च के संस्थापक अनिल गर्ग का कहना है कि आदिवासियों को जमीन कढ़ाई में दी गई थी। सरकार ने तालाब कुंआ खुदवाया। सुप्रीम कोर्ट के इसमें दो आदेश हैं, जो जमीन धारा 237 (1) में आरक्षित है। चराई आदि के लिए वह प्राइवेट सेक्टर के उपयोग के लिए नहीं दी जा सकती। वुडन क्लस्टर प्राइवेट सेक्टर है, इसलिए उनको नहीं दे सकते। फॉरेस्ट राइट एक्ट का दावा अगर निरस्त हो गया है तो उसे बेदखल नहीं किया जा सकता। उस समय इस योजना पर सरकारी पैसा खर्च हुआ है। ग्रामसभा के प्रस्ताव हैं। फाइल आदिवासी थोड़े ढूंढेगा। ये जिम्मेदारी तो प्रशासन की है। बैतूल कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि वुडन कलस्टर बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इससे लोगों की उन्नति होगी। यहां का सागौन विश्वस्तर पर जाना पहचाना जाएगा। भूमि आवंटन काफी सोच समझकर किया जाता है। पूरी जांच पड़ताल के बाद किया जाता है। वहां दो-तीन अतिक्रमण हैं, यह किसी भी शासकीय रिकॉर्ड में नहीं हैं।

बैतूल में 23 आदिवासी परिवारों को 21 साल पहले मिली खुशी अब गम में बदलने वाली है। हरियाली-खुशहाली योजना के तहत आदिवासियों को पेड़-पौधे और खेती करने दी गई जमीन उद्योग विभाग को वुडन क्लस्टर के लिए दी जा रही है। अगर ऐसा होता है तो आदिवासियों के सामने भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। 6 किसानों को हटाने के लिए नोटिस दिया गया है। कढ़ाई गांव के आदिवासियों ने राष्ट्रपति को पत्र भेजकर इच्छामृत्यु की अनुमति मांगी है। आदिवासियों के 21 साल पहले जमीन दिए जाने के दावों और प्रशासन द्वारा इसे अतिक्रमण मानने पर पड़ताल की तो हकीकत सामने आई। सवाल उठ रहे हैं कि बैतूल से 5 किलोमीटर दूर कढ़ाई गांव में 12 आदिवासियों का क्या है दर्द और वे इच्छामृत्यु क्यों मांग रहे हैं।

आदिवासियों के मुताबिक उन्हें साल 2003 में हरियाली खुशहाली योजना के तहत 110 एकड़ जमीन दी गई थी। इसके लिए ग्रामसभा में प्रस्ताव भी पारित किया गया था। यहां 40 से 50 लाख रुपए खर्च कर कूप खनन किया गया, फलदार वृक्ष रोपने के साथ कृषि उपकरण खरीदे गए। आदिवासी यहां पर 21 साल से खेती कर रहे हैं। आदिवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे और वुडन क्लस्टर को उनकी जमीन देने का विरोध करते हुए कलेक्टर कोर्ट के नाम आवेदन सौंपा। राष्ट्रपति के नाम इच्छामृत्यु का आवेदन भी कलेक्टर को दिया है। आदिवासी सुखचंद की तरफ से कलेक्टर कोर्ट में एक अपील आवेदन भी दिया गया है। इसमें जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक रोहित डावर, जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष ब्रिज आशीष पांडे और सचिव पीयूष तिवारी को गैर अपीलार्थी बनाया गया है। जिसमें कलेक्टर समेत, राज्य शासन को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। वुडन क्लस्टर के लिए ली गई कई अनापत्तियों को फर्जी बताया गया है, जबकि भूमि के आवंटन के लिए बड़ा षड्यंत्र तक करने का आरोप लगाया गया है।

मप्र सरकार ने 2003 में 23 आदिवासी परिवारों को भूमिहीन मानते हुए हरियाली से खुशहाली योजना में दो-दो हेक्टेयर जमीन दी थी। चरनोई मद की इन जमीनों पर उन्हें फलदार पौधे लगाने, खेती करने के लिए कहा गया था। ग्रामीणों के मुताबिक उस समय पंचायत ने नक्शा बनाया था। उसी आधार पर उन्हें जमीन चिन्हित कर बांट दी गई थी, जिसका रिकॉर्ड पंचायत के पास है। कढ़ाई गांव के पास छोटे बांध को पोकलेन मशीन के जरिए मिट्टी डालकर बंद करने का काम चल रहा है। ग्रामीण इस प्रोजेक्ट से घबराए हुए हैं। गांव में प्रवेश करते ही लोहे का बड़ा सा गेट है। गेट पर 20 साल पहले लिखा था- हरियाली से खुशहाली ग्राम कढ़ाई, जो अब धुंधला हो गया है। गेट पर लगे बोर्ड पर हरे पेंट से योजनाएं लिखी हैं, लेकिन इन पर भी जंक लग गया है जो साफ नहीं दिखाई दे रहीं। एक बोर्ड पर योजना के लिए आवंटित जमीन का पूरा नक्शा भी लगा है। उसकी जमीन पर आम के पेड़ की बगिया है, इन पेड़ों का योजना के तहत पौधरोपण किया गया था। टीम आगे बढ़ी तो धान के खेत नजर आए। हल्की पहाड़ी चढ़ते ही डैम जैसी जगह के उस पार बड़ी-बड़ी मशीनें काम करती नजर आईं। इनमें एक पोकलेन मशीन से पानी में मिट्टी भर रही थी। कुछ आदिवासी इस काम को देखकर मायूस खड़े थे। एक महीने पहले गांव के 6 आदिवासी परिवार ननिया बाई, विमल, नंदलाल, दीनू, दिनेश, नवलू को जमीन से हटने का नोटिस भेजा गया था। प्रशासन इन आदिवासियों को अतिक्रमणकारी बता रहा है। गांव के विनायक ने बताया, जब जमीन दी गई थी तो पंचायत ने नक्शे भी बनाए थे। उस समय के प्रस्ताव में सभी के नाम है। इनमें सभी 23 परिवार भूमिहीन हैं। अब यहां वुडन क्लस्टर बनाने के लिए दो तालाबों को बंद कर दिया गया है। जेसीबी मशीनों से जमीनों को लेवल किया जा रहा है। जिला उद्योग महाप्रबंधक, संघ अध्यक्ष और सचिव ने शासन की आरक्षित वन भूमि ग्राम कढ़ाई में वुडन क्लस्टर खोलने के लिए कलेक्टर कार्यालय को गलत एवं फर्जी जानकारी दी। आदिवासियों को भूमिहीन करने, पैसा कानून का उल्लंघन करने, आरक्षित वनों को काटने और तालाब को समाप्त करने पर तीनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

क्लस्टर के लिए वन विभाग की कोई एनओसी न होने के बावजूद कलेक्टर और शासन को झूठी जानकारी भेज दी गई। ऐसा ही अन्य विभागों की अनापत्ति में भी किया गया। ग्रामसभा की विशेष बैठक में कोई प्रस्ताव नहीं लिया। 2 अक्टूबर को आयोजित बैठक में विशेष कार्यवाही प्रस्ताव पंजी में वुडन क्लस्टर को निरस्त करने का आवेदन लिया गया है। भूमि के समीप आरक्षित वन क्षेत्र है, जहां पर वुडन क्लस्टर खुलने के बाद भारी मात्रा में सागौन एवं अन्य प्रजातियों के जंगल की एवं जानवरों की जान को खतरा है। वुडन क्लस्टर के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय, भारत शासन व राज्य शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा से 20 किलोमीटर दूरी पर लकड़ी से चिराई संबंधित कार्य होना चाहिए।

● **बृजेश साहू**

मप्र सहित देशभर में जिस गति से शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, गांवों का विकास हो रहा है, उससे आने वाले समय में बिजली की मांग और बढ़ने वाली है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दिशा-निर्देशों पर बिजली उत्पादन के लिए ऊर्जा के तमाम स्रोतों पर काम करते हुए प्रदेश को पावर हब बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। खासकर मप्र नवकरणीय ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

सौर ऊर्जा बनेगी मप्र की शक्ति

बिजली जनजीवन का मुख्य आधार है। थोड़ी देर के लिए भी बिजली चली जाएं तो सारी व्यवस्थाएं ठप हो जाती हैं। अगर यह कहा जाए कि बिजली के बिना जीवन सहज रूप से नहीं चल सकता तो यह अतिश्योक्ति नहीं होगी। बिजली उत्पादन पूरे देश में हमेशा गंभीर मुद्दा रहा है। ताप विद्युत और जल विद्युत से परंपरागत रूप से विद्युत उत्पादन होता रहा है। ताप संयंत्रों से पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर नवकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता दी गई। नवकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा प्रमुख है। सौर परियोजना से उत्पादित बिजली की लागत ताप और जल विद्युत उत्पादन से जहां कम होती है वहां इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। मप्र में भी नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन को प्राथमिकता देने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दिशा-निर्देशन में काम हो रहा है। इसका परिणाम यह देखने को मिल रहा है कि आज मप्र सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में सिरमौर बन गया है।

प्रधानमंत्री मोदी की आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रतिबद्धता का लक्ष्य 2047 तक भारत को ऊर्जा के मामले में स्वतंत्र बनाना है। हालांकि, भारत वर्तमान में अपने तेल का 90 प्रतिशत और औद्योगिक कोयले का 80 प्रतिशत आयात करता है। वैश्विक ऊर्जा बाजारों में मूल्य और आपूर्ति में उतार-चढ़ाव, जैसा कि हाल के वर्षों में देखा गया है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को प्रभावित करता है, जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में व्यापक मुद्रास्फीति होती है। स्वच्छ ऊर्जा की लागत में हाल ही में हुई नाटकीय गिरावट भारत को अक्षय ऊर्जा, बैटरी भंडारण, ईवी और हरित हाइड्रोजन में निवेश के माध्यम से ऊर्जा आयात को कम करने का अवसर प्रदान करती है। यह अध्ययन भारत के लिए अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और 2047 तक लगभग पूर्ण ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने के मार्ग का आंकलन करता है, जो भारत के तीन सबसे बड़े ऊर्जा उपभोग क्षेत्रों (बिजली, परिवहन और उद्योग) पर केंद्रित है, जो सामूहिक रूप से ऊर्जा खपत और ऊर्जा से संबंधित कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन के 80 प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे में सरकार का फोकस सौर ऊर्जा पर है। मप्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने में सबसे आगे है।

वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के अनुकूल पर्यावरण संरक्षित प्रदेश बनने में मप्र निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज मप्र मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रचने जा रहा है। वर्ष 2012 में प्रदेश की लगभग 500 मेगावॉट नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता थी। वर्तमान में कुल क्षमता बढ़कर 7 हजार मेगावॉट हो गई है, जो कि विगत 12 वर्षों में लगभग 14 गुना बढ़ी है। राज्य की कुल ऊर्जा क्षमता में

5 साल में परमाणु संयंत्र से बिजली

मप्र में करीब 5-6 साल बाद परमाणु संयंत्र से उत्पादित बिजली मिलने की संभावना है। संभावना जताई जा रही है कि मंडला के चुटका और शिवपुरी के भीमपुर में बन रहा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2029-30 में तैयार हो जाएगा। इनसे बिजली बनने लगेगी। ऊर्जा विभाग सहमति पत्र जारी कर चुका है। इसके बाद खरीदी के लिए निजी कंपनियों पर निर्भरता भी कम होगी। अभी 33 प्रतिशत बिजली निजी कंपनियों से खरीदी जा रही हैं। इसमें गैर परंपरागत तरीकों से बनी बिजली की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। मप्र सरकार ने इन दोनों परियोजनाओं के निर्माण में आ रही रुकावटें दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा मनु श्रीवास्तव को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। अपर मुख्य सचिव जल संसाधन व लोक निर्माण विभाग, प्रमुख सचिव राजस्व, संभागायुक्त जबलपुर, कलेक्टर मंडला संचालक एनपीसीआईएल, कार्यपालक निदेशक एनपीसीआईएल, परियोजना निदेशक चुटका-भीमपुर एनपीसीआईएल को सदस्य और मुख्य निर्माण अभियंता एवं इकाई प्रमुख चुटका परियोजना एनपीसीआईएल को कमेटी का समन्वयक बनाया गया है। जानकारी के अनुसार सौर ऊर्जा के साथ ही प्रदेश सरकार अब परमाणु बिजली के उत्पादन की दिशा में कदम बढ़ाने जा रही है। प्रदेश में दो बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं आकार लेंगी। इनमें से एक परमाणु ऊर्जा परियोजना की क्षमता 1400 मेगावाट और दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना की क्षमता 2800 मेगावाट होगी। इस तरह दोनों परियोजनाओं से कुल 4200 मेगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होगा।

नवकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़कर 21 प्रतिशत हो गई है। राज्य सरकार की नवकरणीय ऊर्जा की उत्पादन क्षमता को वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 20 हजार मेगावॉट करने की योजना है। आज प्रदेश में मौजूद रीवा और ओंकारेश्वर जैसी विश्व-स्तरीय सौर परियोजनाएं देश में राज्य सरकार के दृढ़ संकल्प और इच्छा-शक्ति का गौरव-गान कर रही हैं। मप्र नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार करने में अग्रणी रहा है। रीवा सोलर प्रोजेक्ट 1590 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित है। यह विश्व के सबसे बड़े सिंगल साइड सौर संयंत्रों में से एक है। इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन को एक आदर्श के रूप में पहचान मिली है। परियोजना से उत्पादित ऊर्जा का 76 प्रतिशत अंश पावर मैनेजमेंट कंपनी उपयोग कर रही है। पहली बार ओपन एक्सेस से राज्य के बाहर दिल्ली मेट्रो जैसे व्यावसायिक संस्थान को उत्पादित बिजली का शेष 24 प्रतिशत अंश भी प्रदान किया जा रहा है। इससे प्रतिवर्ष 15.7 लाख टन कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन को रोका जा रहा है, जो 2 करोड़ 60 लाख पेड़ लगाने के बराबर है।

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हुए मप्र में वर्तमान में आगर-शाजापुर-नीमच में 1500 मेगावॉट क्षमता का सोलर पार्क निर्माणाधीन है। इसमें आगर जिले की 550 मेगावॉट की क्षमता स्थापित की जा चुकी है। शाजापुर एवं नीमच जिले की 780 मेगावॉट क्षमता अक्टूबर 2024 तक पूर्ण कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त मंदसौर में 250 मेगावॉट का सोलर पार्क तैयार किया गया है। इससे उत्पादित ऊर्जा मप्र की वितरण कंपनियों द्वारा क्रय की जा रही है। प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा के तट पर बसे ओंकारेश्वर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट (पानी पर तैरने वाली सौर परियोजना) विकसित किया जा रहा है। इसकी क्षमता 600 मेगावॉट है। इससे बहुमूल्य भूमि की बचत होगी। पैनल से पानी की सतह को ढंकने से वाष्पीकरण द्वारा होने वाले जल की हानि को कम किया जा सकेगा। परियोजना की स्थापना से कोई विस्थापित नहीं होगा। पैनल्स की सफाई के लिए भूमिगत जल की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट की प्रथम चरण में 200 मेगावॉट क्षमता स्थापित हो चुकी है। कुल 3900 करोड़ रुपए की लागत से संपूर्ण 600 मेगावॉट की क्षमता स्थापित होने पर यह 12 लाख टन कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी और वर्ष 2070 तक भारत सरकार के शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन मिशन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। उक्त परियोजना जल वाष्पीकरण को कम करके जल संरक्षण में भी सहायक होगी। प्रदेश को नवकरणीय ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने के अतिरिक्त देश के उन राज्यों, व्यवसायिक संस्थानों को भी नवकरणीय ऊर्जा आपूर्ति हेतु प्रयासरत हैं, जहां इसकी उपलब्धता कम है अथवा आवश्यकता है। नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में किए जा रहे इन सभी प्रयासों के माध्यम से प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया के साथ-साथ लंग्स ऑफ इंडिया तैयार करने का विजन रखा गया है। प्रदेश सरकार की नई नवकरणीय ऊर्जा नीति-2022 का लक्ष्य नवकरणीय ऊर्जा परियोजना विकास के लिए प्रदेश में समग्र वातावरण का विकास करना है।

मप्र में निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले दशक में नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 11 गुना बढ़ी है। यह राज्य की स्थापित क्षमता का लगभग 24 प्रतिशत है। सौर ऊर्जा क्षमता 52 प्रतिशत बढ़ी है। वर्तमान में 1000 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क संचालित हैं और 1778 मेगावॉट के पार्क जल्द ही शुरू हो जाएंगे। साथ ही 3350 मेगावॉट क्षमता की परियोजनाएं लागू होने की प्रारंभिक स्थिति में हैं। इनमें एक हजार मेगावाट क्षमता की सोलर पार्क परियोजनाएं, 250 मेगावाट मंदसौर सोलर पार्क, 750 मेगावाट रीवा सोलर पार्क शामिल हैं, रीवा मेगा पार्क को नवाचारी प्रयासों की वजह से कई पुरस्कार मिले। इसने प्रति इकाई 2.97 रुपए की न्यूनतम मूल्य दर हासिल की। इसे विश्व बैंक के प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्तमान में 1778 मेगावॉट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं में 1500 मेगावॉट की आगर मालवा, शाजापुर और नीमच सोलर पार्क और 500 मेगावॉट की नीमच पार्क परियोजना शामिल हैं। भविष्य की परियोजनाओं में विश्व के सबसे बड़े ओंकारेश्वर जलाशय में 600 मेगावॉट फ्लोटिंग का सोलर पार्क शामिल है। इससे साल के अंत तक पूरी तरह से उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 3350 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं में 1400 मेगावाट की मुरैना और 450 मेगावाट की छतरपुर पार्क और बीरसिंहपुर जलाशय, इंदिरा सागर जलाशय और गांधी सागर जलाशय में 1500 मेगावॉट की फ्लोटिंग सोलर परियोजनाएं शामिल हैं।

● श्याम सिंह सिकरवार

दूसरे राज्यों को रौशन कर रहा मप्र

प्रदेश में मप्र जनरेटिंग कंपनी के ताप विद्युत गृह से 5400 मेगावाट, मप्र जनरेटिंग कंपनी के जल विद्युत ग्रह से 921.58 मेगावाट, संयुक्त क्षेत्र के जल विद्युत गृह और अन्य से 2484.13 मेगावाट, केंद्रीय क्षेत्र के ताप विद्युत गृह से 5251.74 मेगावाट, दामोदर घाटी विकास निगम के ताप विद्युत गृह से 3401.5 मेगावाट और नवकरणीय ऊर्जा स्रोत से 5171 मेगावाट प्राप्त होती है। यानी प्रदेश में कुल बिजली उत्पादन क्षमता 22730 मेगावाट है। यानी प्रदेश में सरप्लास बिजली 8 से 9 हजार मेगावाट है। मप्र ओडिशा, उप्र और तेलंगाना आदि राज्यों को बिजली बेच रहा है। यह स्थिति तब है जब मप्र के लगभग सभी ताप विद्युत गृह सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। यानी इन ताप विद्युत गृहों की कोई न कोई इकाई खराब होने के कारण बंद रहती है। वहीं बूढ़ी हो चुकी इकाईयों का मेंटेनेंस मंहगा पड़ रहा है। इस कारण लगभग सभी ताप विद्युत गृहों में बिजली का उत्पादन क्षमता से आधा भी नहीं हो रहा है। जबकि बिजली उत्पादन का खर्च वही पड़ रहा है। इससे सरकार को रोजाना करोड़ों रुपए की चपत लग रही है। गौरतलब है कि प्रदेश में कुल बिजली उत्पादन क्षमता 22,730 मेगावाट है। मप्र जनरेटिंग कंपनी के ताप विद्युत गृह से 5400 मेगावाट, मप्र जनरेटिंग कंपनी के जल विद्युत गृह से 921.58 मेगावाट, संयुक्त क्षेत्र के जल विद्युत गृह और अन्य से 2484.13 मेगावाट, केंद्रीय क्षेत्र के ताप विद्युत गृह 5251.74 मेगावाट, दामोदर घाटी विकास निगम के ताप विद्युत गृह 3401.5 मेगावाट और नवकरणीय ऊर्जा स्रोत 5171 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। प्रदेश बिजली के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। लेकिन प्रदेश के ताप विद्युत गृह सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। प्रदेश के ताप विद्युत गृहों से 50 फीसदी से कम बिजली उत्पादन हो रहा है।

मप्र में बनेगा एलीफेंट कॉरिडोर

मप्र में हाथियों के लिए एलीफेंट कॉरिडोर बनाया जाएगा। साथ ही बफर और कोर एरिया जोन भी बनाया जाएगा। इसके अलावा एलीफेंट टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसके निर्देश दिए हैं। गत दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उमरिया में हुई हाथियों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री निवास में वन विभाग की बैठक ली। रिव्यू मीटिंग के बाद दो अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने बैठक में वन विभाग को मप्र में एलीफेंट टॉस्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने कहा कि प्रदेश में राज्य स्तरीय हाथी टास्ट फोर्स गठित किया जाएगा। हाथी-मानव सहअस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए हाथी मित्र बनाए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में हाथियों की आवाजाही अधिक है वहां किसानों की फसलों को बचाने के लिए सोलर फेंसिंग की व्यवस्था होगी। यही नहीं किसानों को कृषि के अलावा कृषि वानिकी एवं अन्य वैकल्पिक कार्यों से भी जोड़ने के प्रयास होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मप्र में आने वाले समय में ऐसे वन क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जिसमें हाथियों की बसाहट के साथ सहअस्तित्व की भावना मजबूत हो सके। केंद्रीय वनमंत्री से भी इस संबंध में चर्चा हुई है। वे मार्गदर्शन करेंगे जिससे वन विभाग इस क्षेत्र में ठोस कार्यवाही कर सके। जिन जिलों में हाथी वन क्षेत्रों में रह रहे हैं वहां हाथी मित्र जन जागरूकता के लिए कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में उमरिया जिले के वन क्षेत्र में पिछले दिनों 10 हाथियों की अलग-अलग दिन हुई मृत्यु की घटना दुखद और दर्दनाक है, जिसे राज्य शासन ने गंभीरता से लिया है। वन राज्य मंत्री सहित वरिष्ठ अधिकारियों के दल ने क्षेत्र का भ्रमण किया है। प्रारंभिक रिपोर्ट में कोई कीटनाशक नहीं पाया गया है। हाथियों के बड़े दल के रूप में आने की घटना गत दो-तीन वर्ष में एक नया अनुभव भी है। उमरिया और सीधी जिले में बड़ी संख्या में हाथियों की मौजूदगी दिख रही है। ऐसे में फील्ड डायरेक्टर व अन्य अधिकारियों को सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाथियों की मृत्यु की इतनी बड़ी घटना के समय फील्ड डायरेक्टर का अवकाश से वापस न आना और पूर्व में हाथियों के दल आने के संदर्भ में जो आवश्यक चिंता की जानी चाहिए, वह नहीं की गई। इस लापरवाही के लिए फील्ड डायरेक्टर गौरव चौधरी को सस्पेंड किया गया है। साथ ही प्रभारी एसीएफ फतेहसिंह निनामा को भी निलंबित किया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि बांधवगढ़ क्षेत्र एवं अन्य वन क्षेत्रों में हाथियों के रहने की अनुकूल और आकर्षक स्थिति है। वन क्षेत्रों का प्रबंधन उत्तम होने से हाथियों के दल जो छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों से आया करते थे और वापस चले जाते थे, वे अब वापस नहीं जा रहे हैं। यहां बड़े पैमाने पर हाथियों द्वारा डेरा डालने की स्थिति देखी जा रही है। यह मप्र की वन विभाग की गतिविधियों का हिस्सा बन गए हैं। ऐसे में हाथियों की आवाजाही को देखते हुए स्वाभाविक रूप से स्थाई प्रबंधन के लिए शासन के स्तर पर हाथी टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया जा रहा है। हाथियों को अन्य वन्य प्राणियों के साथ किस तरह रहवास की सावधानियां रखना चाहिए, इसके लिए योजना बनाई जा रही है। इसमें कर्नाटक, केरल और असम जैसे राज्यों की बेस्ट प्रेक्टिसेस को शामिल किया जाएगा। इन राज्यों में बड़ी संख्या में हाथी रहते हैं। इन राज्यों में मप्र के अधिकारियों को भेजा जाएगा ताकि सहअस्तित्व की भावना के आधार पर हाथियों के साथ बफर एरिया, कोर एरिया में बाकी का जन जीवन प्रभावित न हो, इसका अध्ययन किया जाएगा। हाथियों की सुरक्षा को भी खतरा न हो, इस पर गंभीरता से विचार किया है। एक बात और अनुभव की गई है कि नजदीक के बफर एरिया के बाहर के जो मैदानी इलाके हैं वहां की फसलें उसमें सोलर फेंसिंग या सोलर पैनल द्वारा व्यवस्था कर फसलों को सुरक्षित किया जाएगा। यह मनुष्यों के लिए भी सुरक्षा का साधन होगा।

वन विभाग को कहा गया है कि ऐसे क्षेत्रों में कहां-कहां कृषि हो रही है, उसे कैसे बचा सकते हैं। हाथी फसल नष्ट न कर पाएं, यह सुनिश्चित करना होगा। यह चिंता के साथ जागरूकता का भी विषय है। बफर क्षेत्र में ग्रामीण समुदाय की भागीदारी हाथियों और मानव के सहअस्तित्व को सुनिश्चित कर सके ताकि यह एक-दूसरे के साथ जीना सीख सकें। यह कटु सत्य है। इसलिए अभी जो घटना घटी है इसमें जनहानि को लेकर 8 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता था, उसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति करने का निर्णय लिया है। इस घटना में जिन दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनके परिवारों को भी इससे जोड़ा है।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

हाथियों के प्रबंधन के लिए सिर्फ 1 करोड़

वन विभाग की राज्य की विभिन्न योजनाओं के लिए 2665 करोड़ से ज्यादा बजट है। इमारती लकड़ियों के उत्पादन के लिए तक 159 करोड़ का बजट है, लेकिन हाथियों के प्रबंधन के लिए सिर्फ 1 करोड़ सालाना का बजट वन विभाग के पास है। पूरे एक करोड़ की राशि में ही हाथियों का प्रबंधन वन विभाग के अफसर कर लेते हैं। प्रदेश के वन विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए हर साल राशि का प्रावधान किया जाता है। वन विभाग सबसे कम राशि हाथियों के प्रबंधन पर खर्च करता है। इसमें भी हाथियों का प्रबंधन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। साल 2023-24 में हाथियों के प्रबंधन के लिए वन विभाग ने 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इसमें से 62 लाख से अधिक राशि वन विभाग खर्च कर चुका है। वहीं प्रोजेक्ट एलीफेंट के लिए वन विभाग ने इस साल सिर्फ 66 लाख रुपए रखे थे। बजट के हिस्से की ज्यादातर राशि खर्च हो चुकी है। गौरतलब है कि मप्र टाइगर स्टेट है। प्रोजेक्ट टाइगर पर प्रदेश का बजट 200 से 300 करोड़ के बीच रहता है, लेकिन हाथियों के प्रबंधन पर वन विभाग की कोई योजना ही नहीं है। यही वजह है कि इनके प्रबंधन के लिए बजट में भी इजाफा नहीं हो सका।

बुंदेलखंड में अब घर-घर पानी

हर घर में शुद्ध पेयजल का सपना हो रहा पूरा

जब वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन की घोषणा हुई और उसका लाभ उप्र की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प लिया। खासकर बुंदेलखंड के सात जिलों को सबसे पहले इस योजना का लाभ देने के लिए चुना गया। यही वो समय था, जब बदलाव की चली हवा बुंदेलखंड के लोगों के लिए उम्मीद में बदल गई। इस जल जीवन मिशन का मुख्य लक्ष्य दिसंबर 2024 तक बुंदेलखंड के हर घर तक नल से जल पहुंचाना है। इस योजना के तहत मात्र 5 वर्षों में ही बुंदेलखंड और विंध्य के घर-घर में नल से स्वच्छ पेयजल पहुंच रहा हैं। जल जीवन मिशन की योजना पहुंचने से वर्षों से बूंद-बूंद पानी को तड़पने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों की तकदीर बदल गई है। आज यहां हर घर में शुद्ध पेयजल का सपना पूरा हो रहा है। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की हर घर नल से जल योजना बुंदेलखंड क्षेत्र की नई कहानी बन गई है। जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना ने प्रदेश के बड़े क्षेत्र को पेयजल के बड़े संकट से निजात दिला दी है। हजारों गांवों में नल से घर-घर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति शुरू हो जाना इसका जीता जागता प्रमाण है। घर-घर नल से जल मिल रहा है। शुद्ध पानी मिलने से लोगों को बीमारियों से तो निजात मिली ही हैं, साथ ही पानी की उपलब्धता की समस्या भी दूर हो रही है।

बुंदेलखंड... जो कभी पीने के पानी की समस्या से जूझता था, वहां आज 90 फीसदी से ज्यादा घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंच रहा है। बुंदेलखंड का एक बड़ा क्षेत्र है, जहां पर करोड़ों लोग रहते हैं। यहां के गांवों में रहने वाले लोगों के लिए पीने का पानी एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों की तीन पीढ़ियां यहां पानी लाने की जद्दोजहद में गुजर गईं। सालों से महिलाएं यहां कई किलोमीटर दूर से सिर पर पानी ढोकर लाया करती थीं। सुबह 4 बजे से शुरू होने वाला यह सिलसिला देर शाम तक बदस्तूर जारी रहता था, लेकिन अब पीने के पानी की इस जद्दोजहद के बीच उम्मीद की किरण उनके जीवन में खुशियों का संदेश लेकर आई है। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन का ऐलान हुआ और इसे गांव-गांव तक पहुंचाने का फैसला लिया गया। खासकर बुंदेलखंड के पांच जिलों को सबसे पहले इस योजना का लाभ देने के लिए चुना गया। यही वह समय था, जब बदलाव की बयार बुंदेलखंड के लोगों के लिए उम्मीद में बदल गई।

जल जीवन मिशन का मुख्य मकसद दिसंबर 2024 तक बुंदेलखंड के हर घर तक नल से जल पहुंचाना है। इस योजना के तहत मात्र चार सालों में ही बुंदेलखंड के घर-घर में नल से साफ पीने का पानी पहुंच रहा है। बुंदेलखंड में पीने के पानी की समस्या इतनी विकट थी कि इसकी वजह से यहां के लोग अपनी लड़कियों की शादी नहीं करते थे। मगर आज उसी बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन की योजना खुशियों की सौगात लाई है। इस योजना के तहत हर घर में नल हो और उसमें से स्वच्छ पेयजल आता हो, इसका सपना साकार हुआ है। साथ ही जलजनित बीमारियों में कमी आने से यहां के लोगों का स्वस्थ जनजीवन भी बना है। जल जीवन मिशन न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में नल से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करा रहा है, बल्कि होनहार एवं जरूरतमंद लोगों को रोजगार भी प्रदान कर रहा है। हालांकि सूखाग्रस्त कहलाने वाले बुंदेलखंड के गांवों में घर-घर तक पेयजल पहुंचने के रास्ते खुल गए हैं। साथ ही गांव के लोगों को यहां बनाई गई परियोजनाओं में पंप ऑपरेटर, मोटर मैकेनिक, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मेसन के रूप में काम भी मिलने लगा है। हर घर नल जल योजना के तहत हर गांव वासी को प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की जाती है। सरकार स्कूली बच्चों के भविष्य और महिलाओं के जीवन को संवारने और उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रख रही है। गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर गांव से पांच महिलाओं को पानी की टेस्टिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। महिलाएं गांव में फील्ड टेस्ट किट से पानी की जांच कर रही हैं। बुंदेलखंड के छतरपुर में कुछ ऐसे गांव थे, जहां जलसंकट की वजह से लोग अपनी लड़कियों की शादी नहीं करते थे। जल जीवन मिशन योजना पहुंचने के बाद हालात बदले और साफ पीने का पानी पहुंचने लगा है। ऐसे गांवों के लिए जल जीवन मिशन योजना रिश्तों की लाइफ लाइन बनी है। पथरीली जमीनों पर पीने के पानी के लिए पाइपलाइन बिछाने, गांव-गांव पानी की टंकियां बनाने, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने, जल स्त्रोतों को बढ़ाने और घर-घर तक नल से जल पहुंचाने का काम तेजी से किया गया है।

मीलों दूर से पानी भरकर लाने वाली महिलाओं को घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचने से बड़ी राहत मिली है। खासकर बुंदेलखंड में महिलाओं को मीलों दूर से पानी भरकर लाना पड़ता था, लेकिन जल जीवन मिशन की योजना के शुरू होने के बाद से अब वे घर का कामकाज करने के साथ बच्चों की पढ़ाई में भी समय दे रही हैं और खुद भी पढ़ने के लिए समय निकाल पा रही हैं। इससे वे खुद का रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। जल जीवन मिशन योजना के आने से वर्षों से बूंद-बूंद पानी को तरसने वाले बुंदेलखंड के लोगों की तकदीर बदल गई है। आज यहां हर घर में साफ-स्वच्छ पानी पीने का सपना पूरा हो रहा है। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की हर घर नल से जल योजना बुंदेलखंड की नई कहानी बन गई है। जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना ने प्रदेश के बड़े क्षेत्र को पेयजल के बड़े संकट से निजात दिला दी है। हजारों गांवों में नल से घर-घर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति शुरू हो जाना इसका जीता जागता प्रमाण है। जल जीवन मिशन न सिर्फ गांव के इलाकों में नल से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करा रहा है, बल्कि होनहार और जरूरतमंद लोगों को रोजगार भी प्रदान कर रहा है। शुद्ध पानी से दांतों की उम्र बढ़ने के साथ त्वचा रोगों से भी छुटकारा मिल रहा है। उल्टी, दस्त, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, दांत, हड्डी, किडनी, लीवर से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम हो रहा है। बुंदेलखंड के महोबा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट, बांदा, झांसी में कुछ ऐसे गांव थे, जहां जलसंकट की वजह से लोग अपनी लड़कियों की शादी नहीं करते थे। जल जीवन मिशन योजना पहुंचने के बाद स्थितियां बदलीं और स्वच्छ पेयजल पहुंचने लगा है। ऐसे गांवों के लिए जल जीवन मिशन योजना रिश्तों की लाइफलाइन बनी है। पथरीली जमीनों पर पीने के पानी के लिए पाइपलाइन बिछाने, गांव-गांव पानी टंकियों को बनाने, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने, जल स्त्रोतों को बढ़ाने और घर-घर तक नल से जल पहुंचाने का काम तेजी से किया गया है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

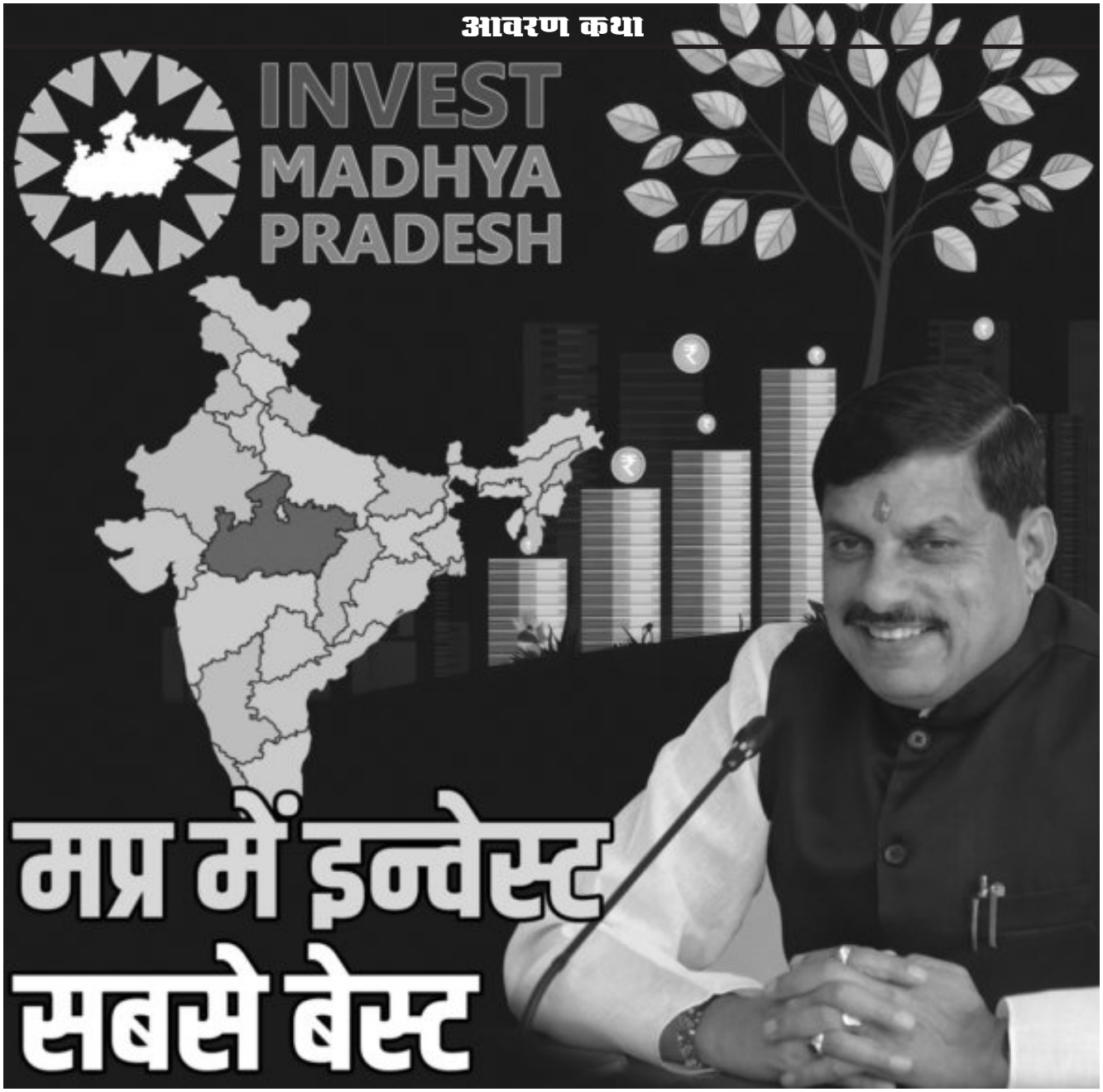

मप्र में इन्वेस्ट सबसे बेस्ट

मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की जो पहल की है उसके परिणाम स्वरूप मप्र में निवेश करने के लिए औद्योगिक घरानों में होड़ लग गई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि मप्र में अब तक 2,82,700 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। जो इस बात का संकेत है कि निवेशक यह मान रहे हैं कि मप्र में इन्वेस्ट... सबसे बेस्ट। रीजनल इंडस्ट्रीयल समिट की सफलता को देखते हुए अब मुख्यमंत्री भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने ब्रिटेन और जर्मनी जाएंगे।

● राजेंद्र आगाल

जिद करो और दुनिया बदलो की तर्ज पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मप्र के हर क्षेत्र में एक समान विकास के संकल्प पर काम कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का सहारा लिया है। जिसके तहत हर जिला और संभाग स्तर पर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में एक समान विकास का यह फॉर्मूला निवेशकों को भी खूब पसंद आया है। अब निवेशक अपनी पसंद की जगह पर निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि उद्योगों के लिए आवश्यक सड़क, बिजली, पानी, और अधोसंरचना सहित सुशासन के हर पैमाने में मप्र निवेशकों के लिए पहली पसंद बन रहा है। औद्योगिक घरानों का भरोसा जीतने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को लगातार सफलता मिल रही है। वहीं अब मुख्यमंत्री मप्र में निवेश करने के लिए विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने की कवायद में जुट गए हैं। वे ब्रिटेन और जर्मनी जाएंगे।

मप्र में पिछले 11 महीने में औद्योगिक विकास की नई लहर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में औद्योगिक विकास की जो पहल की है उसके परिणाम स्वरूप अब तक 2,82,700 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। जानकारों का कहना है कि प्रदेश में जिस तेजी से निवेश के प्रस्ताव मिल रहे हैं, उससे मप्र का औद्योगिक विकास मिसाल बनेगा। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 24 नवंबर को मुंबई से अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर रवाना होंगे, जिसमें वे यूके और जर्मनी के विभिन्न उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात करेंगे। यह यात्रा फरवरी 2025 में मप्र में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) के मद्देनजर की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन का प्रयास है कि वे राज्य में निवेश के नए अवसरों को ला सकें और विदेशी निवेशकों को इस आयोजन के लिए आमंत्रित कर सकें। यात्रा के दौरान कई अधिकारी भी होंगे। यह टीम यूके और जर्मनी में विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगी और उन्हें मप्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन का यह दौरा राज्य में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने इस यात्रा से पहले देश में मुंबई, बेंगलुरु, कोयंबटूर और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों में उद्योगपतियों के साथ बातचीत की है, जहां उन्होंने मप्र में निवेश के लाभ और अवसरों को उजागर किया। राज्य सरकार ने प्रदेश में संभाग स्तर पर रीजनल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन भी शुरू कर दिया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करना है। उद्योगों के लिए आवश्यक सड़क, बिजली, पानी और अधोसंरचना सहित सुशासन के हर पैमाने में मप्र निवेशकों के लिए पहली पसंद बन रहा है। औद्योगिक घरानों का भरोसा जीतने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को लगातार सफलता मिल रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक हुए पांचों कॉन्क्लेव में अब तक प्रदेश में 1.82 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनसे 2 लाख 3 हजार 420 नए रोजगार मिलेंगे। सरकार प्रदेश में निवेश के लिए मुंबई, बेंगलुरु , कोयंबटूर और कोलकाता में इंटरेक्टिव सेशन कर चुकी है। इसमें भी 1 लाख 700 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इस तरह अब तक मप्र को 2 लाख 82 हजार 700 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। सभी जिलों में औद्योगिक विकास के लिए शुरू की गई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का सिलसिला जारी है। पांच कॉन्क्लेव के बाद अगली कॉन्क्लेव नर्मदापुरम में होगी। कृषि आधारित उद्योग, नवकरणीय ऊर्जा उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण के निर्माण पर फोकस होगा। मप्र में मोहन सरकार की अब तक 5 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो चुकी हैं। इनमें उज्जैन 1 लाख करोड़, जबलपुर 22 हजार करोड़, ग्वालियर 8 हजार करोड़, सागर 23,181 करोड़ और रीवा 30,814 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं।

टेक्निकल टेक्सटाइल पर फोकस

मप्र के कॉलेजों में अब टेक्निकल टेक्सटाइल पर फोकस किया जाएगा। भारत सरकार के प्रस्ताव के बाद औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग ने उच्च शिक्षा विभाग को इस संबंध में चिट्ठी लिखी है। इसके बाद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सभी कॉलेजों से टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए केंद्र सरकार से फंड लेने के लिए आवेदन करने को कहा है। इतना ही नहीं नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन इसे बढ़ावा देने के लिए इसी माह दो दिनी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी भोपाल में करने वाला है। टेक्निकल टेक्सटाइल ऐसे कपड़े हैं जो सौंदर्य और सजावटी विशेषताओं के बजाय तकनीकी प्रदर्शन और क्वालिटेटिव वर्किंग के लिए निर्मित होते हैं, वे (टेक्निकल टेक्सटाइल) तकनीकी वस्त्र श्रेणी में आते हैं। इन प्रोडक्ट्स को 12 अलग-अलग कैटेगरी में बांटा है। ये कैटेगरी एग्रोटेक, ओकोटेक, बिल्डटेक, मेडिटेक, जियोटेक, क्लॉथटेक, मोबिलटेक, होमटेक, स्पोर्ट्सटेक, इंडुटेक, प्रोटेक, पैकटेक हैं। राष्ट्रीय स्तर की इस टेक्निकल टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस को लेकर शासन स्तर पर कवायद तेज हो गई है और कॉन्फ्रेंस की तारीख तय की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस का खर्च भारत सरकार उठाएगी और औद्योगिक पार्टनर्स के साथ अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को इसमें बुलाया जाएगा। ताईवान और जापान ने इंडिया में इन्वेंस्ट करने में रूचि दिखाई है। इसलिए यहां के निवेशकों को भी बुलाया जा सकता है। इस कॉन्फ्रेंस में मप्र के मुख्यमंत्री की ओर से टेक्निकल टेक्सटाइल पर पॉलिसी जारी की जाएगी। इसमें तमिलनाडु और ओडिशा की भागीदारी होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रस्ताव के बाद सभी शासकीय, अनुदान प्राप्त अशासकीय और निजी महाविद्यालयों को इसके लिए आवेदन करने को कहा है। भारत सरकार के नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन की ओर से राज्य सरकार को पत्र लिखकर इस मिशन के कामों की जानकारी पिछले माह दी गई थी।

जमीनों की मांग बढ़ी

मप्र में औद्योगिक विकास के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का जो फॉर्मूला शुरू किया है, उसका परिणाम भी दिखने लगा है। उसके परिणाम स्वरूप मप्र में निवेश करने के लिए औद्योगिक घरानों में होड़ लग गई है। इसको देखते हुए प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 15 नए औद्योगिक क्षेत्र जल्द शुरू किए जाएंगे। इनका विकास 323 हेक्टेयर जमीन पर किया जा रहा है। यह क्षेत्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग विकसित कर रहा है। सागर संभाग में सबसे ज्यादा चार क्षेत्र बनेंगे। इससे बुंदेलखंड में निवेश की संभावना है। इसके अलावा नए जिलों में भी औद्योगिक क्षेत्रों का विकास शुरू किया गया है। यहां केवल एमएसएमई के दायरे में आने वाले उद्यम ही चलेंगे। बड़े उद्योगों को जमीन नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार अन्य राज्यों में उद्योगपतियों के

पीथमपुर, धार और बदनावर में नए इंडस्ट्रीयल एरिये की तैयारी

अगले साल प्रस्तावित ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट से पहले मप्र इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआईडीसी) नए औद्योगिक क्षेत्र तैयार कर रहा है। इंदौर-धार जिले में कुछ नए क्षेत्र विकसित करने के साथ पीथमपुर में सेक्टर-8 और 9 के साथ सेक्टर-6 का फेस-2 भी विकसित किया जाएगा। इनके लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जा रही है। धार जिले में धामनोद के पास जैतापुरा में भी जमीनों का आवंटन लगभग हो चुका है। इसके विस्तार के रूप में तारापुर, लालबाग-बसवी में नए प्रोजेक्ट प्रस्तावित किए गए हैं। यहां की जमीनें उद्योग विभाग के पास ही हैं। इसलिए अधिग्रहण सहित अन्य प्रक्रिया में लगने वाला समय बचेगा। एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक राजेश राठौर का कहना है, अब तक जो सेक्टर इंदौर-धार रीजन में है, उनमें कई बड़े निवेशक आ चुके हैं। निवेशकों को हर क्षेत्र में जमीन मिल सके और उन्हें आवंटन के लिए इंतजार न करना पड़े, इसलिए कुछ नए प्रस्ताव मुख्यालय को भेजे गए हैं। अभी हमारे पास पीएम मित्र पार्क के अलावा तिलगारा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बरलई में भी जमीन हैं। पुराने एरिया में भी खाली जमीन चिन्हित की जा रही है, जिनका नए सिरे से विकास हो सकता है। अभी तक कुल 1716 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। इन्वेस्टर्स समिट से पहले इनसे संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी।

साथ इंटरेक्टिव सेशन और प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहे हैं। इसके बाद निवेशक भी जमीन की मांग कर रहे हैं। एमएसएमई विभाग के अधिकारियों के अनुसार उद्यमियों को जमीन उपलब्ध कराने प्रदेश के अलग-अलग रीजन में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। मऊगंज और आगर मालवा में और उद्योगों की दृष्टि से पिछड़े जिलों में भी क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। नए 15 औद्योगिक क्षेत्रों में 700 से ज्यादा उद्यम शुरू होने की संभावना है। इनमें प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 6 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। दरअसल, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने मुख्यमंत्री ने 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया है। इसके तहत द्विवार्षिक प्रमुख आयोजन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फरवरी 2025 में भोपाल में होगी। सागर और आसपास खाद्य प्रसंस्करण, खनन, इंजीनियरिंग, और पेट्रोकेमिकल्स जैसे कई उद्योग संचालित हो रहे हैं। कॉन्क्लेव से इनमें भी निवेश बढ़ने की संभावना है। प्रदेश में अभी एमएसएमई के 208 औद्योगिक क्षेत्र हैं। 12.48 लाख उद्यम रजिस्टर्ड हैं। सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के हैं। लगभग 66 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ट्रेडिंग यूनिट को 2021 में शामिल किया गया। थोक और खेरची ट्रेड करने वाले व्यापारी पंजीकृत हो रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में इनकी संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में जो नए औद्योगिक क्षेत्र बन रहे हैं उनका कुल क्षेत्रफल 323.45 हेक्टेयर है। इनमें सागर जिले के पटना ककरी में 21.20 हेक्टेयर में, सागर जिले के रीठौर में 3.99 हेक्टेयर में, टीकमगढ़ जिले के सुनौरा खिरिया में 10.68 हेक्टेयर में, निवाड़ी जिले के जेर में 25.48 हेक्टेयर में, बैतूल जिले के मोही में 14.79 हेक्टेयर में, बालाघाट जिले के कनकी में 12.85 हेक्टेयर में, कटनी जिले के टिकरया तलखा में 19.52 हेक्टेयर में, उज्जैन जिले के महिदपुर में 43.46 हेक्टेयर में, खरगोन जिले के मातमूर में 49.82 हेक्टेयर में, सीहोर जिले के बुदनी में 8.0 हेक्टेयर में, आगर-मालवा जिले के आकली में 9.1 हेक्टेयर में, रीवा जिले के घूमा में 56.83 हेक्टेयर में, धार जिले के जैतपुरा में 21.0 हेक्टेयर में, मऊगंज जिले के पटेहरा में 9.44 हेक्टेयर में और सतना जिले के कोठी में 19.36 हेक्टेयर में औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है।

निवेशकों की पहली पसंद

उद्योगों के लिए आवश्यक सड़क, बिजली, पानी, और अधोसंरचना सहित सुशासन के हर पैमाने में मप्र निवेशकों के लिए पहली पसंद बन रहा है। औद्योगिक घरानों का भरोसा जीतने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को लगातार सफलता मिल रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक हुए पांचों कॉन्क्लेव में अब तक प्रदेश में 1.82 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनसे 2 लाख 3 हजार 420 नए रोजगार मिलेंगे। सरकार प्रदेश में निवेश के लिए मुंबई, बेंगलुरु, कोयंबटूर और कोलकाता में इंटरेक्टिव सेशन कर चुकी है। इसमें भी 1 लाख 700 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इस तरह अब तक मप्र को 2 लाख 82 हजार 700 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।

उधर, गत दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में निवेश संवर्धन पर मंत्रिस्तरीय समिति की बैठक हुई। इसमें मेगा स्तर की औद्योगिक इकाइयों के 10 प्रकरणों को कस्टमाइज्ड पैकेज के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त परियोजनाओं में लगभग 2100 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की संभावना है। प्रस्तावित परियोजनाओं से करीब 6200 व्यक्तियों को सीधे रोजगार प्राप्त होने का अनुमान है। बैठक में टेक्सटाइल की तीन इकाइयों, लक्ष्मीनाथ कल्पना जिला खरगोन, विश्वेश्वरा डेनिम जिला नीमच, मोहिनी एक्टिव लाइफ जिला इंदौर, खाद्य प्र-संस्करण की पांच इकाइयों, डाबर जिला धार, हिंदुस्तान कोकाकोला जिला राजगढ़, मॉड्लेज जिला भिंड, ड्राईटेक जिला पांढुर्ना एवं बेकर्सविले जिला इंदौर, इंजीनियरिंग क्षेत्र की इकाई शक्ति पंप जिला धार तथा एफएमसीजी की इकाई शिवानी डिटर्जेंट जिला धार से संबंधित प्रकरणों पर विचार किया गया। बैठक में बताया गया कि उपरोक्त परियोजनाओं में लगभग 2100 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश आएगा। प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न मदों जैसे कम दरों पर बिजली, पूंजीगत अनुदान, रोजगार सृजन अनुदान एवं प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किया जा रहा है। प्रस्तावित परियोजनाओं से लगभग 6200 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होने का अनुमान है। बता दें, राज्य शासन द्वारा संपूर्ण प्रदेश में औद्योगीकरण एवं निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सतत् रूप से विभिन्न क्षेत्रों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। उक्त आयोजनों के फलस्वरूप प्रदेश में निवेश के लिए सकारात्मक वातावरण बना है।

औद्योगिक विकास को साझा जिम्मेदारी मान रही मोहन सरकार प्रदेश में नए निवेश के लिए अवसर पैदा करने के साथ नई यूनिट्स के शिलान्यास पर फोकस कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कह चुके हैं कि ऐसे कामों में न केवल सरकार की भूमिका है, बल्कि स्थानीय व्यवसायों, समाज और शिक्षा संस्थानों का भी सक्रिय रूप से शामिल होना आवश्यक है। यह समावेशी विकास की दिशा में एक ठोस कदम

है, जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का प्रयास करता है। इसी के चलते प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मोहन सरकार ने रीवा, धार, सागर, सतना और उज्जैन में 21 औद्योगिक इकाइयों का भूमिपूजन किया है। सरकार ने इंडस्ट्रीयल कॉन्क्लेव के जरिये औद्योगिक इकाइयों के भूमिपूजन और लोकार्पण का सिलसिला उज्जैन से शुरू किया, जो जबलपुर, ग्वालियर, सागर के बाद रीवा में हुई कॉन्क्लेव तक जारी रहा है। अब शहडोल, नर्मदापुरम और नीमच में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की तैयारी में सरकार जुट गई है। इंदौर क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्र 6 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास किया गया। जिसमें कुल 2252.42 करोड़ का निवेश और 1046 रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

स्मार्ट इंडस्ट्रीयल पार्क पीथमपुर, जिला धार में मेसर्स पिनेकल मोबिलिटी प्रा.लि. ने पीथमपुर में निवेश का प्रस्ताव रखा। सेक्टर-7 जिला-इंदौर में इलेक्ट्रिक बस एवं इलेक्ट्रिक लाइट व्हीकल्स के लिए 1600 करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया गया, जिससे 501 लोगों को रोजगार मिलेगा। मेसर्स कोर ब्लॉक स्केफहोल्डिंग एंड फॉर्म वर्क प्रा.लि. ने पाइप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 150 करोड़ का प्रस्ताव रखा। जिससे 350 रोजगार पैदा होंगे। मेसर्स रेकबैंक डाटा सेन्टर्स प्रा.लि. ने औद्योगिक क्षेत्र एसईजेड फेस-2, पीथमपुर में 500 करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया जो 150 लोगों को रोजगार देगा। मेसर्स मां तुलजा इंडस्ट्रीज की औद्योगिक क्षेत्र हातोद, जिला-धार में प्लास्टिक प्रोडक्ट एवं पैकेजिंग की 49 लाख की इकाई में 13 लोगों को रोजगार मिलेगा। मेसर्स कारनिश पॉवरझोन प्रा.लि. ने पीथमपुर सेक्टर-3, जिला-धार में इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी एवं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में 1.50 करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया है, जो 27 रोजगार देगा। श्री गजानन इन्टरप्राइजेस ने रेहटा खड़कोद, बुरहानपुर में नॉनफेरस मेटल्स एंड प्रोडक्ट्स में 43 लाख का निवेश किया है। 5 लोगों को रोजगार मिलेगा।

वहीं सागर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत सागर में औद्योगिक क्षेत्र सिद्धगुंवा में 5 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास किया गया। इसमें 8.62 करोड़ का निवेश होगा और 92 लोगों रोजगार मिलेगा। मेसर्स भगतजी ट्रांसफार्मर एंड इलेक्ट्रिकल्स द्वारा 72 लाख रुपए का निवेश किया जाएगा जिससे 25 लोगों को रोजगार मिलेगा। मेसर्स जिगिलक्ष्मी एपरेटर्स प्रा.लि. द्वारा 70 लाख रुपए का निवेश किया जाएगा। जिससे 20 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। मेसर्स श्री द्वारका ट्रेडर्स 93 लाख रुपए का निवेश करेगी। जिससे 17 लोगों को रोजगार मिलेगा। मेसर्स कल्पद्रुम आयरन इंडस्ट्रीज द्वारा 77 लाख रुपए का निवेश किया जाएगा। जिससे 5 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। उज्जैन क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत उज्जैन में मेसर्स एमडीएच प्राइवेट लिमिटेड डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस इकाई की स्थापना से 200 लोगों को रोजगार मिलेगा।

एमएसएमई से बढ़ेगा रोजगार

कम लागत और बड़ा काम। यही वो तरीका है जो अर्थव्यवस्था को गति देकर मप्र की तस्वीर बदल सकता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) का विस्तार सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने का माध्यम बन सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार इसे प्राथमिकता में ले और वो सभी सुविधाएं उपलब्ध कराए जो छोटे उद्योगों के लिए वातावरण बनाने का काम करें। सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। 194 औद्योगिक क्षेत्र केवल एमएसएमई के लिए बनाए गए हैं और प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर में क्लस्टर बनाए गए हैं। सरकार के अनुसार तीन लाख 54 हजार एमएसएमई इकाइयों को पंजीकृत किया है। इनमें 18.33 लाख नौकरियां उत्पन्न करने की क्षमता है। इसके साथ-साथ ग्रामीण कुटीर उद्योग पर भी फोकस करना होगा। स्थानीय स्तर पर इसको लेकर काफी संभावनाएं भी हैं। मप्र में 10 साल में 30 लाख 13 हजार 41.607 करोड़ रुपए के 13 हजार 388 निवेश प्रस्ताव आए। इनमें 3 लाख 47 हजार 891 करोड़ रुपए के 762 पूंजी निवेश हुए हैं। इन पूंजी निवेश से प्रदेश में 2 लाख 7 हजार 49 बेरोजगार को रोजगार मिला है। इसी तरह वर्ष 2007 से अक्टूबर 2016 तक आयोजित इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन पर 50.84 करोड़ रुपए व्यय किए गए और 366 औद्योगिक इकाइयों को 1224 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी गई। मप्र से अधिकांश उत्पादों को जीआई टैग दिलाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें आदिवासियों की पारंपरिक औषधियों, खाद्यान्न और उनकी कलात्मक वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जीआई टैग सबसे अधिक दक्षिण भारत के हैं। मप्र सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के छोटे से छोटे उत्पाद को जीआई टैग मिले। वर्तमान में मप्र में 21 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। मप्र के एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) की ब्रांडिंग की जा रही है। इसके लिए अलग से एक सेल गठित किया गया है। मप्र के रोजगार पोर्टल पर 38 लाख 93 हजार 149 बेरोजगार हैं।

रेडीमेड गारमेंट का हब बनेगा इंदौर

मिनी मुंबई के रूप में ख्यात इंदौर और उसके आसपास तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा है। दरअसल, इन दिनों मप्र में औद्योगिक विकास की नई लहर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में औद्योगिक विकास की जो पहल की है उसके परिणाम स्वरूप मप्र में निवेश करने के लिए औद्योगिक घरानों में होड़ लग गई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि इंदौर में गारमेंट उद्योग लगाने के लिए कई कंपनियों ने इच्छा जाहिर की है। इसको देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि इंदौर आने वाले समय में रेडीमेड गारमेंट का हब बन सकता है। औद्योगिक विकास को साझा जिम्मेदारी मान रही मोहन सरकार प्रदेश में नए निवेश के लिए अवसर पैदा करने के साथ नई यूनिट्स के शिलान्यास पर फोकस कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कह चुके हैं कि ऐसे कामों में न केवल सरकार की भूमिका है, बल्कि स्थानीय व्यवसायों, समाज और शिक्षा संस्थानों का भी सक्रिय रूप से शामिल होना आवश्यक है। यह समावेशी विकास की दिशा में एक ठोस कदम है, जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का प्रयास करता है। इसी के चलते प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मोहन सरकार ने औद्योगिक इकाइयों का भूमिपूजन किया है। सरकार ने इंडस्ट्रीयल कॉन्क्लेव के जरिये औद्योगिक इकाइयों के भूमिपूजन और लोकार्पण का सिलसिला उज्जैन से शुरू किया है, जो जबलपुर, ग्वालियर, सागर के बाद रीवा में हुई कॉन्क्लेव तक जारी रहा है। अब शहडोल, नर्मदापुरम और नीमच में इंडस्ट्रीयल कॉन्क्लेव की तैयारी में सरकार जुट गई है। कपड़ा मिलों की पहचान रहा इंदौर अब रेडीमेड गारमेंट का हब बनने जा रहा है। इंदौर से

110 किमी दूर बदनावर के पास पीएम मित्र (प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल) पार्क प्रोजेक्ट में गुजरात और कोलकाता की दो कंपनियों ने 2500 करोड़ रुपए का निवेश करने में रूचि दिखाई है। इनमें से एक गुजरात की अरविंद मिल कंपनी है, जो कि वस्त्र निर्माण की इकाई लगाने की तैयारी में है। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने जमीन का निरीक्षण भी किया है, वहीं कोलकाता की एक अन्य कंपनी भी यहां होजयरी के कई बड़े ब्रांड के लिए होजयरी वस्त्रों के निर्माण का प्लांट भी लगाएगी। इसके साथ ही यहां पर प्रदेश सहित देशभर से कई छोटी बड़ी 22 कंपनियां भी आने की तैयारी में हैं। इसका फायदा रोजगार के सृजन से होगा। पीएम मित्र पार्क का काम इसी वर्ष जनवरी में शुरू हुआ है, जिसे आगामी ढाई वर्ष में पूरा किया जाना है। करीब दो हजार एकड़ में बन रहे इस पार्क की लागत लगभग 1600 करोड़ रुपए है। एमपीआईडीसी के कार्यकारी निदेशक राजेश राठौर ने बताया कि पीएम मित्र पार्क का काम तेजी से चल रहा है। एप्रोच रोड, वाटर लाइन आदि का काम किया जा रहा है। पिछले कुछ समय में तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और प्रदेश की 22 से अधिक छोटी-बड़ी कंपनियों ने पीएम मित्र पार्क का विजिट किया और निवेश में रूचि दिखाई है। इसमें से कुछ कंपनियों के साथ बातचीत अंतिम दौर में है। आने वाले समय टेक्सटाइल से जुड़ी अन्य बड़ी कंपनियां भी विजिट करने आने वाली हैं। अभी तक 22 से अधिक कंपनियों ने पीएम मित्र का विजिट किया है। इन कंपनियों द्वारा यहां 9462 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने की संभावना है, जिससे 25 हजार से अधिक लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा।

गुजरात की ख्यात कपड़ा कंपनी अरविंद मिल्स जल्द ही इंदौर में बड़ा निवेश करने जा रही है। एमपीआईडीसी (मप्र इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन) के साथ कंपनी की बातचीत फाइनल हो चुकी है। कंपनी बदनावर के पास भैंसोला में बन रहे पीएम मित्र पार्क में बड़ा

प्रोजेक्ट शुरू करेगी, वहीं इंदौर के पास रेडीमेड गारमेंट यूनिट भी डालेगी। इस तरह कुल 1500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। राजस्थान की भी कुछ कंपनियां जो झालावाड़ बेस्ड हैं, वे मंदसौर, नीमच क्षेत्र में निवेश करने जा रही हैं। एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक राजेश राठौर ने बताया कि अरविंद मिल्स से प्रारंभिक चर्चा हो चुकी है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उद्योग विभाग की टीम के साथ बेंगलुरु और कोयंबटूर सहित अन्य शहरों में निवेशकों से मिले थे। दक्षिण भारत की कई इंडस्ट्रीज ने यहां आने की संभावनाएं जताई हैं। ईडी राठौर ने बताया कि 44 करोड़ की लागत से देवी अहिल्या गारमेंट सिटी का निर्माण होगा। इससे 30 हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा। मप्र में निवेश के लिए कई बड़ी कंपनियों ने रूचि दिखाई है। जानकारी के अनुसार गुजरात की अरविंद मिल्स 1500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। वहीं बेस्ट कार्पोरेशन 620 करोड़ रुपए, आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड भीलवाड़ा 850 करोड़ रुपए, ओस्वाल ग्रुप भीलवाड़ा 650 करोड़ रुपए, निहार स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड 580 करोड़ रुपए, पाशा पोलिटेक्स प्रा. लि. 827 करोड़ रुपए, निहार इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस लिमिटेड, लुधियाना 550 करोड़ रुपए केयरफिट इंडस्ट्रीयल प्रा.लि. 600 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही हैं। पीथमपुर में पिनेकल मोबिलिटी कंपनी 600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। शुरुआत में 500 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जैसे ही पूरी क्षमता के साथ वर्किंग शुरू होगी, 500 लोगों को और रोजगार मिलेगा। यानी एक हजार लोगों को कंपनी रोजगार देगी। 48 एकड़ में बनने वाले इस प्लांट का 23 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वर्चुअली शुभारंभ कर चुके हैं। जिसमें इलेक्ट्रिक बसों और ट्रकों का निर्माण होगा। यह प्लांट 2 साल में तैयार होगा। जिसके बाद इसमें इंडस्ट्रीयल ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। खास बात यह है कि पिनेकल इस प्लांट के साथ ही एक अन्य प्लांट भी सेक्टर-7 में बना रही है, जहां पर वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर कोच को तैयार किया जाएगा। बता दें, पिनेकल कंपनी के इन दो नए प्लांट्स के अलावा पीथमपुर में पहले से ही तीन प्लांट वर्किंग में हैं।

पतंजलि आयुर्वेद रीवा सहित विंध्य इलाके में करेगी 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट

रीवा की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बाबा रामदेव के पतंजलि ग्रुप के आचार्य बालकृष्ण ने प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने पतंजलि ग्रुप द्वारा मप्र के गेहूं की खरीदी करने की घोषणा की। आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि पतंजलि आयुर्वेद रीवा सहित विंध्य इलाके में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है। कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए। बाबा रामदेव के पतंजलि ग्रुप के आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि यहां उद्योगों की अपार संभावनाए हैं। शरबती गेंहू मप्र की पहचान है। पतंजलि यह गेहूं खरीदेगी। आचार्य बालकृष्ण ने बताया विंध्य क्षेत्र के लोग सहज सरल हैं, उनमें गजब का धैर्य भी है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मुझे लेने हरिद्वार पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि हम विंध्य के लिए किसानों की आय बढ़ाने का काम करेंगे। यहां सरसों सहित कई खाद्य पदार्थ बड़ी मात्रा में उत्पादित होते हैं। सरसों और सूरजमुखी के तेल की पूर्ति हो सकती है। पतंजलि रीवा में एक प्लांट लगाएगा। रीवा से करीब 70 किलोमीटर दूर यह प्लांट स्थापित किया जाएगा। आचार्य बालकृष्ण ने विंध्य को पर्यटन का बड़ा सेंटर बनाने की इच्छा जताई। उन्होंने आईटी पार्क बनाने की भी रूचि जाहिर की। पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। देश में इस तरह का यह पहला प्रयास है। मप्र में उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण है। यहां उद्योगपतियों के लिए निवेश की अपार संभावनाएं हैं। पतंजलि ग्रुप यहां खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा, आईटी, पर्यटन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर कार्य करने वाला है। मप्र में जब कृषि क्रांति हुई तो गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन यहां की पहचान बन गया है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए पतंजलि ग्रुप गेहूं की खरीदी भी करेगा।

घुसपैठ की पिच पर जमकर लड़ाई

झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान हो गया है। इसके साथ ही जीत-हार का आंकलन का दौर शुरू हो गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए में ज्यादातर सीटों पर सीधी लड़ाई है। चुनाव में विरोधी एक-दूसरे के खिलाफ मुद्दों के कांटे बिछा रहे हैं। चुनावी रास्ते में मुद्दों को दीवार बनाकर रोकने की तैयारी है। इस चुनाव में आधी आबादी सभी दलों के केंद्र में है। इनके मुद्दे छाए हुए हैं। इंडिया गठबंधन मंईयां सम्मान योजना को लेकर आगे बढ़ा है, तो भाजपा ने गोगो दीदी योजना का पासा फेंका है। वोटरों की गोलबंदी का प्रयास हो रहा है। चुनाव की पिच पर मंईयां योजना के साथ-साथ बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है।

इस बार कभी भाजपा, झामुमो और कांग्रेस को अपने पिच पर खिला रही है, तो कभी झामुमो का प्रयास है कि वह अपने मुद्दों की जाल में एनडीए को फंसा ले। भाजपा की ओर से स्टार कैंपेनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, यूपीए के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से लेकर प्रदेश के नेताओं ने बांग्लादेशी घुसपैठ मुद्दे से चुनावी धार को मोड़ने की भरपूर कोशिश की है। वहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन सरकार की योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रही हैं। विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों की नजर ओबीसी वोटबैंक पर है। दोनों ही गठबंधन ने 27 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया है। गठबंधन ने कहा है कि झारखंड में आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। इंडिया गठबंधन ने सरना धर्म कोड को मुद्दा बनाया है। घुसपैठ के मुद्दे को केंद्र सरकार की ओर मोड़ने और लोगों को समझाने का प्रयास इंडिया गठबंधन कर रहा है। बहरहाल, विधानसभा चुनाव इन मुद्दों के इर्द-गिर्द ही घूम रहा है। मुद्दों की सवारी कर रहे पार्टियों का नफा-नुकसान चुनाव परिणाम ही बताएगा। पिछले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने आरक्षण को मुद्दा बनाया था। इंडिया गठबंधन ने यह नैरेटिव चलाया कि भाजपा की सरकार आएगी, तो आरक्षण खत्म कर देगी। भाजपा इस मुद्दे को सेफ ही करती रही। कहीं-कहीं इंडिया गठबंधन को इसका फायदा मिलने की बात भी कही जा रही है। इधर भाजपा ने इस बार रणनीति अपनायी है कि इसका जोरदार काउंटर करना है। चाईबासा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को ही घेरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शुरू से आरक्षण के विरोध में रही है। आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर ये अपने वोटबैंक को देंगे। झामुमो छोड़कर भाजपा का दामन थाम चुके झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का कहना है कि चुनाव के बाद जमीन वापस लेने के लिए आदिवासी बड़ी अदालतें बुलाएंगे, केंद्र और राज्य की एजेंसियां हमारी मदद करें या नहीं। चंपाई सोरेन ने कहा, चार साल पहले संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में पता चला था। हमारे विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने घुसपैठियों द्वारा आदिवासी महिलाओं को काटे जाने का मामला उठाया था। उन्होंने कहा, मंत्री के रूप में मेरे पास सीमित शक्तियां थीं। मुख्यमंत्री के तौर पर मैंने प्रशासन से इस पर डेटा इकट्ठा करने को कहा था। चंपाई सोरेन ने कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद आदिवासी ग्राम सभाएं बड़ी अदालतें लगाएंगी और बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा हड़पी गई जमीनें वापस लेंगी। उन्होंने कहा कि जमताड़ा जैसे इलाके अपराध का केंद्र बन गए हैं। चंपाई सोरेन झारखंड चुनाव की हॉट सीट सरायकेला से चुनाव मैदान में हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कोल्हान रीजन की कमान संभालते आए चंपाई इस बार भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं।

झारखंड चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया था। संकल्प पत्र जारी करने के बाद उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया और हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, बल्कि झारखंड का भविष्य सुरक्षित करने का चुनाव है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार झारखंड की अस्मिता- रोटी, बेटी, माटी को बचाने में विफल रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव में संथाल परगना सेंटर पॉइंट बन गया है। आदिवासी अस्मिता की पिच पर लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाने के बाद विपक्षी भाजपा अब सत्ताधारी झामुमो पर सीता सोरेन और चंपाई सोरेन के अपमान का आरोप लगाते हुए हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह और निशिकांत दुबे सहित भाजपा के तमाम नेता बेटी, रोटी और माटी की रक्षा में हेमंत सोरेन सरकार को विफल बताते हुए डेमोग्राफी में बदलाव के लिए इंडिया ब्लॉक की सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं। डेमोग्राफी में बदलाव की बात आती है तो सबसे अधिक चर्चा संथाल परगना की होती है। संथाल परगना की गोड्डा सीट से सांसद निशिकांत दुबे इस मुद्दे को संसद में भी उठा चुके हैं। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भी घुसपैठियों को झारखंड की सीमा से बाहर निकालने का वादा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक रैली में कहा, घुसपैठिए आपकी बेटियों को छीन रहे हैं, जमीन हड़प रहे हैं और आपकी रोटी खा रहे हैं। झारखंड की डेमोग्राफी बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में अब बात इसे लेकर भी हो रही है कि मुद्दों में कोल्हान और कोयलांचल जैसे क्षेत्र भी हैं लेकिन संथाल परगना ही पक्ष-विपक्ष का मुख्य अखाड़ा क्यों बन गया है?

● **रजनीकांत पारे**

संथाल परगना क्यों बना मुख्य अखाड़ा?

झारखंड विधानसभा की कुल स्ट्रेंथ 81 सीटें हैं। संथाल परगना में 18 विधानसभा सीटें हैं। 18 सीटों वाला यह परगना झारखंड सरकार की अगुवाई कर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का परगना है। सीएम हेमंत सोरेन जिस बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वह भी संथाल परगना में ही है। झारखंड की सत्ता निर्धारित करने में यह परगना अहम भूमिका निभाता है और यह भी एक वजह है कि हर दल का फोकस संथाल जीतने पर रहता है।सत्ताधारी गठबंधन के लिए शिबू सोरेन का गृह क्षेत्र होने के कारण संथाल की सीटें नाक का सवाल बन गई हैं। बीजेपी भी प्रतिद्वंद्वी को उसके घर में, गढ़ में ही घेरने की रणनीति पर चल रही है। सूबे की आबादी में सबसे बड़े वर्ग आदिवासी समाज की आबादी में भी सबसे अधिक भागीदारी संथाल जनजाति की है। संथाल जनजाति का बड़ा हिस्सा संथाल परगना में निवास करता है और यहां के सियासी मिजाज का संदेश धनबाद-गिरीडीह के इलाके में रहने वाले संथाल मतदाताओं को भी प्रभावित करता है। हेमंत सोरेन खुद भी संथाल जनजाति से ही हैं।

मुफ्त, मुफ्त, मुफ्त... चुनाव आते ही किसी क्लीयरेंस सेल जैसा माहौल बन जाता है। रस्ते का माल सस्ते में की तर्ज पर राजनीतिक पार्टियां वादे पर वादा करती जाती हैं और अब तो ज्यादातर पार्टियां सरकार बनते ही उन वादों को पूरा करने में भी जुट जाती हैं। कई दशक पहले दक्षिणी राज्यों से शुरु हुआ यह सिलसिला अब करीब-करीब पूरे देश में फैल चुका है। चमत्कारी बात यह है कि हरेक पार्टी ऐसे वादे करती है और दूसरे पर उंगली उठाने का कोई मौका भी नहीं चूकती।

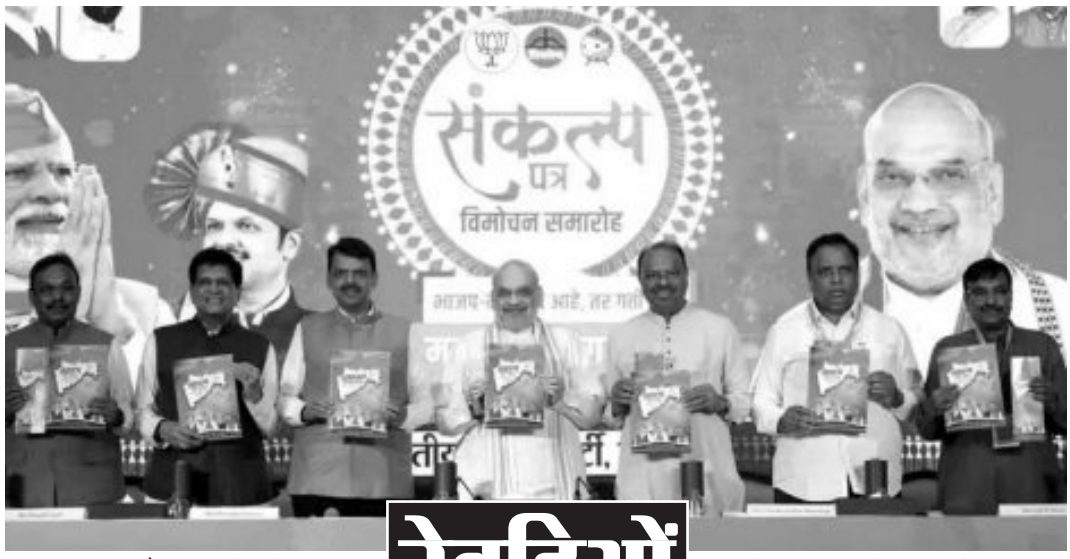

रेवड़ियों का चुनाव

महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने चुनावी रेवड़ियों की बरसात कर दी है। आमतौर पर मुफ्त की रेवड़ी वाली राजनीति से परहेज करने वाली भाजपा ने झारखंड और महाराष्ट्र में इसी तरीके को अपनाया है। हरियाणा की तरह ही भाजपा ने झारखंड और महाराष्ट्र में भी कई लोकलुभावन वादे किए हैं। भाजपा ने हरियाणा में जमकर वादे किए और सत्ता की हैट्रिक लगाने में कामयाब रही। हरियाणा के लिए भगवा दल ने 20 सूत्रीय संकल्प पत्र जारी किया था। हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मप्र में भाजपा ने आधी आबादी यानी महिलाओं को लुभाने के लिए वादे किए और सत्ता पाने में कामयाब रही। इसी तरीके से उसे ताजा सफलता अब हरियाणा में मिली है। इससे अभिभूत भाजपा अब झारखंड में भी पांच वादे कर रही है। इसके तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपए, सभी परिवारों को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, 5 साल में 28 लाख 87 हजार रोजगार, स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को 2 हजार रुपए का मासिक भत्ता और सभी को आवास देने के वादे किए गए हैं। हालांकि, घोषणा पत्र अभी नहीं आया है। यहां रोचक बात यह है कि दूसरे राजनीतिक दलों की घोषणाओं को मुफ्त की रेवड़ी बताने वाली भाजपा अपनी घोषणाओं को मुफ्त की रेवड़ी नहीं, बल्कि जनकल्याण का नाम दे रही है। पार्टी ने वैसे तो अभी झारखंड के लिए अपना आधिकारिक मेनिफेस्टो तो जारी नहीं किया है, लेकिन भगवा दल ने अपने कुछ वादों को सार्वजनिक करना शुरू कर दिया है। इसी तरह की घोषणाएं महाराष्ट्र में भी की गई हैं।

अभी झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव गर्मी पकड़ ही रहा था कि एक बार फिर यह किस्सा खुल गया। मजे की बात यह है कि इस बार वाद-विवाद की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के एक बयान से हुई और वह भी कांग्रेस की सरकार वाले राज्य कर्नाटक में। खरगे के बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लपक लिया और फिर कांग्रेस के नेता भी खुलकर मैदान में उतर गए। शुरुआत इस बात से हुई कि कर्नाटक सरकार महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा देने वाली शक्ति योजना खत्म करने जा रही है। खरगे के सवाल उठाते ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने तुरंत उन्हें दुरुस्त किया और कहा कि योजना की समीक्षा की बात हुई है, खत्म करने की नहीं। लेकिन यह बात खुले मंच से हुई, जहां पूरे प्रदेश का मीडिया मौजूद था। खरगे ने एक तरह से राज्य के नेताओं को फटकार लगाई और कहा कि उन्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, जिनका दूसरी पार्टियां फायदा उठा सकें। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि राज्य का बजट देखकर ही गारंटी देनी चाहिए। अगर आप बजट से ज्यादा की गारंटी दे देंगे, तो दिवालिया हो जाएंगे। सड़क बनाने के लिए मिट्टी तक नहीं मिलेगी और लोग आपको दोष देंगे। उनका यह बयान झारखंड व महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए था। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस राज्यों के बजट का अध्ययन करेगी और उसके हिसाब से ही ऐलान किया जाएगा कि क्या गारंटी दी जाएगी।

खरगे की इस बात से किसी को क्या ऐतराज हो सकता है? जो भी सुनेगा, यही कहेगा कि समझदारी की बात है, राजनीतिक दलों को ऐसा ही करना चाहिए। मगर राजनीति ऐसे तो चलती नहीं है। भाजपा ने बात पकड़ ली और खुद

आप ने शुरु की थी मुफ्त की रेवड़ी वाली राजनीति

बता दें कि मुफ्त की रेवड़ी वाली राजनीति की शुरुआत आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से की थी। बाद में ऐसे ही वादे कांग्रेस ने कर्नाटक और हिमाचल में किए। जिसकी वजह से इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बाद भाजपा ने मप्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुफ्त की गारंटियां देकर तीनों राज्यों में अपनी सरकार बनाने में सफलता पाई। अभी हाल ही में हरियाणा में भाजपा ने सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 90 सीटों वाले राज्य में भाजपा ने 48 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस 37 सीटें ही जीत पाई। एक ओर जहां कांग्रेस हार के कारणों की समीक्षा कर रही है, वहीं भाजपा अब झारखंड और महाराष्ट्र की सत्ता में आने के लिए लोक लुभावन वादों की सूची तैयार कर रही है।

प्रधानमंत्री मैदान में आ गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गलत वादे करके बेनकाब हो गई है। इसके साथ ही भाजपा ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि सिद्धारमैया सरकार ने कर्नाटक की माली हालत खस्ता कर दी है और सरकार के पास वादे पूरे करने के लिए पैसे नहीं हैं। हालांकि, कांग्रेस की तरफ से इसका खंडन हो रहा है, लेकिन बाकी देश में यह विवाद छिड़ गया है कि चुनावी वादे जनता की भलाई के लिए हैं या फिर वोट जुटाने के लिए रेवड़ी बांटने की कवायद है?

और फिर महाराष्ट्र चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी, यानी कांग्रेस गठबंधन की तरफ से पांच गारंटियों का ऐलान भी हो गया। खुद राहुल गांधी ने यह ऐलान किया। इनमें महिलाओं के लिए तीन हजार रुपए महीने का भुगतान और महिलाओं व बच्चियों के लिए मुफ्त बस सेवा देने वाली महालक्ष्मी योजना पहली गारंटी है। दूसरी गारंटी है- किसानों के लिए तीन लाख रुपए तक की कर्जमाफी और कर्ज चुकाने वाले किसानों को पचास हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि। इसे कृषि समृद्धि कहा गया है। तीसरी गारंटी है- राज्य में जातिगत गणना और आरक्षण में 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने का ऐलान। चौथी गारंटी है- 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त दवाएं। पांचवां वादा है- बेरोजगार नौजवानों को प्रतिमाह चार हजार रुपए तक की सहायता। मानना चाहिए कि कांग्रेस और उसके साथी दलों ने महाराष्ट्र का बजट पढ़कर ही ये वादे किए होंगे, लेकिन यह सवाल तो उठेगा कि इनमें से कितने वादे पूरे हो पाएंगे और क्या जनता इन पर भरोसा करेगी? यहां यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस के वादों पर सवाल उठाने वाली भाजपा भी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की माझी लाडकी बहीण योजना पर जबर्दस्त जोर दे रही है।

ये चुनावी वादे हैं या रेवड़ी, यह सवाल दो साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही खड़ा किया था, जब कांग्रेस ने कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के चुनावों में भी महिलाओं और नौजवानों के लिए ऐसे ही वादे किए थे। हिमाचल में कांग्रेस ने दस चुनावी वादे किए थे। तीनों जगह महिलाओं और नौजवानों को लुभाने के लिए उन्हें हर महीने भत्ता देने का वादा हुआ। कह सकते हैं, पार्टी को इसका फायदा भी मिला। लेकिन तेलंगाना में केसीआर और आंध्र में जगन मोहन रेड्डी अपनी सरकारों की कल्याणकारी योजनाएं गिनाते रह गए और वोटरों ने उनका साथ नहीं दिया। जबकि मप्र में भाजपा की जीत में ऐसी ही योजना की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। राज्यों के चुनाव को छोड़ भी दें, तो देश की राजनीति में किसान सम्मान योजना, मुफ्त रसोई गैस, मुफ्त शौचालय, मुफ्त घर और मुफ्त अनाज योजना ने जो भूमिका निभाई है, उसे भला कैसे नजरअंदाज करेंगे?

नोबेल विजेता अर्थशास्त्री भी अब कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में सबके लिए काम जुटाना संभव नहीं होगा, ऐसे में सरकारों को न सिर्फ गरीबों को मदद देने, बल्कि बिना उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए मदद का इंतजाम करना पड़ेगा। केंद्र या राज्य सरकारों के हाल देखें, तो वे मदद पहुंचाने में अपना भी राजनीतिक फायदा देख पा रही हैं। सम्मान का सवाल अभी केंद्र में आ नहीं पाया है। ऐसी परिस्थिति में लखनऊ के मशहूर नवाब आसिफुद्दौला की याद लाजिमी है, जिन्होंने 18वीं सदी में अकाल पीड़ित जनता को राहत देने के लिए इमामबाड़ा जैसी बड़ी इमारत बनवाई थी। इसमें हजारों लोगों को काम दिया गया, ताकि लोग मेहनत करके पैसा कमा सकें, उन्हें खैरात लेने की जिल्लत न झेलनी पड़े। तभी से यह जुमला प्रसिद्ध है जिसको न दे मौला, उसको दे आसिफुद्दौला। क्या आज इसी अंदाज में राहत देना संभव नहीं रह गया है? काम के बदले अनाज और मनरेगा जैसी योजनाओं को मजबूत करना क्या बेहतर तरीका नहीं होगा? इस सवाल का जवाब सिर्फ सरकारों और राजनेताओं को नहीं, बल्कि उन्हें कुर्सी तक पहुंचाने वाले वोटरों को भी देना होगा।

चुनाव के समय में सरकार बनाने के लिए पार्टियां दे दनादन घोषणाएं करती हैं। लेकिन जब उन पर अमल करने की बारी आती हैं तो सरकारों के पसीने छूटने लगते है। केवल कर्नाटक सरकार को ही अपनी पांच गारंटियां पूरा करना कठिन नहीं हो रहा है। ऐसी ही कठिनाई हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भी पेश आ रही है। इसका कारण यह है कि कांग्रेस ने इन दोनों राज्यों में चुनाव जीतने के लिए रेवड़ियां बांटने वाले ऐसे वादे किए, जिन्हें पूरा करना संभव नहीं था। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि कांग्रेस अध्यक्ष यह जताते दिख रहे हैं कि उन्हें रेवड़ी संस्कृति रास नहीं आ रही और वह इस पक्ष में हैं कि चुनावी वादे करते समय आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा जाए, क्योंकि वह खुद बढ़-चढ़कर लोक-लुभावन वादे करते रहे हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने यकायक यह घोषणा कर दी थी कि यदि हम सत्ता में आए तो गरीब परिवारों को दस किलो मुफ्त अनाज देंगे, जबकि ऐसी किसी योजना का कांग्रेस के घोषणापत्र में कोई उल्लेख नहीं था। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस की ओर से लोक-लुभावन वादे किए जा रहे हैं। प्रश्न यह है कि क्या ये वादे इन राज्यों की वित्तीय स्थिति का आंकलन करके किए जा रहे हैं?

● **विपिन कंधारी**

लोक-लुभावन घोषणाओं के दुष्परिणाम

बिना सोचे-समझे लोकलुभावन घोषणाएं करने के क्या दुष्परिणाम होते हैं, इसका पता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से अपने दल के नेताओं को दी गई इस नसीहत से चलता है कि बिना विचारे कोई घोषणा न करें और जो घोषणा करें, वह बजट के हिसाब से करें। उन्होंने इस तरह की घोषणाओं के खतरे रेखांकित करते हुए यह भी कहा कि वादे पूरे न करने वाली घोषणाओं से बदनामी भी होती है और राजनीतिक नुकसान भी। कांग्रेस अध्यक्ष को यह सब इसलिए कहना पड़ा, क्योंकि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कुछ दिन पहले यह कह दिया था कि राज्य सरकार महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने वाली शक्ति योजना पर नए सिरे से विचार करेगी। इससे यही ध्वनित हुआ कि यह योजना बंद की जा सकती है, क्योंकि कर्नाटक सरकार अपनी पांच गारंटियों को पूरा करने के फेर में आर्थिक संकट का सामना कर रही है। डीके शिवकुमार के कहने का मतलब कुछ भी हो, लेकिन मल्लिकार्जुन खरगे ने जिस तरह उन्हें फटकार लगाई और यहां तक कह दिया कि क्या आप अखबार नहीं पढ़ते, उससे तो यह भी लगता है कि उनके और शिवकुमार के बीच सबकुछ ठीक नहीं है। यह सामान्य बात नहीं कि कांग्रेस अध्यक्ष अपनी ही राज्य सरकार के उपमुख्यमंत्री की सार्वजनिक रूप से खिंचाई करें। यह ठीक है कि खरगे की खरी-खोटी के बाद डीके शिवकुमार ने सफाई देते हुए कहा कि शक्ति योजना को बंद करने का कोई इरादा नहीं और केवल उसकी समीक्षा की जाएगी।

कोई भी राजनीतिक गठबंधन हो, उसमें कुछ न कुछ खींचतान बनी ही रहती है। यह खींचतान तब और बढ़ जाती है, जब चुनाव आ जाते हैं। इन दिनों महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों के चलते पक्ष-विपक्ष के गठबंधनों के बीच आपसी खींचतान देखने को मिल रही है, लेकिन यह स्पष्ट ही है कि एनडीए के मुकाबले विपक्षी दलों के मोर्चे इंडिया गठबंधन में वह कुछ ज्यादा ही है। इसका कारण यह है कि जहां भाजपा के सहयोगी दल उसकी राजनीतिक जमीन पर कब्जा करके नहीं उभरे, वहीं कांग्रेस के सहयोगी दल उसके ही वोट बैंक में सेंध लगाकर मजबूत हुए हैं।

एक-दूजे की जड़ें काटने वाले सहयोगी

दो राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों की 48 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में टिकट के बंटवारे को लेकर राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन की गांठ बढ़ गई है। खासकर इंडिया गठबंधन में यह अधिक दिख रहा है। इसी कारण उप्र के उपचुनावों में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच खींचतान हुई। दोनों में विधानसभा की नौ सीटों के उपचुनावों के लिए भी सहमति कायम नहीं हो सकी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस को नौ में से केवल दो सीट देने की पेशकश की। ये भी वे सीटें थीं, जहां से कांग्रेस के जीतने की संभावना स्याह थी। जोखिम देखकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि यदि वह ये सीटें हार जाती तो भविष्य में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का उसका दावा कमजोर हो जाता। कांग्रेस ने सपा की पेशकश ठुकराते हुए यह दिखाया कि वह गठबंधन की एकजुटता के लिए त्याग कर रही है। कांग्रेस ने त्याग नहीं किया, बल्कि मजबूरी में उपचुनाव लड़ने से मना किया, यह अखिलेश यादव के इस बयान से स्पष्ट हो गया कि राजनीति में कोई त्याग नहीं करता। उन्होंने यह बयान महाराष्ट्र में पांच सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोकते हुए किया।

सपा ने चेताया है कि यदि उसे महाविकास आघाड़ी ने पांच सीटें नहीं दीं तो वह 25 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार देगी। वह ऐसा कर भी सकती है, क्योंकि मप्र में जब कांग्रेस ने उसे एक अकेली सीट भी नहीं दी थी तो उसने अपने 22 प्रत्याशी उतार दिए थे। कांग्रेस ने हरियाणा में भी सपा को कोई सीट नहीं दी थी। हरियाणा में वह आम आदमी पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ने के संकेत देकर पीछे हट गई थी। इसका उसे नुकसान अवश्य हुआ, लेकिन उसका यह फैसला उचित ही था, क्योंकि यदि वह आप से समझौता करती तो वह उसे हरियाणा में अपने वोट बैंक में सेंध लगाने का ही मौका देती। कांग्रेस ने ऐसा करके ही एक के बाद एक राज्यों में अपनी राजनीतिक जमीन खोई है और आज उप्र, बिहार समेत कई ऐसे राज्यों में तीसरे-चौथे नंबर का दल बनकर रह गई है, जहां कभी वह प्रमुख दल हुआ करती थी।

यह कहना-मानना निरा झूठ है कि सपा, राजद, जदयू, झामुमो, राकांपा, शिवसेना-यूबीटी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी आदि जो अनेक दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, वे कांग्रेस के स्वाभाविक सहयोगी हैं। ये सभी दल कांग्रेस विरोध की पैदाइश हैं और वस्तुत: एक-दूजे के स्वाभाविक विरोधी हैं। संविधान और आरक्षण बचाने का थोथा नारा लगाकर वे स्वाभाविक विरोध के इस सच को छिपा नहीं सकते। सहयोगी दलों ने कांग्रेस के कोर वोट बैंक को हड़पकर ही अपना अस्तित्व बनाया है। ये नहीं चाहेंगे कि उनके सहयोग-समर्थन से कांग्रेस फिर से मजबूत हो। सपा के दृष्टिकोण से देखें तो उसने उप्र उपचुनाव में कांग्रेस को महत्व न देकर ठीक ही किया। उप्र में कांग्रेस तभी मजबूत हो सकती है, जब सपा का कुछ वोट बैंक उसके हिस्से में आए। आखिर ऐसे में सपा यह क्यों चाहेगी कि कांग्रेस फिर सशक्त हो। वह यह अच्छे से जानती है कि उसने अपनी राजनीतिक जमीन कांग्रेस के कोर वोट बैंक पर कब्जा करके ही बनाई है। यदि कांग्रेस की भागीदारी वाला महाविकास आघाड़ी सपा को कोई सीट देने के लिए तैयार नहीं तो उसके नजरिए से यह उचित ही है। जब कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना-यूबीटी को एक-दूसरे से सामंजस्य बैठाने में पहले से ही अपनी राजनीतिक जमीन पर सिमटना पड़ रहा है, तब फिर उन्हें एक और नया साझेदार बनाकर अपनी समस्या क्यों बढ़ानी चाहिए?

यदि कांग्रेस यह चाह रही है कि वह अपने सहयोगी दलों से अपना वोट बैंक छीने और यदि फिलहाल यह न कर सके तो कम से कम उनके

जाति जनगणना कितनी प्रभावी?

सपा की ओबीसी पर निर्भरता तीन कारणों से भ्रामक है। एक, मोदी अब ओबीसी नेता के रूप में स्थापित हो गए हैं। इसकी अनदेखी नहीं हो सकती कि भाजपा ने डॉ. मोहन यादव (मध्य प्रदेश), नायब सिंह सैनी (हरियाणा), भूपेंद्र पटेल (गुजरात) आदि ओबीसी मुख्यमंत्रियों को प्राथमिकता दी है। दूसरा, सपा ओबीसी केंद्रित होने का दावा करती है, मगर उसकी छवि मुख्यत: यादवों को प्रमुखता देने वाली पार्टी की है। भाजपा ने समावेशी दृष्टिकोण दिखाते हुए नेतृत्व और सत्ता संरचना में यादवों सहित सभी पिछड़ों को प्रतिनिधित्व दिया है। इसका उदाहरण टिकट वितरण, पार्टी-पदों और मंत्रियों की नियुक्ति में दिखता है। तीसरा, सपा जाति जनगणना की मांग को अपना ट्रंप कार्ड समझती है, पर यदि जाति जनगणना हुई तो उसके लिए दांव उलटा पड़ सकता है, क्योंकि आरक्षण लाभ से वंचित ओबीसी उपजातियां प्रकट हो जाएंगी। रोहिणी आयोग के अनुसार लगभग 37 प्रतिशत ओबीसी जातियों का सरकारी नौकरियों में शून्य प्रतिनिधित्व है। जाति जनगणना से सामाजिक न्याय का जो लोकतंत्रीकरण होगा, उससे सपा और इस जैसे दलों को नुकसान हो सकता है। अखिलेश पीडीए प्रयोग को उपचुनावों में और आगे भी दोहराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उपचुनावों में विजेता कौन होगा, यह तो समय बताएगा, लेकिन अखिलेश द्वारा योगी सरकार को कड़ी चुनौती देने से सरकार जनता के दरवाजे पर आ गई है, जो प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकती है।

विस्तार को रोके तो यह गलत नहीं है। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में गुजरात में आप से समझौता कर राजनीतिक आत्मघात ही किया था। उसने हरियाणा में आप को भाव न देकर गुजरात वाली गलती को ठीक करने का ही काम किया। इस पर भी हैरानी नहीं कि झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आपस में सीटें बांट लीं और राजद को ठेंगा दिखा दिया। ऐसा करके इन दोनों दलों ने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि एक तो राजद की झारखंड में कोई राजनीतिक हैसियत नहीं और दूसरे, वह यहां कांग्रेस एवं झामुमो के वोट बैंक में ही सेंध लगाता। अब यह तय सा है कि जब बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे तो राजद इसका बदला लेगा और कांग्रेस को कम से कम सीटें देगा। वैसे भी वह पिछली बार उसे 70 सीटें देकर अब तक पछता रहा है। राजद यह भी जानता है कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने का मतलब होगा, उसे अपने वोट बैंक में साझेदार बनाना और फिर से मजबूत होने का मौका देना। यदि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल एक-दूसरे की जड़ें काटने की ताक में रहते हैं तो यह इंडिया गठबंधन की प्रकृति के कारण। एक-दूसरे को हाशिये पर ठेलना इस गठबंधन के घटकों की नियति है। जो दल इसकी कोशिश नहीं करेगा, वह अपने लिए खतरा ही पैदा करेगा। इस गठबंधन के घटकों में यदि कोई साझा तत्व है तो वह है एक-दूसरे की राजनीतिक जमीन पर कब्जा करना।

महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों के साथ देश की निगाह उप्र में होने वाले नौ विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर भी है। पिछले लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित बढ़त से उत्साहित विपक्ष जाति जनगणना पर बल देने के साथ संविधान और आरक्षण बचाने पर भी जोर देने में लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव उपचुनावों में पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अपनी सफलता दोहराना चाहते हैं। सपा का जनाधार 2019 लोकसभा में 17.96 से बढ़कर 2022 विधानसभा चुनावों में 32.06 और 2024 लोकसभा में 33.59 प्रतिशत हो गया। 2019 में पांच सीटों के मुकाबले सपा ने 2024 में 37 लोकसभा सीटें जीतीं। क्या इसका श्रेय पीडीए को दिया जा सकता है? क्या यह उपचुनावों में और आगे भी सफलता दिलाएगा? 2017 में सपा अध्यक्ष बनने के बाद अखिलेश ने गठबंधन राजनीति में नए-नए प्रयोग किए हैं। पीडीए उनकी नवीनतम सोशल इंजीनियरिंग है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने बीती सदी के सातवें दशक में अजगर (अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत), फिर मजगर (मुस्लिम, अहीर/यादव, जाट, गुर्जर, राजपूत) का प्रयोग किया। मुलायम सिंह ने एम-वाई (मुस्लिम-यादव) की राजनीति की, जबकि अखिलेश ने 2022 में गुर्जर, अहीर, जाट, ब्राह्मण समीकरण का प्रयोग किया। उनका पीडीए अभी तक का सफलतम प्रयोग रहा। अखिलेश ने 2017 में राहुल गांधी के साथ गठबंधन कर उप्र के दो लड़के का असफल प्रयोग किया।

साल-दर-साल बदलती राजनीति

2019 लोकसभा चुनावों में उन्होंने धुर विरोधी बसपा सुप्रीमो मायावती से हाथ मिलाया, पर उनकी सीटें घटकर पांच रह गईं। 2022 विधानसभा चुनावों में उन्होंने छोटे-छोटे दलों जैसे रालोद, महान दल, अपना दल (कमेरावादी), सुहेलदेव पार्टी आदि के साथ असफल गठबंधन किया। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने पुनः राहुल के साथ हाथ मिलाया, जो सफल रहा। उन्हें 33.59 प्रतिशत वोट और 37 लोकसभा सीटें मिलीं, पर इसका असली श्रेय उस झूठे विमर्श को जाता है, जिसे अखिलेश-राहुल ने दलितों और ओबीसी के सामने रखा कि भाजपा का अबकी बार 400 पार का नारा बाबासाहेब के संविधान को ध्वस्त करने और आरक्षण खत्म करने के उद्देश्य से है। इसका असर पड़ा। इसलिए और भी, क्योंकि भाजपा ने इस विमर्श को हल्के में लिया। अखिलेश का पीडीए प्रयोग संविधान और आरक्षण विमर्श के अभाव में संभवतः सफल नहीं होता, क्योंकि सामाजिक संरचना में तर-ऊपर होने से दलितों और पिछड़ों के सामाजिक संबंध तनावपूर्ण हैं। दलित ज्यादातर भूमिहीन मजदूर हैं, जो ओबीसी भू-स्वामियों के खेतों पर श्रम करते हैं और प्रायः आर्थिक शोषण सहते हैं। यह सामाजिक आर्थिक शोषण दलितों और ओबीसी को एक राजनीतिक मंच पर आने से रोकता है। इसीलिए जब अखिलेश ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती के साथ गठबंधन किया, तब भी दलितों ने सपा को वोट नहीं किया था और सपा को इसका नुकसान उठाना पड़ा था।

अखिलेश अपनी सोशल इंजीनियरिंग से विभिन्न सामाजिक घटकों को जोड़कर अस्मिता की राजनीति कर रहे हैं, जबकि मोदी-योगी की भाजपा ने आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए विकास, कल्याण और शासन की त्रिवेणी से हर वर्ग तक पहुंचने की समावेशी राजनीति का एक नया मार्ग अपनाया है। लोकसभा चुनाव परिणाम ने दिखाया कि योगी-मोदी सरकार की बेहतर कानून-व्यवस्था, विकास और जन-कल्याणकारी शासन के दावे अखिलेश-राहुल के झूठे विमर्श के आगे टिक न सके। उपचुनावों में योगी सरकार इसकी पुनरावृत्ति रोकने का प्रयास कर रही है। अखिलेश के लिए उपचुनावों में पीडीए प्रयोग दोहराना आसान नहीं। अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम सपा के साथ रहेंगे, लेकिन अखिलेश के लिए दलितों को रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि एक तो सामाजिक आर्थिक कारणों से दलित-ओबीसी साथ-साथ नहीं रह सकते, दूसरे उपचुनावों में मायावती की वापसी हुई है और कांग्रेस ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है।

लोकसभा चुनाव में मायावती के उदासीन होने से दलितों को कहीं भी जाने का विकल्प मिल गया था। उन्होंने संविधान और आरक्षण मुद्दे पर सपा को चुना। नगीना सांसद चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी भी चुनाव मैदान में है। आज दलितों के पास कई विकल्प हैं। उन्हें अखिलेश-राहुल के झूठे विमर्श का भी आभास है। अगर दलित सपा से दूर जाते हैं तो उसका वोट शेयर 28 प्रतिशत पर गिर सकता है, जबकि पिछले कई चुनावों से भाजपा 40 प्रतिशत से अधिक वोट शेयर पर मजबूती से टिकी हुई है। यह पीडीए की सफलता पर ब्रेक लगा सकता है। त्रिकोणीय मुकाबले में 40 प्रतिशत एक सशक्त जनाधार है। मायावती ने 2007 में मात्र 30 प्रतिशत और अखिलेश ने 2012 में 29 प्रतिशत वोटों पर सरकार बनाई थी।

● **इन्द्र कुमार**

309 दिन में 189 नक्सली ढेर

छत्तीसगढ़ के बस्तर में इस साल 1 जनवरी से 5 नवंबर तक पुलिस और नक्सलियों के बीच कुल 96 मुठभेड़ हुई है। इन 309 दिनों में अलग-अलग जिलों में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 9 करोड़ 72 लाख रुपए के कुल 189 नक्सलियों को ढेर किया है। इनमें 5 दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी कैडर के भी नक्सली शामिल हैं। मारे गए नक्सलियों से पुलिस ने एके-47, एसएलआर और इंसास जैसे कुल 207 हथियार भी बरामद किए हैं। ये हथियार नक्सलियों ने अलग-अलग मुठभेड़ों के बाद जवानों से ही लूटे थे। राज्य गठन होने के बाद बस्तर के नक्सल इतिहास में यह पुलिस की सबसे बड़ी सफलता वाला साल रहा है। इस साल पुलिस ने नक्सली कमांडर हिड़मा के इलाके पूवर्ती समेत नक्सलियों के सबसे सुरक्षित ठिकानों में से एक अबूझमाड़ के जंगलों में कुल 22 नए कैंप खोले हैं। अबूझमाड़ जिसे नक्सलियों की राजधानी और इनका अभेद किला कहा जाता है यहां भी अंतिम छोर तक पुलिस की पैठ बढ़ी है। नक्सलियों के इलाके में घुसकर उनका एनकाउंटर किया गया है।

बस्तर में नक्सली मार्च से जून तक अपना टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन मनाते हैं। इस दौरान बड़े हमले करते हैं। ताड़मेटला, रानीबोदली, बुरकापाल में जवानों को एंबुश में फंसाकर मारना और अरनपुर में आईईडी ब्लास्ट कर जवानों से भरी वाहन को उड़ाना इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन इस बार नक्सलियों के टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन महीने में पुलिस फोर्स इन पर भारी पड़ी है। पुलिस ने अटैकिंग मोड पर काम किया और संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च कर नक्सलियों को घेरकर मारा है। इसी तरह मानसून में भी जवानों का ऑपरेशन जारी रहा। अंदरूनी इलाकों में नदी-नाले पार कर जवान नक्सलियों के ठिकाने में घुसे। कैंप को ध्वस्त किया। हथियार, सामान बरामद किए और नक्सलियों को ढेर कर उनके शवों को भी लेकर आए। इस साल 5 बड़े कैडर के नक्सलियों को भी मारा गया है, इनमें नीति उर्फ निर्मला, रूपेश, रणधीर और जोगन्ना समेत अन्य शामिल हैं। ये सभी 25-25 लाख रुपए के इनामी नक्सली थे। इसके अलावा डीवीसीएम, एसीएम, एलओएस, प्लाटून कमांडर, पीएलजीए सदस्य जैसे कैडर्स को भी मार गिराया है।

छत्तीसगढ़ के बस्तर के अलग-अलग जिलों के 22 अंदरूनी गांवों में सुरक्षाबलों का कैंप स्थापित किया गया है। कैंप स्थापित होने के बाद इन पूरे गांव की तस्वीर बदलनी शुरू हो गई है। इनमें से 13 गांवों में आजादी का जश्न भी मनाया गया है। इनमें दंतेवाड़ा के नेरली घाटी, कांकेर के पानीडोबरी, बीजापुर के गुंडम, पुतकेल, छुटवही, नारायणपुर के कस्तूरमेटा, इरकभट्टी, मसपुर, मोहंदी, सुकमा के मुलेर, परिया, सलातोंग, टेकलगुडेम, पूवर्ती, लखापाल पुलनपाड़ शामिल हैं। बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बड़े कैडर्स को मारने में भी सफलता मिली है। हमारी नक्सलियों से अपील है कि वे नक्सल संगठन छोड़ दें और मुख्य धारा में लौट आएं।

प्रदेश में सक्रिय नक्सलियों की संख्या कम हो रही है। अब युवा भी इनकी ओर नहीं जा रहे हैं। बड़ी संख्या में अंदरूनी इलाकों के युवाओं का रुझान अब सेना, आईटी और दूसरे सेक्टर में बढ़ रहा है। सरकारी योजनाओं के पहुंचने से अब युवा शिक्षा के प्रति ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में नक्सलियों की भी वापसी हो रही है। वह भी सरेंडर कर रहे हैं। इसके पीछे वो अपने साथ अभद्र व्यवहार, स्वास्थ्य में कमी, परिवार बनाने और बेहतर जिंदगी देने की बात कहते हैं। नक्सलियों की संख्या कम होने की कई अन्य वजह भी हैं। नक्सलियों के बीच आपस में तालमेल न बैठने की वजह, घर बसाने और एनकाउंटर में मारे जाने के डर से सरेंडर के आंकड़े बढ़े हैं। पिछले 9 महीने में 700 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। नक्सल संगठन में नई भर्ती नहीं हो पा रही है। नक्सलियों ने फरमान जारी कर युवाओं को संगठन में भर्ती होने के लिए भी कहा था। पिछले 9 महीने में 188 नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया है। इससे पहले भी बहुत से माओवादी मारे गए हैं। बस्तर आईजी सुंदरराज पी कहते हैं- माओवादियों के खिलाफ चल रहे सभी ऑपरेशन्स में महिला कमांडो ग्राउंड जीरो में जा रही हैं। सुरक्षाबलों को नक्सलियों की पड़ताल के लिए खराब रास्ते और नालों को पार करना पड़ता है। इस दौरान जंगलों में विजिबिलिटी न के बराबर होती है। इसके बावजूद तय समय पर टारगेट को अचीव करना पड़ता है। गौरतलब है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 24 अगस्त को राजधानी रायपुर में देश से नक्सलियों के खात्मे की जो डेडलाइन तय की थी छत्तीसगढ़ सरकार धीरे-धीरे उस दिशा में आगे बढ़ रही है। शाह ने कहा था कि मार्च 2026 तक पूरा देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि नक्सली हथियार छोड़ें नहीं तो परिणाम भुगतने को तैयार रहें।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

12 किलो वजन लेकर पैदल चलती हैं महिला कमांडों

नक्सल ऑपरेशन में डीआरजी, सीआरपीएफ, एसटीएफ और बस्तर फाइटर्स के साथ दुर्गा और दंतेश्वरी फाइटर्स की महिला कमांडो भी बराबरी से मुकाबला कर रही हैं। फोर्स में एके-47 जैसे वेपन लिए महिला कमांडो हर दस्ते में दिखाई देती हैं। महिला कमांडो के पास राइफल के साथ बुलेट्स और दूसरी जरूरतों का सामान मिलाकर करीब 12 किलो का वजन होता है। कई बार उन्हें कई किमी तक यह वजन लेकर उन जगहों पर पैदल चलना पड़ता है, जहां रास्ते नहीं होते हैं। कहीं पहाड़, कहीं खेत, मेड़ और पगडंडियों से भरे रास्तों से नक्सलियों के गढ़ में घुसकर महिला कमांडो अपनी ताकत दिखा रही है। नक्सलियों के खिलाफ चल रही लड़ाई के लिए बस्तर में अलग-अलग फोर्स के करीब 60 हजार से ज्यादा जवान तैनात हैं। इनमें कांकेर में एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, नारायणपुर में आईटीबीपी, बीएसएफ, एसटीएफ, कोंडागांव में आईटीबीपी, सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं जबकि दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। इसके अलावा सभी जिलों में डीआरजी, जिला बल, बस्तर फाइटर्स, बस्तरिया बटालियन भी सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां कमर कसती हुई दिख रही हैं, जहां अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग सियासी मुकाबला बनता नजर आ रहा है। वहीं महाराष्ट्र चुनाव में असली और नकली का खेल भी देखने को मिलेगा, क्योंकि शिवसेना भी दो हैं और एनसीपी भी दो हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस बार चुनाव में कौनसी शिवसेना और कौनसी एनसीपी अपना परचम लहराकर अपने आप को असली साबित करती है।

असली बनाम नकली की जंग

महाराष्ट्र के अलग-अलग क्षेत्र में लड़ाई

महाराष्ट्र के अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग सियासी मुकाबला बनता नजर आ रहा है। प्रदेश के तीन क्षेत्रों में भाजपा बनाम शिवसेना (यूबीटी) की लड़ाई रही है। ठाणे-कोंकण बेल्ट में शिवसेना बनाम शिवसेना की फाइट है तो मुंबई और मराठवाड़ा में भाजपा की लड़ाई उद्धव की शिवसेना से है। विदर्भ और उत्तरी महाराष्ट्र में यह भाजपा बनाम कांग्रेस की लड़ाई है और पश्चिमी महाराष्ट्र में भाजपा और अजित पवार की एनसीपी बनाम शरद पवार एनसीपी की लड़ाई है। ऐसे में महाराष्ट्र की जिन सीटों पर मुकाबला शिवसेना बनाम शिवसेना का है और एनसीपी बनाम एनसीपी की लड़ाई है, उसमें जिसका पलड़ा भारी रहेगा, वो ही अलग बादशाह बनकर उभरेंगे?

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए (महायुति) और कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन (महाविकास अघाड़ी) के बीच मुख्य मुकाबला है, लेकिन असली बनाम नकली का भी चुनाव है। महाराष्ट्र के बदले सियासी समीकरण में शिवसेना और एनसीपी दो धड़ों में बंट गई। शिवसेना के एक धड़े की कमान एकनाथ शिंदे के हाथों में है तो दूसरे की बागडोर उद्धव ठाकरे के हाथ में है। इस तरह से एनसीपी भी अजित पवार और शरद पवार के बीच बंटी हुई है। इस तरह नकली शिवसेना और नकली एनसीपी बनाम असली शिवसेना और असली एनसीपी की है।

शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी का भाजपा के साथ गठबंधन है जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) और शरद पवार की एनसीपी (एस) का कांग्रेस के साथ गठबंधन है। नामांकन खत्म होने के साथ ही महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर साफ हो गई है। राज्य की 47 विधानसभा सीटों पर शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई है तो 36 सीटों पर एनसीपी बनाम एनसीपी का मुकाबला है। इन सीटों पर दोनों ही खेमों ने पूरी ताकत लगा दी है और सत्ता का भी फैसला इन्हीं सीटों से ही होगा? महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन के तहत एकनाथ शिंदे के अगुवाई वाली शिवसेना 82 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से 47 सीटों पर शिवसेना की लड़ाई उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) के उम्मीदवारों से है और बाकी 35 सीटों पर शिंदे के प्रत्याशियों को कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी से चुनावी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। शिवसेना बनाम शिवसेना मुकाबले वाली 47 सीटों में 16 सीटें मुबंई इलाके की हैं तो 18 सीटें कोंकण क्षेत्र की हैं। इसके अलावा मराठवाड़ा इलाके की 7 सीटों पर भी शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई है और बाकी सीटें विदर्भ, पश्चिम और उत्तर महाराष्ट्र की हैं।

शिवसेना में बंटवारे के बाद यह दूसरा चुनाव है, जब शिवसेना का मुकाबला शिवसेना के उम्मीदवार से होगा। लोकसभा चुनाव में मुंबई की तीन सीटों- मुंबई दक्षिण, मुंबई दक्षिण मध्य और उत्तर पश्चिम पर शिंदे की शिवसेना ने उद्धव के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा और सिर्फ एक ही सीट जीत सकी। इस तरह विधानसभा में मुंबई की 10, पुणे की 2 और कल्याण की 3 सीटों सहित 47 सीटों पर शिवसेना (यूबीटी) की शिंदे की शिवसेना के बीच टक्कर है। कोपरी-पचपाखड़ी और वर्ली जैसी हाई प्रोफाइल सीट भी है। वर्ली में मिलिंद देवड़ा का मुकाबला आदित्य ठाकरे से है तो मुख्यमंत्री शिंदे की सीट कोपरी-पचपाखड़ी में शिवसेना यूबीटी ने उनके गुरु आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे को उतार दिया है। शिवसेना बनाम शिवसेना (यूबीटी) के बीच मुकाबला वाली बायकुला, माहिम, जोगेश्वरी ईस्ट, मागाठाणे, कुर्ला, विक्रोली, डिंडोशी, चेंबूर, अंधेरी ईस्ट, भांडुप, शिवरी, अंबरनाथ, कल्याण वेस्ट, भिवंडी ग्रामीण, कल्याण ग्रामीण और ओवळा-माजिवडा जैसी विधानसभा सीटें हैं। इस तरह विधानसभा के चुनाव में एक निर्णायक लड़ाई, अस्तित्व की लड़ाई और यह तय करने की लड़ाई होने की उम्मीद है कि असली शिवसेना कौन है। माना जा रहा है कि हर सीट पर कड़ी टक्कर होगी और फिर सही मायनों में यह तय होगा कि असली सेना कौन है।

शिवसेना बनाम शिवसेना की तरह ही एनसीपी में अजित पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी के बीच असली बनाम नकली एनसीपी की लड़ाई है। राज्य की करीब 36 विधानसभा सीटों पर मुकाबला शरद पवार और अजित पवार के सिपाहसालारों के बीच है। राज्य में 52 सीटों पर अजित पवार की एनसीपी चुनावी मैदान में उतरी है, जिसमें 36 सीट पर उनके उम्मीदवारों को शरद पवार की एनसीपी के प्रत्याशी से फाइट करनी पड़ रही है। अजित पवार ने अपने मौजूदा 35 विधायकों को फिर से टिकट दिया तो शरद पवार ने भी अपने साथ खड़े रहने वाले सभी 15 विधायकों को उतारा है। एनसीपी बनाम एनसीपी (एस) की लड़ाई का सियासी केंद्र बारामती है, जहां पर शरद पवार ने अजित पवार के सामने उनके भतीजे योगेंद्र पवार को उतारा है। ऐसे ही पश्चिम महाराष्ट्र में इलाके की ज्यादातर सीटों पर अजित पवार के उम्मीदवारों को शरद पवार की एनसीपी के प्रत्याशी से आमना-सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में भी बारामती ही नहीं, पश्चिम महाराष्ट्र इलाके की ज्यादातर सीटों पर मुकाबला अजित पवार के एनसीपी उम्मीदवारों का शरद पवार की एनसीपी के प्रत्याशियों से हुआ था। इस लड़ाई में शरद पवार का पलड़ा भारी रहा था। अजित पवार सिर्फ एक सीट ही जीत सके थे और सात सीटें शरद पवार ने अपने नाम कर ली थी। ऐसे में अजित पवार के लिए अपने चाचा के सिपाहसालारों से मुकाबला करना आसान नहीं है।

● **बिन्दु माथुर**

पायलट या किरोड़ी की अग्निपरीक्षा

महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ-साथ चर्चा राजस्थान के उपचुनाव की भी है। 13 नवंबर को राजस्थान विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव कराए गए, लेकिन देवली-उनियारा और दौसा की सीट हॉट बनी हुई है। दोनों ही सीटों पर देश के दो दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इनमें पहला नाम है भाजपा के किरोड़ी लाल मीणा का और दूसरा कांग्रेस के सचिन पायलट का। किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान सरकार के मंत्री हैं और उनकी गिनती प्रदेश के दिग्गज नेताओं में होती है। उसी तरह पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं। हालांकि, कहा जा रहा है कि दोनों की सियासत किस तरफ यूटर्न लेगी, यह देवली और दौसा सीट के उपचुनाव से तय हो जाएगा।

टोंक जिले की देवली उनियारा पाल-मीणा बहुल है। यहां पर पाल समुदाय की आबादी करीब 12.8 प्रतिशत है। वहीं 12.7 प्रतिशत मीणा जाति के लोग इस विधानसभा में रहते हैं। गुर्जर की आबादी इस सीट पर करीब 6 प्रतिशत है। यहां 7 प्रतिशत के करीब मुस्लिम भी हैं। इसके अलावा बैरवा, सैनी, लाल जाति के लोग यहां किंगमेकर की भूमिका में रहते हैं। 2018 से इस सीट पर कांग्रेस जीतती रही है। कांग्रेस के हरीश मीणा अब टोंक सीट से सांसद बन गए हैं। हरीश मीणा की इस सीट पर अब भाजपा ने पूर्व विधायक और गुर्जर समुदाय के नेता राजेंद्र गुर्जर को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने मीणा समुदाय के कस्तूर चंद मीणा को टिकट दिया है। निर्दलीय नरेश मीणा भी यहां से मैदान में हैं। मीणा बहुल दौसा सीट पर 2018 से ही कांग्रेस का कब्जा है। यहां की 24 प्रतिशत आबादी मीणा समुदाय की है। गुर्जर यहां करीब 6 प्रतिशत हैं। इसी तरह बैरवा 10 प्रतिशत और 12 प्रतिशत आबादी ब्राह्मण बिरादरी की है। दौसा विधानसभा सीट पर मुस्लिम 4 प्रतिशत और सैनी 5 प्रतिशत है, जो जीत-हार में बड़ी भूमिका निभाता है। कांग्रेस ने यहां से दीनदयाल बैरवा को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा की तरफ से किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिया गया है। 2023 के चुनाव में भाजपा ने यहां से शंकरलाल शर्मा को सिंबल दिया था, जिसे कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा ने हरा दिया। सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा का राजनीतिक मैदान पूर्वी राजस्थान ही है। पायलट और किरोड़ी लाल मीणा दोनों ही दौसा सीट से सांसद रहे हैं। 2004 से 2009 तक सचिन पायलट दौसा से सांसद रहे हैं। 2008 में यह सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित कर दी गई। किरोड़ी यहां से चुनाव लड़कर जीत गए। हालांकि, पायलट ने दौसा का मैदान नहीं छोड़ा। वर्तमान में पायलट के करीबी मुरारी लाल मीणा दौसा से सांसद हैं। इधर, दौसा की कुछ सीटों पर किरोड़ी भी प्रभावी हैं। देवली-उनियारा भी मीणा बहुल इलाका है और किरोड़ी के लिए यहां परफॉर्म करना साख का सवाल है। देवली उनियारा जिस जिले के अधीन है। उसी जिले की टोंक से सचिन पायलट विधायक भी हैं। दौसा और देवली दोनों ही सीटों पर पायलट समर्थकों को टिकट दिया गया है, जबकि किरोड़ी ने दौसा में अपने भाई को मैदान में उतार दिया है। कहा जा रहा है कि किरोड़ी अगर दौसा नहीं जीतते हैं तो मंत्री पद छोड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से ही किरोड़ी लाल मीणा मंत्रालय नहीं जा रहे हैं।

राजस्थान में सबसे ज्यादा चर्चा खींवसर सीट की है, जहां त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। क्योंकि यहां से भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और आरएलपी के हनुमान बेनीवाल की ये परंपरागत सीट है। पिछली बार भाजपा के प्रत्याशी को आरएलपी ने बहुत कम वोटों के अंतर से हराया था। ऐसे में देखना होगा कि क्या बेनीवाल अपना सियासी गढ़ बचा पाते हैं या फिर भाजपा अपना कमल खिलाकर ले जाएगी। 2023 में आरएलपी महज एक सीट राजस्थान में खींवसर जीती थी, जहां से हनुमान बेनीवाल विधायक चुने गए थे। उपचुनाव में बेनीवाल ने खींवसर सीट से अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को उतारा है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी के चलते मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। ऐसे में उपचुनाव में असल इम्तिहान हनुमान बेनीवाल का है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने वाले हनुमान बेनीवाल उपचुनाव के सियासी मंझधार में अकेले पड़ गए हैं। कांग्रेस ने खींवसर विधानसभा सीट पर डॉ. रतन चौधरी को उतारा है तो भाजपा ने रेवंतराम डांगा पर दांव खेला है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल ने अपनी परंपरागत सीट से अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को उतारकर अपने सियासी वर्चस्व को बरकार रखने की स्ट्रैटेजी अपनाई है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा के सियासी चक्रव्यूह के चलते बेनीवाल के लिए खींवसर सीट पर अपना दबदबा बनाए रखना आसान नहीं है? राजस्थान की सियासत में किंगमेकर बनने की कवायद में हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया था। बेनीवाल अपने पहले ही चुनाव में तीन सीटें 2018 में जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन पांच साल में आरएलपी का सियासी रंग फीका पड़ गया।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

यूटर्न लेगी पायलट-किरोड़ी की सियासत

2023 के विधानसभा चुनाव में किरोड़ी लाल मीणा के बूते भाजपा ने दौसा और टोंक-सवाईमाधोपुर में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। दौसा लोकसभा की 8 में से 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। 3 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इसी तरह टोंक-सवाईमाधोपुर की 8 में से 4 सीटों पर भाजपा और 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। सवाईमाधोपुर सीट पर खुद किरोड़ी लाल मीणा जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। हालांकि, लोकसभा चुनाव में पायलट ने बदला ले लिया। 2024 के चुनाव में दोनों ही सीट पर भाजपा हार गई। वो भी तब, जब किरोड़ी लाल मीणा ने अलल-ऐलान किया था कि हार के बाद मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा। अब कहा जा रहा है कि इस उपचुनाव में अगर भाजपा परफॉर्म नहीं कर पाई तो किरोड़ी के साथ खेल हो सकता है। वहीं कांग्रेस अगर हारती है तो पायलट के गुर्जर, मीणा और दलित समीकरण में बड़ा सेंध लग जाएगा।

उपचुनाव में होगा नारे का लिटमस टेस्ट

उप्र की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे के प्रभाव की भी परख होगी। वजह ये है कि उपचुनाव को खुद फ्रंट से लीड कर रहे उप्र के मुख्यमंत्री के इस नारे को विपक्ष की जातीय गोलबंदी के काट के तौर पर देखा जा रहा है। इस नारे ने हाल ही में हरियाणा चुनाव में रंग दिखाया है और महाराष्ट्र, झारखंड में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ रही है। ऐसे में उप्र उपचुनाव की रैलियों और जनसभाओं में ये नारा गूंज रहा है। वहीं अब इस नारे को संघ का समर्थन मिलने के बाद 2027 में उप्र विधानसभा चुनाव में भाजपा की सियासी रणनीति इसके इर्द-गिर्द होने के संकेत भी मिल रहे हैं। उप्र में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव सत्तारूढ़ भाजपा के लिए बहुत अहम है। हालांकि लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से उत्साहित विपक्ष खासतौर पर समाजवादी पार्टी प्रदेश में न सिर्फ मुखर है बल्कि उसे इसी प्रदर्शन को बनाए रखने की उम्मीद है। इस बीच उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हरियाणा चुनाव में दिया गया नारा बटेंगे तो कटेंगे उप्र उपचुनाव के केंद्र में आ गया है।

उप्र की सियासत में इन दिनों नारों को लेकर घमासान मचा है। योगी के बंटेंगे तो कटेंगे की सियासत में अखिलेश यादव और मायावती भी कूद पड़ी हैं। अखिलेश के जुड़ेंगे तो जीतेंगे की शहर में लगी होर्डिंग्स को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर वाद-विवाद हो रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस नारे को लेकर काफी आक्रामक हैं। टीवी डिबेट हो या सोशल मीडिया प्लेटफार्म, वे हर जगह सक्रिय नजर आ रहे हैं। सपा दफ्तर के बाहर इससे संबंधित एक होर्डिंग भी लगी है, जिस पर लिखा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। वहीं, योगी के नारे बंटेंगे तो कटेंगे पर एक गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव में भाजपा की ओर से यह गाना खूब बजाया जा रहा है। इससे पहले हरियाणा के चुनाव में जब उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह नारा दिया था तो पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नारे के आसपास की लाइन दी- एक हैं तो सेफ हैं। कुछ लोग तो हरियाणा में भाजपा की जीत के पीछे इस नारे को वजह भी बताने लगे हैं।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा- जिनका नजरिया जैसा उनका नारा वैसा। अखिलेश ने इसके साथ हैशटैग के साथ जुड़ेंगे तो जीतेंगे और सकारात्मक राजनीति लिखा। उन्होंने मुख्यमंत्री को नसीहत देते हुए कहा कि देश और समाज के हित में उन्हें अपनी नकारात्मक नजर और नजरिए के साथ अपने सलाहकार भी बदल लेने चाहिए, ये उनके लिए भी हितकर साबित होगा। एक अच्छी सलाह ये है कि पालें तो अच्छे विचार पालें और आस्तीनों को खुला रखें, साथ ही बांहों को भी, इसी में उनकी भलाई है। उनका नकारात्मक-नारा उनकी निराशा-नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनके जो गिनती के 10 प्रतिशत मतदाता बचे हैं अब वो भी खिसकने की कगार पर हैं। इसीलिए ये उनको डराकर एक करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य ने कहा कि इसमें जो क्रिया इस्तेमाल की जा रही है वह भविष्यकाल की है। इसका मतलब है कि अभी बंटे नहीं हैं, अभी हम एक हैं। जब एक हैं तो वह कौनसा कारण है जिसके कारण हम बंट जाएंगे। उनको कैसे पता चल रहा है कि बंट जाएंगे हम। बसपा सुप्रीमो मायावती का कहना है कि उपचुनाव में बसपा के उतरने से सपा-भाजपा की नींद उड़ गई है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए दोनों दल पोस्टरबाजी कर रहे हैं। भाजपा के बंटेंगे तो कटेंगे और सपा के जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नारों की बजाय वास्तव में होना यह चाहिए कि बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे।

अभी कुछ दिन पहले मठाधीश और माफिया को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ था। हाल ही में सपा कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगाई गई जिस पर लिखा गया सत्ताईस के सत्ताधीश। यानी मठाधीश को सत्ताधीश से जोड़ दिया गया। वहीं, योगी के बंटेंगे तो कटेंगे के नारे के जवाब में अखिलेश यादव ने एक टीवी डिबेट में नारा दिया- जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अगले ही दिन इन नारों की होर्डिंग भी शहर में दिखाई देने लगी। इसी तरह बंटेंगे तो कटेंगे की होर्डिंग भी शहर में अलग-अलग जगहों पर नजर आ रही हैं। उप्र में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, वहां भी इन नारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सत्तापक्ष बंटेंगे तो कटेंगे का नारा लगा रहा है और सपा के लोग जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में बंटेंगे तो कटेंगे का नारा खूब चर्चा में है। हरियाणा के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया यह नारा अब चुनाव का मुख्य मुद्दा बनता नजर आ रहा है।

पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भाजपा ने योगी के नारे बंटेंगे तो कटेंगे से अभी लीड ले ली है। हरियाणा चुनाव में इसका असर भी दिखा। जाट को छोड़कर बाकी जातियां एकजुट हो गईं। वहां, कांग्रेस की पूरी राजनीति जाट वोटों पर टिकी थी। सपोर्ट में मुस्लिम वोट थे। ऐसा ही कुछ उप्र में है। लोकसभा चुनाव से पहले यहां सपा का मुख्य वोटबैंक यादव और मुस्लिम रहे हैं। दलित वोटों पर बसपा का राज रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में सपा को यादव और मुस्लिम के अलावा ओबीसी की अन्य जातियों और दलित वोट मिले हैं। भाजपा को इससे नुकसान हुआ है। इसलिए भाजपा इस नारे को घर-घर तक पहुंचाने में लगी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिले इस फायदे का असर उप्र में भी दिख सकता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव इस पर मुखर होकर बोल रहे हैं। उनके पीडीए (पिछड़ा-दलित और अल्पसंख्यक) की तोड़ यही नारा हो सकता है। फौरी तौर पर भाजपा को इससे फायदा होता दिख रहा है।

राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र कुमार कहते हैं, योगी को लग रहा है कि हरियाणा में जो नारा दिया था वह कामयाब हुआ। उन्हें संघ का भी साथ मिला है और संघ ने इस नारे के इस्तेमाल को हरी झंडी दे दी। अब इसे आगे के चुनावों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा डराकर लोगों से वोट लेना चाहती है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उससे भाजपा के लोग घबरा गए। हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने के लिए यह नारा दिया गया है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि अखिलेश यादव के पीडीए से जो नुकसान हुआ, उसे कम करने के लिए भाजपा ने दो रणनीति अपनाई है। पहली रणनीति यह है कि विराट हिंदू एकता के मुद्दे पर आगे बढ़ा जाए। उसके लिए नारा दिया गया बंटेंगे तो कटेंगे और दूसरी रणनीति पिछड़ों को प्रतिनिधित्व देने की रही है। हाल में आयोगों में नियुक्तियां हों या उपचुनाव में टिकटों का बंटवारा रहा हो, सभी पिछड़ी जातियों का भाजपा ने ख्याल रखा है। इसे पीडीए इफेक्ट कहा जा सकता है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

पीके के निशाने पर कौन?

चर्चित चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की नवनिर्मित जन सुराज पार्टी ने राज्य में होने वाले चार विधानसभा उपचुनावों में तरारी सीट से सेना के रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल श्रीकृष्ण सिंह को उम्मीदवार बनाकर सियासी हलचल पैदा कर दी है। वे बिहार से दूसरे बड़े चर्चित सैन्य अधिकारी रहे हैं और तरारी के करथ गांव के रहने वाले हैं। उनके पहले दिवंगत लेफ्टिनेंट जनरल (रि.) एसके सिन्हा बेहद चर्चित हुए थे और सियासत में पहली बार पटना लोकसभा सीट से निर्दलीय उतरे थे, हालांकि वे कामयाब नहीं रहे। बाद में उन्हें जम्मू-कश्मीर और असम का राज्यपाल बना दिया गया था। प्रशांत किशोर ने आगामी चारों उपचुनावों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की सभी 243 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। किशोर के न सिर्फ उम्मीदवारों के चयन, बल्कि अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के चयन में भी नीतीश और लालू-तेजस्वी विरोधी रणनीति की झलक मिलती है। मार्च 2025 तक के लिए पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष मधुबनी के रहने वाले भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी तथा चार देशों में राजदूत रह चुके मनोज भारती को बनाया गया है। सभी चार सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में अपने उम्मीदवारों के ऐलान और जीतने का भरोसा जताने के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि 2025 के चुनाव की झलक इसी उपचुनाव में दिख जाएगी।

यूं तो जन सुराज पार्टी कहती है कि वह जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेगी, मगर प्रशांत किशोर मनोज भारती की जाति की चर्चा करना नहीं भूलते। दो अक्टूबर को पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में आयोजित रैली में प्रशांत ने मनोज भारती का परिचय करवाते हुए दलित शब्द पर खास जोर दिया था। वे दलितों को भी अच्छी संख्या में उम्मीदवार बनाने और हर संसदीय क्षेत्र में कम से कम एक महिला उम्मीदवार उतारने की बात कहते रहे हैं। जहां तक मुसलमानों की बात है, हाल के दशक में मोटे तौर पर भाजपा के खिलाफ एकतरफा वोटिंग का ट्रेंड रहा है, लेकिन भाजपा विरोधी दलों की उपेक्षा के कारण मुसलमानों में असंतोष होने के बावजूद विकल्पहीनता की स्थिति है। प्रशांत किशोर की नजर इसी पर है। वे मुस्लिम समुदाय से अच्छी संख्या में टिकट देने की बात करते रहे हैं। राजनीति में अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी पर वे कई कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। सितंबर के प्रारंभ में पटना के बापू सभागार में जन सुराज के कार्यक्रम राजनीति में मुसलमानों की भागीदारी में प्रशांत किशोर ने आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी के जिक्र के साथ बिहार की 40 विधानसभा सीटों पर मुसलमान उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था। उन्होंने यह भी ऐलान किया था कि पार्टी का नेतृत्व 25 लोगों की टीम करेगी जिसमें चार-पांच मुसलमान होंगे। उसके पहले वे 75 सीटों पर मुसलमानों को उतारने की बात कह चुके हैं। पूर्व मंत्री मोनाजिर हसन, जनता दल राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय संयोजक रहे तथा धार्मिक संस्थाओं में गहरी पैठ रखने वाले अशफाक रहमान, जैसे कई अल्पसंख्यक चेहरों को वे अपने साथ जोड़ चुके हैं। इससे वोटों की उनकी घेरेबंदी को समझा जा सकता है। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और जनता दल-यूनाइटेड (जदयू) में विशेष बेचैनी है।

पिछला लोकसभा चुनाव उदाहरण है जब पूर्णिया, वैशाली, औरंगाबाद और काराकाट में पार्टी की प्रतिबद्धता किनारे पड़ गई और जाति का जोर मजबूत साबित हुआ, लेकिन चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव एक परीक्षा है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में स्पष्ट होगा कि दूसरों की जीत की गारंटी करने वाले पीके अपनी पार्टी के लिए क्या कर पाते हैं। दो साल पहले गांधी जयंती पर चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से समूचे राज्य की अपनी पदयात्रा शुरू करते हुए प्रशांत ने अपने भाषण में कहा था, मेरे कड़े आलोचकों को भी पता है कि प्रशांत किशोर को कुछ आए या नहीं लेकिन चुनाव लड़ाना आता है। जिसका भी हाथ पकड़कर चुनाव लड़वाएंगे सामने वाले का दांत खट्टा हो जाएगा। तब से प्रशांत किशोर प्रदेश में गांव-गांव पैदल घूमकर पांच हजार किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर चुके हैं। इस बार गांधी जयंती पर उन्होंने अपनी जन सुराज पार्टी की स्थापना की घोषणा की। उनके निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद के लालू प्रसाद यादव बराबर हैं, हालांकि भाजपा पर उनके प्रहार उतने तीखे नहीं हैं। वे पूरी पदयात्रा में अपने भाषणों में लगातार कहते रहे हैं, आपने देखा कि लालू आए, नीतीश आए लेकिन कुछ भी नहीं बदला। मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया हूं। इसलिए आया हूं कि आप अपने बीच से अच्छे लोगों को चुनकर निकालिए और उन्हें वोट दीजिए ताकि आपके बच्चों को बिहार छोड़कर नहीं जाना पड़े। प्रशांत किशोर कोई दस हजार करोड़ रुपए की कंपनी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आइपैक) के मालिक रहे हैं। करीब एक दशक तक वे तकरीबन हर किस्म की राजनीति करने वाले दलों के लिए वोट प्रबंधन का काम करते रहे हैं। उनकी शुरुआत 2013 में नरेंद्र मोदी के भाजपा का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने से दो साल पहले ही हो गई थी जब मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने किशोर की सेवाएं ली थीं।

● **विनोद बक्सरी**

नीतीश के संकटमोचक थे प्रशांत कुमार

आज नीतीश पर निशाना साध रहे प्रशांत ने 2015 में जदयू और राजद के महागठबंधन के लिए चुनावी रणनीति बनाने की जिम्मेदारी संभाली थी। प्रशांत ने ही कथित तौर पर नीतीश के साथ निश्चय और विकास की गारंटी का नारा जनता तक पहुंचाया और उन्हें कामयाबी दिलाई, जिसके चलते नीतीश उनसे इस कदर प्रभावित हुए कि उन्हें अपना सलाहकार बना लिया। 2016 में प्रशांत ने पंजाब चुनाव में कांग्रेस को अपनी सेवाएं दीं। वहां कांग्रेस सत्ता में लौट आई। फिर 2017 में उप्र में कांग्रेस ने दोबारा प्रशांत को आजमाया, लेकिन वहां उन्हें विफलता मिली। उसी साल वाईएस जगनमोहन रेड्डी के लिए उन्होंने चुनावी प्रबंधन की और आंध्रप्रदेश की 175 में 151 विधानसभा सीटों पर जगन को जीत दिलवाकर वाईएसआरसीपी की सत्ता में वापसी करवाई। फिर 2020 में प्रशांत ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सेवाएं दीं और 2021 में ममता बनर्जी के साथ बंगाल में तथा एमके स्टालिन के लिए तमिलनाडु में काम किया। बिहार में सियासी हलकों में चर्चा है कि प्रशांत कहीं भाजपा की ओर से तो नहीं खेल रहे हैं।

बांग्लादेश में चुनाव कराने की मांग

बांग्लादेश में एक प्रमुख राजनीतिक दल के हजारों कार्यकर्ताओं ने देश की राजधानी में रैली की और नए चुनाव और तत्काल सुधारों की मांग की। बता दें कि अगस्त में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद देश अंतरिम सरकार के अधीन है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने रैली का आयोजन किया था। यह पार्टी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर त्वरित सुधार लाने और अगला चुनाव कराने के लिए दबाव डाल रही है। दरअसल वंशवादी राजनीतिक ढांचे में हसीना और जिया मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं। जिया बीमार हैं और व्यक्तिगत रूप से रैली का नेतृत्व करने में असमर्थ थीं और उनके बड़े बेटे, तारिक रहमान, उत्तराधिकारी हैं और 2008 से निर्वासन में रह रहे हैं। बीएनपी कार्यकर्ता ढाका की सड़कों पर उतरे और देश के राष्ट्रीय संसद भवन तक पहुंचने से पहले प्रमुख मार्गों से होकर मार्च किया। यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने अगले चुनाव के लिए कोई समयसीमा घोषित नहीं की है। बीएनपी ने शुरू में तीन महीने में चुनाव की मांग की थी। जब यूनुस ने छात्र नेतृत्व वाले जन विद्रोह के बीच 5 अगस्त को शेख हसीना के देश से भागकर भारत आने के तीन दिन बाद सत्ता संभालने की मांग की थी।

बीएनपी नेताओं ने पहले कहा था कि यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार को लंबे समय तक सत्ता में रहने के बजाय चुनाव कराने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन पार्टी कुछ सुधार लाने के लिए सरकार को उचित समय देना चाहती है। रहमान ने लंदन से वीडियो-कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि अंतरिम सरकार को किसी भी स्थिति में विफल नहीं होने दिया जाना चाहिए। क्योंकि सरकार देश में व्यवस्था लाने के लिए गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी और उसके सहयोगियों को भी नए राजनीतिक परिदृश्य से निपटने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अगले चुनाव के बारे में किसी भी सीधे संदर्भ से बचते हुए रहमान ने कहा कि सरकार को लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

बीएनपी नेताओं ने हाल ही में संकेत दिया है कि अगर अंतरिम सरकार अगले चुनाव के लिए रोडमैप तैयार नहीं करती है तो पार्टी दो से तीन महीनों में सड़क पर विरोध प्रदर्शन की योजना पर आगे बढ़ेगी। रहमान ने अपने उत्साही समर्थकों से सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि हसीना की पूर्व सरकार के सहयोगी अभी भी सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि निर्वासित तानाशाहों के सहयोगी अभी भी देश और विदेश में, शासन और प्रशासन में मौजूद हैं, जो अंतरिम सरकार को अस्थिर करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इस अंतरिम सरकार को किसी भी परिस्थिति में विफल नहीं होने दिया जाना चाहिए। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। देश में महंगाई आसमान छू रही है और इससे निजात पाने का फिलहाल कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार को 3 महीने हो चुके हैं और इस बीच महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के मुताबिक महंगाई दर बीते 3 महीनों के उच्चतम स्तर पर है। अगस्त में 10.49 और सितंबर में 9.92 फीसदी के बाद अक्टूबर महीने में महंगाई दर 10.87 फीसदी तक पहुंच गई है। इससे पहले हिंसक आंदोलन के दौरान जुलाई में महंगाई दर 11.66 फीसदी तक बढ़ गई थी। शेख हसीना सरकार के कार्यकाल में इस साल 7 महीनों में से जुलाई के अलावा बाकी सभी 6 महीनों में महंगाई दर 10 फीसदी से नीचे यानी सिंगल डिजिट में ही रही लेकिन यूनुस सरकार के आते ही यह 3 महीने में दो बार डबल डिजिट को पार कर चुकी है।

अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर भी सितंबर की तुलना में 2 फीसदी से ज्यादा बढ़कर 12.66 फीसदी तक पहुंच गई। वैसे तो कोरोना महामारी के बाद से ही बांग्लादेश में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन पिछले साल मार्च से महंगाई दर 9 फीसदी से ज्यादा ही रही है। हालांकि शेख हसीना सरकार ने इस साल के शुरुआती 6 महीनों में महंगाई दर को नियंत्रित रखने में काफी हद तक कामयाबी हासिल की थी लेकिन जून के अंत में हुए आरक्षण विरोधी आंदोलन के कारण जुलाई में महंगाई अचानक से बढ़ गई। अंतरिम सरकार में बीते 3 महीने में ही 2 बार महंगाई दर डबल डिजिट को पार कर चुकी है। महंगाई दर को काबू करने के लिए अंतरिम सरकार ने हाल ही में एक बैठक की। अंतरिम सरकार के वित्त-वाणिज्य मंत्री सलेहउद्दीन अहमद, प्लानिंग एंड एजुकेशन एडवाइजर वहीदुद्दीन महमूद और पावर, एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्स एडवाइजर मोहम्मद फौजुल कबीर खान समेत कई अधिकारी बैठक में शामिल रहे। सरकार ने फैसला किया है कि बांग्लादेश के एक करोड़ परिवारों को फैमिली कार्ड पर मिलने वाले चावल की मात्रा को दोगुना कर दिया जाएगा, साथ ही बाजार निगरानी की रणनीति में बदलाव किया जाएगा जिससे महंगाई को काबू किया जा सके।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

12-18 महीनों में कम होगी महंगाई!

बांग्लादेश बैंक के गवर्नर अहसान एच. मंसूर ने बैठक के बाद कहा है कि ग्लोबल मार्केट की स्थिति को देखते हुए घरेलू स्तर पर किए गए उपायों से महंगाई कम होगी। हालांकि इसमें काफी वक्त लग सकता है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर मौद्रिक नीति को सख्त करने के लिए उठाए गए कदमों से 12 से 18 महीने में महंगाई के नियंत्रण पर प्रभाव पड़ता है। मंसूर ने कहा कि हमें धैर्य रखने की जरूरत है और नीतियों को भी काफी धैर्य के साथ लागू करना होगा। बांग्लादेश बैंक के गवर्नर के इस बयान से समझा जा सकता है कि जनता को महंगाई से राहत फिलहाल नहीं मिलने वाली है, अगर सबकुछ ठीक रहा तो हो सकता है एक से डेढ़ साल बाद इसमें कुछ कमी आए, लेकिन यूनुस सरकार की नीति और नीयत को देखते हुए यह मुश्किल ही लगता है।

ट्रम्प की सत्ता में वापसी...

एक शानदार जीत के बाद अब डोनाल्ड ट्रम्प आगामी 20 जनवरी 2025 को विश्व के सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश होने के कारण दुनिया का चौधरी भी है, इसलिए सारे विश्व की नए राष्ट्रपति से कुछ अपेक्षाएं भी होंगी तो रूस और चीन जैसे कुछ देशों को उनसे आशंकाएं भी होनी स्वाभाविक ही है। पिछले ट्रम्प प्रशासन (2017-2021) के दौरान भारत-अमेरिका संबंधों में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन कुल मिलाकर इसे भारत का मिलाजुला अनुभव कहा जा सकता है। उस समय ट्रम्प प्रशासन के दौरान भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों में कुछ अहम पहलुओं पर जोर दिया गया था।

भारत को भी इस शक्तिशाली देश के सर्वाधिक शक्तिशाली नेता से अवश्य ही कई अपेक्षाएं हैं। चूंकि डोनाल्ड ट्रम्प से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत संबंध भी हैं इसलिए अगले ट्रम्प प्रशासन से हमारी कुछ ज्यादा ही अपेक्षाएं होनी स्वाभाविक ही है। पिछले ट्रम्प प्रशासन के दौरान भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों में मजबूती आई थी। दोनों देशों ने विभिन्न रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए और सैन्य सहयोग बढ़ाया। कम्बाइंड मिलिटरी एक्सरसाइज और भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा देने से रणनीतिक साझेदारी को प्रोत्साहन मिला। पिछले ट्रम्प प्रशासन (2017-2021) ने चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखा था।

भारत और अमेरिका दोनों ही चीन के आक्रामक रवैये के खिलाफ मिलकर काम करने की ओर अग्रसर हुए। भारत-चीन सीमा विवाद के दौरान अमेरिका ने भारत के पक्ष में कई बयान दिए, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को एक रणनीतिक दिशा मिली थी। अत: भारत और अमेरिका के बीच चीन के प्रभाव को चुनौती देने के लिए साझा रणनीतियां बनाने की उम्मीद की जा सकती है। ट्रम्प प्रशासन ने पहले भी भारत को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख भागीदार के रूप में देखा था। अगला ट्रम्प प्रशासन खासकर सीमा विवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा मामलों में भारत के प्रयासों का समर्थन कर सकता है। अब भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग में और विस्तार की संभावना है, जिससे भारत को अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों और तकनीकी सहयोग का लाभ मिल सकता है। इससे भारत की सैन्य ताकत बढ़ने के साथ-साथ दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी भी और मजबूत होगी।

पिछले ट्रम्प प्रशासन के दौरान व्यापार विवादों में वृद्धि हुई। अमेरिका ने भारत पर अपने व्यापार घाटे को कम करने के लिए दबाव डाला था। इसके अलावा ट्रम्प ने भारत की उच्च टैरिफ और ड्यूटी जैसे कुछ व्यापारिक निर्णयों को लेकर आलोचना की थी। हालांकि उस दौर में रक्षा उपकरणों की बिक्री जैसे कुछ महत्वपूर्ण समझौते भी हुए थे जो दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में सहायक थे। अगला ट्रम्प प्रशासन इन मुद्दों को फिर से उठा सकता है। हालांकि यदि दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत होते हैं, तो भारत को अमेरिका के साथ व्यापार समझौतों में कुछ लचीलापन और बेहतर साझेदारी की उम्मीद हो सकती है। भारत को उम्मीद हो सकती है कि अगला ट्रम्प प्रशासन व्यापारिक फैसलों में अमेरिका फर्स्ट दृष्टिकोण अपनाएगा, लेकिन वह भारत से अपने व्यापार घाटे को घटाने के लिए भी दबाव बना सकता है। इस बार भारत को अमेरिका से मित्रतापूर्ण बीजा नीति की भी अपेक्षा रहेगी। पिछली बार ट्रम्प प्रशासन की वीजा नीति, विशेष रूप से एच-1बी वीजा को लेकर भारतीय पेशेवरों के लिए अनुकूल नहीं थी। ट्रम्प के प्रशासन ने प्रवासी नीति को सख्त किया था जिससे भारतीय प्रवासियों और पेशेवरों, खासकर एच-1बी वीजा धारकों के लिए कुछ चुनौतियां उत्पन्न हुईं।

ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट नीति ने वीजा आवेदनों पर प्रतिबंध और अन्य नियमों में कड़ाई लाने का प्रयास किया था। अब भारत को उम्मीद हो सकती है कि ट्रम्प प्रशासन अपने अमेरिका फर्स्ट दृष्टिकोण के तहत प्रवासी नीति को सख्त रखे लेकिन यदि कोई सुधार होता है तो भारतीय पेशेवरों को वीजा प्रक्रिया में राहत मिले। भारतीयों के अमेरिका में योगदान को लेकर ट्रम्प प्रशासन की नीतियों में कुछ सकारात्मक संकेत भी हो सकते हैं, जैसे भारतीय समुदाय के लिए विशेष योजनाएं और सम्मान। भारत एशिया में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में ट्रम्प प्रशासन से अपनी वैश्विक भूमिका को और बढ़ाने की उम्मीद कर सकता है। विशेषकर भारतीय अर्थव्यवस्था, लोकतांत्रिक मूल्य और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर ट्रम्प प्रशासन से सहमति और समर्थन मिल सकता है।

● **कुमार विनोद**

जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण नीति

ट्रम्प प्रशासन ने 2017 में पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया था और यह निर्णय भारत सहित कई देशों के लिए चिंताजनक था। ट्रम्प के पुनः राष्ट्रपति बनने पर भारत को यह चिंता हो सकती है कि वह फिर से इस समझौते से बाहर हो सकता है, जिससे वैश्विक जलवायु प्रयासों को नुकसान पहुंचेगा। हालांकि, भारत की अपेक्षा हो सकती है कि ट्रम्प प्रशासन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी रणनीति को पुनः प्राथमिकता दे, भले ही पेरिस समझौते में शामिल होने की संभावना कम हो। पिछले ट्रम्प प्रशासन के दौरान, अमेरिका ने विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वित्तीय सहायता कम करने की कोशिश की थी। भारत, एक विकासशील देश होने के नाते, अपनी आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ पर्यावरणीय जिम्मेदारियों का संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। ट्रम्प प्रशासन से भारत यह अपेक्षाएं कर सकता है कि वह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के वित्तीय और तकनीकी समर्थन में सहायता प्रदान करेगा, खासकर हरित ऊर्जा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देने के मामले में। ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों को काफी महत्व दिया गया। मोदी-ट्रम्प की मुलाकातों को भारत में एक सकारात्मक कदम माना गया और उस समय ट्रम्प ने मोदी की सार्वजनिक रूप से सराहना भी की, खासकर हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रम्प जैसे आयोजन हुए थे।

एनीमिया महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन

वर्षों से अपने पेशे और उससे इतर कामों के दौरान मैं इस एक हकीकत से हमेशा रू-ब-रू होती रही हूँ कि भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर तमाम बातों और कार्रवाईयों में लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ है। दूसरी तरक्कियां हुई हैं और अहम बदलाव भी हुए हैं लेकिन दूसरे मसलों की तुलना में यह समस्या और बढ़ी ही है। जिस दुनिया में महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों को सक्रियता से प्राथमिकता दी जाती हो, ऐसी दुनिया बनाने के लिए जब तक निरंतर एक सार्थक संवाद और प्रतिबद्ध कार्रवाई नहीं की जाती तब तक हम वास्तविक बदलाव नहीं देख सकते।

भारत में, महिलाओं के स्वास्थ्य के मसले को प्राय: धुंधले चश्मे से देखा जाता है, उनके जीवन के विशेष चरणों या उनकी उपलब्धियों पर ही जोर दिया जाता है। इस देश की आधी से ज्यादा महिलाएं खून की कमी यानी कि एनीमिया से पीड़ित हैं लेकिन इस मसले पर तभी ध्यान दिया जाता है जब महिला गर्भवती होती है। एक मां के रूप में अपनी पहचान से अलग, महिलाओं में खून की कमी उनकी कुल सेहत पर कितना दीर्घकालिक और घातक असर डाल सकती है उसका क्या? एक महिला की जिंदगी इसके कारण रोज जिन चुनौतियों से गुजरती है, उनका क्या? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) की एक दूत के रूप में मुझे मुंबई की **झोपड़पट्टियों** में रहने वाली महिलाओं के बीच काम करने का मौका मिला। मैंने पाया कि वह समुदाय इस बात को लेकर आमतौर पर जागरूक है कि महिलाओं के चेहरे पर पीलापन स्वास्थ्य संबंधी किन वजहों से आता है, कि इसका संबंध उनमें खून की कमी से है। लेकिन लापरवाही के कारण इस मसले की गंभीरता की उपेक्षा कर दी जाती है।

खून की कमी मुख्यत: अपौष्टिक भोजन के कारण होती है और यह स्त्री-पुरुष की भूमिकाओं के बारे में बनी गहरी धारणाओं का नतीजा है। खासकर गांवों के अधिकतर घरों में महिलाएं परिवार की जरूरतों को अपनी निजी जरूरतों से ज्यादा महत्व देती हैं। भारत में, यह महिलाएं प्राय: घर में सबसे अंत में भोजन करती हैं और अक्सर ऐसा होता है कि अधिकांश पौष्टिक भोजन परिवार के दूसरे सदस्यों के हिस्से में चला जाता है। आत्मत्याग की यह भावना भारतीय महिलाओं को घुट्टी में पिलाई गई है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम न केवल उन्हें खुद बल्कि परिवार के बाकी सदस्यों को भी भुगतने पड़ते हैं। इसके कारण पीढ़ी-दर-पीढ़ी को खून की कमी के दुष्चक्र से गुजरना पड़ता है। सामाजिक धारणाओं के अलावा, कीमत भी अहम भूमिका निभाती है। मैं ऐसी औरतों से मिल चुकी हूं जो अपनी पूरी कोशिश के बावजूद खुद को ऐसे दुष्चक्र में फंसा पाती हैं कि पौष्टिक भोजन और स्वास्थ्य सेवा उनकी पहुंच से दूर ही रहती है। मांस, मछली, पत्तेदार हरी सब्जियों जैसे आयरन युक्त आहारों की कीमत इतनी है कि ये कई लोगों की पहुंच से दूर ही रहते हैं। ये उपलब्ध भी हों, तो उनके महत्व के बारे में जानकारी की कमी के कारण उनका नाकाफी उपभोग किया जाता है। अध्ययनों से पता चलता है कि कई महिलाओं को पौष्टिक भोजन की प्रारंभिक बातें भी नहीं पता होतीं और उन्हें यह पता नहीं होता कि संतुलित आहार के लिए क्या-क्या खाद्य सामग्री जरूरी है। हमें महिलाओं को ऐसी जानकारियां देकर ताकतवर बनाने की जरूरत है जिनके बूते वे खानपान के बारे में सोचे-समझे फैसले कर सकें। भारतीय महिलाएं अपने परिवार की खानपान की आदतें बनाने और पौष्टिक भोजन बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं। उन्हें संतुलित आहार, पौष्टिकता संबंधी जरूरतों, और स्वास्थ्यप्रद पाक विधियों के बारे में शिक्षित करने से बदलाव की लहर पैदा हो सकती है।

फिलहाल जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें सेहत संबंधी ज्ञान को शामिल किया जाना चाहिए और महिलाओं पर खासतौर से ध्यान देना चाहिए। पोषण और सेहत के बीच के संबंध के बारे में, और भोजन से पैदा होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को रोकने और उनका समाधान करने के ज्ञान के बारे में समझदारी भी इसमें शामिल है। सहायता का नेटवर्क और सपोर्ट ग्रुप्स तैयार करना भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जिनमें महिलाएं अपने ज्ञान को साझा कर सकें और एक-दूसरे को सेहतमंद खानपान अपनाने को प्रेरित कर सकें। सेहत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ हमें ऐसा वातावरण भी बनाना होगा जिसमें महिलाएं अपनी जरूरत की खाद्य सामग्री हासिल कर सकें।

महिलाओं की सेहत हमारे राष्ट्र की सेहत का आधार है। हमें ऐसे सामाजिक मानकों को खारिज करना होगा जो महिलाओं की जरूरतों को बाकी सबकी जरूरतों से नीचा बताते हैं, और ऐसी मानसिकता अपनानी होगी जो महिलाओं के कुशल-क्षेम को तरजीह देती हो। मामला केवल खानपान का नहीं है, यह गरिमा और समानता से भी जुड़ा है। महिलाएं खुद अपने पोषण की व्यवस्था कर सकें, यह ज्ञान और क्षमता देकर हम उन्हें शक्तिसंपन्न बना सकें तो हम न केवल उनमें खून की कमी की समस्या से लड़ सकेंगे बल्कि उनके लिए एक ऐसा भविष्य भी निर्मित कर सकेंगे जिसमें वे आगे बढ़ने के लिए सेहत और ताकत से लैस हो सकेंगी।

● **ज्योत्सना**

महिलाओं में सेहत के बारे में जागरुकता

शरीर में खून की कमी कुपोषण और खराब सेहत का कारण भी और परिणाम भी है। मामला केवल पर्याप्त आहार लेने का नहीं है, बल्कि सही पोषक सामग्री लेने का भी है। भारतीय आहार पारंपरिक रूप से संतुलित और पौष्टिक होते हैं। लेकिन खानपान की आगे जो रवायत बनी उसके कारण हम संतुलित आहार से दूर होते गए और प्रोसेस्ड फूड की ओर बढ़ते गए। जागरूकता की कमी के साथ, इस बदलाव ने समस्या को गहरा बना दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि खानपान की आदतें जीवन पर्यंत बनती-बदलती रहती हैं। यह पोषण में सुधार करने और खून की कमी की समस्या से लड़ने की संभावनाएं पैदा करती है। इन आदतों को बदलना हालांकि आसान नहीं होता लेकिन उन्हें बदला जा सकता है और यह जरूरी भी है। इसके लिए ऐसे सांस्कृतिक बदलाव की जरूरत है जिसमें महिलाओं की सेहत को परिवार, समुदाय और देश के कुशलक्षेम के लिए केंद्रीय महत्व दिया जाता हो।

रामचरितमानस में हर समस्या का समाधान

मनुष्य का जीवन तीन भाव से बना है, पहला हर्ष, दूसरा शोक और तीसरा भय। हर्ष का अर्थ होता है खुशी, शोक यानी की दु:ख और भय मतलब डर। अक्सर सफलता के रास्ते में डर रुकावट पैदा करता है। आमतौर पर इस डर को कम करने के लिए धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने से जीवन में सकारात्मकता बनी रहती हैं।

हम सभी के जीवन में कई तरह के उतार-चढ़ाव आते हैं। इन परिस्थितियों से निकलने के लिए कई बार रास्ते नजर नहीं आते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसीदास द्वारा लिखी गई श्रीरामचरितमानस की चौपाइयों में जीवन की हर समस्या का समाधान छिपा है। माना जाता है कि इसका पाठ करने से जन्म जन्मांतरों के पाप से मुक्ति, भय, रोग आदि सभी दूर हो जाते हैं। साथ ही जीवन जीने को लेकर नई प्रेरणा की भी प्राप्ति होती है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं उन चमत्कारी चौपाइयों व उनके प्रभाव के बारे में विस्तार से।

हरि अनंत हरि कथा अनंता।
कहहिं सुनहिं बहुबिधि सब संता॥
रामचंद्र के चरित सुहाए।
कलप कोटि लगि जाहिं न गाए॥

इसका अर्थ है कि हरि अनंत हैं उनका कोई पार नहीं पा सकता है। उनकी कथा भी अनंत ही है। सभी संत लोग उस कथा को बहुत प्रकार से कहते-सुनते हैं। साथ ही ये पंक्तियां कहती हैं कि भगवान श्री रामचंद्र के सुंदर चरित्र का कोई बखान नहीं कर सकता क्योंकि सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते।

जा पर कृपा राम की होई।
ता पर कृपा करहिं सब कोई॥
जिनके कपट, दम्भ नहिं माया।
तिनके हृदय बसहु रघुराया॥

इसका अर्थ है जिन पर प्रभु श्रीराम की कृपा होती है, उन्हें कोई सांसारिक दुख छू नहीं सकता। जिन लोगों पर परमात्मा की कृपा हो जाती है उस पर तो सभी की कृपा बनी ही रहती हैं। जिसके अंदर कपट, झूठ और माया नहीं होती, उन्हीं के हृदय में रघुपति राम बसते हैं। साथ ही उनके ऊपर प्रभु की कृपा सदैव होती है।

अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर,
भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर।
काम क्रोध मद गज पंचानन,
बसहु निरंतर जन मन कानन।।

इसका अर्थ है कि हे गुणों के मंदिर! आप सगुण और निर्गुण दोनों है। आपका प्रबल प्रताप सूर्य के प्रकाश के समान काम, क्रोध, मद और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। आप हमेशा ही अपने भक्तजनों के मन रूपी वन में निवास करने वाले हैं।

कहु तात अस मोर प्रनामा।
सब प्रकार प्रभु पूरनकामा॥
दीन दयाल बिरिदु संभारी।
हरहु नाथ मम संकट भारी॥

इस चौपाई का अर्थ है कि हे भगवान श्रीराम! आपको मेरा प्रणाम और मेरा आपसे ये निवेदन है कि हे प्रभु! अगर आप सभी प्रकार से पूर्ण हैं अर्थात् आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीन-दुखियों पर दया करना आपकी प्रकृति है, अत: हे नाथ! आप मेरे भारी संकट को हर लीजिए।

होइहि सोइ जो राम रचि राखा।
को करि तर्क बढ़ावै साखा॥
अस कहि लगे जपन हरिनामा।
गईं सती जहं प्रभु सुखधामा॥

अर्थ है कि जो कुछ भी संसार में राम ने रच रखा है, वही होगा। इसलिए इस विषय में तर्क करने का कोई लाभ नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव हरि का नाम जपने लगे और सती वहां गईं जहां सुख के धाम प्रभु राम थे। रामचरितमानस में सिर्फ जीवन के लिए ही मार्गदर्शन नहीं हैं बल्कि इसमें पेरेंटिंग टिप्स भी हैं।

भगवान राम की कथाओं में कुछ ऐसी बातें छिपी हैं जो पेरेंट्स को अपने बच्चों को विचारशील और एक सम्मानित व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित करेंगी। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको रामचरितमानस से सीखने वाले कुछ खास पेरेंटिंग टिप्स के बारे में बता रहे हैं। आज की मॉडर्न पेरेंटिंग में भी ये टिप्स बहुत काम के रहने वाले हैं। रामचरितमानस सिखाती है कि हर मनुष्य अपने अनुभवों से ही सीखता है। भगवान राम की जीवन यात्रा से सीखने को मिलता है कि चुनौतियों का सामना करने और अपनी गलतियों से सीखने के बाद ही मनुष्य को प्रगति मिलती है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को अपने रास्तों पर खुद चलने देना चाहिए, उन्हें अपने निर्णय लेने देना चाहिए। बच्चे भी अपनी समस्याओं का सामना कर के खुद सीखेंगे।

भगवान राम हर किसी को सम्मान और आदर देते थे। उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। भगवान राम के जीवन से सीख सकते हैं कि सम्मान पाना हर किसी का अधिकार है। मां-बाप भी अपने बच्चों को दूसरों का सम्मान करना सिखाएं। उन्हें बताएं कि उन्हें हर किसी के साथ आदर और सहानुभूति के साथ पेश आना चाहिए। रामचरितमानस से एक सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि हमें नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। रामजी ने शूर्पणखा को अस्वीकार किया। यह दर्शाता है कि सकारात्मक रिश्ते बनाना अधिक महत्वपूर्ण होता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को टॉक्सिक लोगों से दूर रहना सिखाएं। इससे बच्चे सच्चे और अच्छे दोस्त बनाएंगे।

रामचरितमानस से सीखने को मिलता है दूसरों की बात को भी सुनना चाहिए और उसे सम्मान देना चाहिए। जैसे कि भगवान राम माता सीता की बात सुनते थे, उसका सम्मान करते हैं और उसे समझते थे। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के विचारों को महत्व देना चाहिए। इससे बच्चे अपनी बात कहने में सहज महसूस करते हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।

भगवान राम ने अपने पूरे जीवन में अनेक लोगों से सच्चे और गहरे रिश्ते बनाए हैं। उनका भाई भरत उनके प्रति अत्यंत समर्पित रहा है और भाई लक्ष्मण ने उनकी असीम सेवा की है। वहीं हनुमानजी उनके सच्चे भक्त हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को सच्चे रिश्ते बनाने की सीख दें। जो रिश्ते किसी मतलब के लिए बनते हैं, वे ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते हैं।

● **ओम**

आंखें खुल गईं

पंडित बैजनाथ जी हर साल की तरह आज दशहरे का प्रोग्राम देख कर घर आए। रावण दहन को वे शुरू से ही हर वर्ष बड़े चाव से देखते आ रहे थे। जब रावण के पुतले को आग लगाई जाती तो पटाखों की आवाज के साथ वे भरपूर जोर-शोर से तालियां बजाते। रावण से उन्हें घोर नफरत थी कि सीता माता का हरण करके उसने यह नीच काम क्यों किया था!

आज रात को सोते वक्त भी उनके दिमाग में यह बातें घूम रही थीं। जब वो गहरी नींद में सो रहे थे तो उन्हें सपना आया। हाथ में गदा पकड़े दस सर वाला रावण उसके सामने खड़ा था। देखकर बैजनाथ घबरा गया। घबराएं नहीं बैजनाथ जी! मैं तो बस आपसे यह पूछता हूं कि हर वर्ष आप मुझे इतना जलील क्यों करते हो, हर वर्ष मुझे आग लगा के खुश होते हो, क्या मेरा गुनाह इतना बड़ा था? अब बैजनाथ जी को कुछ हौंसला हुआ और बोला, लंकेश जी! सीता मैया को उठाकर जो अपराध आपने किया, वोह भी जानते हुए कि श्रीरामजी ने कोई अपराध नहीं किया था, अपराध तो लक्ष्मण ने किया था।

रावण बोला, बैजनाथ जी, पहली बात तो यह कि लक्ष्मण ने मेरी बहन का नाक काट कर उसे हमेशा के लिए बदसूरत बना दिया, मेरी बहन का गुनाह कोई नहीं था। माना कि, लक्ष्मण जी विवाहित थे लेकिन उस समय एक शख्स की एक से ज्यादा पत्नियों का चलन था जैसे रामजी के पिता जी दशरथ की थीं, गुस्से में आकर अपनी बहन का बदला लेने की खातिर मैं सीताजी को छल से लंका ले आया लेकिन मैंने सीताजी को हाथ नहीं लगाया और बकायदा एक कैदी की तरह वाटिका में रखा लेकिन बैजनाथ जी! तुम मुझे हर साल जलाकर तो खुश हो लेते हो लेकिन जो आज के भारत में महिलाओं, यहां तक कि छोटी-छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उन लोगों के पुतले कब जलाओगे!

बैजनाथ जी की आंखें खुल गई और घबराए हुए इर्द-गिर्द देखने लगे।

- गुरमेल भमरा

लाठी

घावों को सहलाती हुई नीता ने अपनी सखी सुमी का नंबर मिला लिया। उसके हर दुख-सुख की साथी थी वह। मोबाइल उठाने तक अधीरता से वह उससे हुई पिछली वार्ता बिसूरने लगी थी-

मेरा बेटा अब बड़ा हो रहा है सुमी।

तो क्या वह तेरा साथ देगा?

हां, क्यों नहीं! आखिर मैंने उसे जन्म दिया है। लोगों के उलाहनों के साथ पति के ताने भी उसके लिए ही सहती रही कि जब जवान होगा तो मेरे साथ खड़ा होगा। परिजनों के रोक-टोंक के बावजूद उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा दिला रही हूं। उसे बड़ा करते हुए न जाने कितनी बार लक्ष्मण रेखा लांघने पर मैंने अपने तन-मन पर घाव झेलें हैं।

मैं भी सोच रही थी कि पति और परिवार के दिए घाव मेरे बच्चे भरेंगे, लेकिन किशोरावस्था में ही मेरे बच्चे मेरे विरुद्ध खड़े मिलते हैं!

किंतु मेरा बच्चा मातृभक्त और आज्ञाकारी है सुमी। अभी से ही रिश्तेदारों, यहां तक कि अपने पिता से भी मेरे लिए विद्रोह कर बैठता है। भविष्य में वह मेरी लाठी अवश्य बनेगा!

कूप-मंडूक मत बन नीता, मैं तो तुझे आगाह कर रही थी। आगे तेरी इच्छा।

अतीत के गलियारे में घूमती हुई अचानक घाव पर हाथ लगते ही पीड़ा से कराह उठी- आह...!

क्या हुआ नीता, बहू आने के बाद भी तेरे पति ने तुझसे मारपीट करना नहीं छोड़ा! तेरा बेटा तेरी लाठी नहीं बना? मोबाइल पर बचपन की सखी की घबराहट भरी आवाज आई।

बेटा लाठी बना तो सुमी! सख्त लाठी बना! लेकिन वह लाठी आए दिन बहू के समर्थन में मुझपर ही तनी रहती है।

- सविता मिश्रा 'अक्षजा'

गीत

रात जब भी चांद का,
बेंदा लगाती है
सच कहूं बस प्रिय,
तुम्हारी याद आती है
उस पहर जब चांदनी,
आंगन उतरती है
बस प्रतीक्षा में तुम्हारी,
देह जलती है
दीप की लौ हर घड़ी
तब थरथराती है
स्याह नभ में
सप्तऋषि धूनी रमाते हैं
कामना को धैर्य की
डोरी थमाते हैं
किंतु फिर भी
नेह-गंगा वेग पाती है
दूरियों के बाण मन को,
भेद जाते हैं
सुप्त पीड़ाओं की इक,
ज्वाला जगाते हैं
द्वार की सांकल हवा,
तब खटखटाती है
जुगनुओं ने अनकही हर,
पीर जानी है
आंसुओं की साक्षी,
बस रातरानी है
तारिका भी यह निगोड़ी
मुंह बिराती हैं
भाग्यवश हम कुछ
विषमताओं के मारे हैं
क्या कहें इन
हस्तरेखाओं से हारे हैं
सोचकर ये आंख मेरी
डबडबाती है
रात जब भी चांद का,
बेंदा लगाती है
सच कहूं बस प्रिय,
तुम्हारी याद आती है

- वत्सला पांडेय

रोचक हुई फाइनल की जंग

विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप 2025 का फाइनल मुकाबला लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर 11 जून से 15 जून के बीच खेला जाएगा तो वहीं एक दिन रिजर्व डे के तौर पर रखा गया है यानी 16 जून को रिजर्व डे होगा। ऐसे में सवाल है कि इस बार का खिताब कौन जीतेगा? क्या भारत अभी भी फाइनल की रेस में है? भारत के अपने घर में न्यूजीलैंड से सीरीज गंवाने के बाद फाइनल की जंग को दिलचस्प बना दिया है। अब भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका के साथ साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम भी फाइनल में पहुंचने की जंग में शामिल हो गई है। भारतीय टीम को अब विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप में 6 मैच और खेलने हैं। जिसमें कम से कम भारत को 4 टेस्ट मैच जीतने ही होंगे। भारतीय टीम को अब एक टेस्ट न्यूजीलैंड और 5 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने हैं। अगर भारतीय टीम 6 में से 4 टेस्ट मैच जीतने में सफल रही तो फाइनल में जगह पक्की हो जाएगी। वहीं, अगर 6 में से तीन टेस्ट मैच जीतती है तो फिर दूसरी टीमों के परिणामों पर उसे निर्भर रहना पड़ सकता है। भारतीय टीम का इस समय जीत प्रतिशत अंक 62.82 का है और प्वाइंट्स टेबल में पहले नंबर पर है। डब्ल्यूटीसी फाइनल की प्वाइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया भारत के बाद दूसरे नंबर पर बनी हुई है। वहीं न्यूजीलैंड और श्रीलंका भी फाइनल में पहुंचने की दावेदार मानी जा रही है।

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप अंक तालिका की बात करें तो पुणे टेस्ट में हार के बाद भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की अंक तालिका में भी झटका लगा है। पुणे टेस्ट से पहले भारतीय टीम के 68.06 प्रतिशत अंक थे जबकि हार के बाद उसके अंकों का प्रतिशत 62.82 रह गया है, लेकिन अभी भी भारत पहले स्थान पर है तो ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है। हालांकि कौनसी दो टीमें फाइनल में पहुंचेंगी, ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि 5 टीमें गणितीय रूप से फाइनल की रेस में अब भी बनी हुई हैं। टॉप पर काबिज भारतीय टीम के अब तक 13 मैचों में 8 जीत, 4 हार और 1 ड्रॉ से 98 अंक हैं। वहीं दूसरे नंबर पर काबिज कंगारू टीम के 12 मैच में 8 जीत, तीन हार एवं एक ड्रॉ से 90 अंक हैं। विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (2023-25) के मौजूदा चक्र में अब सिर्फ 20 टेस्ट मैच बचे हैं। ऐसे में हार या जीत से टीमों के समीकरण बदलते नजर आएंगे।

भारत को ऑस्ट्रेलिया को पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-2 से जरूर हराना होगा, यानी उसे छह में चार मैच जीतने होंगे। इससे उसके 62.82 से 64.04 प्रतिशत अंक हो जाएंगे। अगर भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई टेस्ट हार जाती है तो उसे ऑस्ट्रेलियाई धरती पर चार जीत और एक ड्रॉ की आवश्यकता होगी। यदि भारत अपने बाकी छह में से तीन ही मैच जीत पाता है और तीन में उसे हार मिलती है तो उसका अंक प्रतिशत 58.77 होगा, जो क्वालिफिकेशन की पूरी गारंटी नहीं देगा। ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का अंक प्रतिशत भारत से ज्यादा हो सकता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की सीरीज हार ने ऑस्ट्रेलिया के फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को बढ़ा दिया है। भारत के खिलाफ 3-2 से सीरीज जीतने और श्रीलंका में 1-0 की जीत से उसका स्कोर 62.28 फीसदी होगा, जो उसे भारत से आगे रखेगा। दूसरे परिणामों पर निर्भर रहे बिना फाइनल में जगह बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया को अपने बाकी सात मैचों में से पांच में जीत की आवश्यकता होगी, ऑस्ट्रेलिया को अपनी धरती पर भारत के खिलाफ 5 टेस्ट मैच खेलने हैं, वहीं श्रीलंका टूर पर उसे दो टेस्ट मैच खेलने हैं।

श्रीलंकाई टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-0 से सीरीज जीत हासिल की थी, जिसके चलते वह फाइनल की रेस में बनी हुई है। श्रीलंका को चार मैच और खेलने हैं। यदि वे उन सभी मैचों में जीत हासिल करते हैं तो उसके 55.56 से 69.23 प्रतिशत अंक हो जाएंगे और फाइनल में उसकी जगह पक्की हो जाएगी। यदि श्रीलंकाई टीम एक मैच हार जाती है और तीन में जीत हासिल करती है, तो ऐसे में उसे बाकी परिणामों पर निर्भर रहना होगा, श्रीलंका को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से दो-दो टेस्ट मैच खेलने हैं। वर्तमान में 47.62 प्रतिशत अंकों के साथ साउथ अफ्रीका बाकी के पांचों टेस्ट जीत जाता है तो 69.44 फीसदी अंक हो जाएंगे। जो फाइनल में पहुंचाने के लिए पर्याप्त होंगे। चार जीत और एक ड्रॉ की स्थिति में अफ्रीका 63.89 पर समाप्त करेगा, जबकि पांच जीत और एक हार की स्थिति में उसके अंकों का प्रतिशत 61.11 रह जाएगा। इस स्थिति में उसे दूसरे परिणामों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इंग्लैंड को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीनों मुकाबले उसके घर पर खेलने हैं। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को अपने घर पर टेस्ट सीरीज में 2-1 से हराया है। देखा जाए तो पाकिस्तान गणितीय रूप से अब भी रेस में है लेकिन उसकी फाइनल खेलने की संभावनाएं काफी कम हैं। पाकिस्तान यदि अपने बाकी के चारों मैच जीत लेता है तो भी वह 52.38 प्रतिशत तक ही पहुंच पाएगा। पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के खिलाफ दो-दो टेस्ट मैच खेलने हैं। बांग्लादेशी टीम फाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। भारत के खिलाफ 2-0 और साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की हार से बांग्लादेश को बहुत नुकसान हुआ। वेस्टइंडीज की टीम ने पहले ही चार सीरीज खेल ली है और उसके महज 18.52 प्रतिशत अंक हैं। अगर वह अपने अंतिम चार टेस्ट जीत लेता है तो भी वह 43.59 अंकों पर ही पहुंच पाएगा। वेस्टइंडीज को बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ 2-2 मैचों की सीरीज खेलनी है।

● आशीष नेमा

दो साल का चक्र होता है टेस्ट चैम्पियनशिप

गौरतलब है कि विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप दो साल का चक्र होता है, जिसमें टेस्ट खेलने वाले देशों के बीच घरेलू और बाहरी परिस्थितियों में द्विपक्षीय सीरीज खेली जाती है। प्रतियोगिता का उद्घाटन सत्र 2019 और 2021 के बीच खेला गया था, जिसमें न्यूजीलैंड ने साउथेम्प्टन के रोज बाउल में खेले गए फाइनल में भारत को हराया था। भारतीय टीम लगातार दो बार विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंची थी। दूसरे सत्र में 2023 के फाइनल में भारत को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय टीम को इस बार ऑस्ट्रेलियाई टीम ने फाइनल में हरा दिया था। विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप का यह तीसरा संस्करण है, जो 2023 से 2025 तक चलेगा। जिसमें कुल नौ टीमों में से अभी तक वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और बांग्लादेश ही फाइनल की रेस से बाहर हुए हैं। यदि कोई टीम 60 प्रतिशत अंकों पर अपना अभियान समाप्त करती है तो उसके फाइनल में पहुंचने के आसार रहेंगे, भारत ने पिछली बार 58.8 प्रतिशत अंकों के साथ फाइनल के लिए क्वालीफाई किया था।

हीरो जिसके आने से चकनाचूर हो गया था सबका स्टारडम... पीक पर छोड़ी एक्टिंग

शशि कपूर-अमिताभ की सलाह भी नहीं मानी...

साल 1971 में धर्मेन्द्र, आशा पारेख की फिल्म मेरा गांव-मेरा देश में विनोद खन्ना ने बतौर विलेन एंट्री कर बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया था। विनोद खन्ना ने फिल्म में विलेन की भूमिका निभाकर इतिहास रच दिया था। धर्मेन्द्र के होते हुए भी सारी लाइमलाइट लूट ले गए थे। फिर एक दौर ऐसा भी आया, जब उन्होंने एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया था। कई फिल्मी सितारों ने उन्हें एक्टिंग ना छोड़ने की सलाह दी थी।

विनोद खन्ना ने दर्शकों के दिलों पर लंबे समय तक राज किया। खासतौर पर विलेन बनकर तो उन्होंने दर्शकों को अपना मुरीद बना रखा था। हीरो बनकर एंट्री करते ही वह एक्शन हीरो बनकर लोगों का दिल जीतने लगे। बड़ी पहचान पाने के बावजूद उन्होंने एक्टिंग को अलविदा कह दिया था। 1982 में अपने करियर के शिखर पर, दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना ने ओशो के कम्यून, रजनीशपुरम, ओरेगन में जाने का फैसला किया। विनोद ने बॉलीवुड छोड़कर गहरी ध्यान साधना में लीन होने का मन बना लिया और अपने परिवार को मुंबई में छोड़ दिया।

ओशो के आश्रम जाने के लिए सबकुछ छोड़ा

अमिताभ बच्चन उस समय विनोद खन्ना के टक्कर के एक्टर बनकर उभर रहे थे। कहा जाता है कि अमिताभ ने विनोद के एक्टिंग छोड़ने के बाद बॉलीवुड के अगले सुपरस्टार बनने की राह पकड़ी, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार भावना सोमाया ने बताया था कि अमिताभ ने विनोद से फिल्मों को न छोड़ने की गुजारिश भी की थी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना के करियर के लिए जिम्मेदार नहीं थे, क्या वे अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। विनोद बहुत हैंडसम और टैलेंटेड एक्टर थे; उन्होंने ओशो के आश्रम जाने के लिए सबकुछ छोड़ दिया था। उस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और ऐलान किया कि इंडस्ट्री छोड़ रहे हैं। आगे बताया गया कि उस वक्त अमिताभ बच्चन ने विनोद को रोकने की बहुत कोशिश की थी। इतना ही नहीं बताया तो ये भी गया कि शशि कपूर ने भी उन्हें कहा था कि वह जाने से पहले एक बार और इस पर विचार करें कि कई और निर्देशक और अभिनेताओं ने उनसे कहा कि यह गलत होगा, लेकिन वे इंडस्ट्री छोड़ने के अपने डिसीजन से बदले नहीं और चले गए थे।

कम्यून में जाने का फैसला स्वार्थी था... विनोद खन्ना ने भी सिमी ग्रेवाल के इंटरव्यू में बताया था कि कम्यून में जाने का उनका फैसला स्वार्थी था, लेकिन यही होना था। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे अब भी अपने इस कदम को स्वार्थी मानते हैं, तो उन्होंने कहा था, हां! जब तक आप स्वार्थी नहीं होते, आप फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि यह आपकी अपनी आत्मा है जिसे उस पार जाना होता है। सभी को अकेले ही अपना सफर तय करना होता है। आप अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं।

तुम जानते हो हमारा रिश्ता..., आमिर खान के सामने फूट-फूट कर रोई थीं मर्दानी एक्ट्रेस, ये डायरेक्टर बना था बड़ी वजह

फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं। लेकिन एक बार करण की वजह से वह फूट फूट कर रोई थीं। इस बात का खुलासा खुद रानी ने करण के शो में किया था।

एक्ट्रेस ने बताया कि आमिर खान के सामने वह करण जौहर की वजह से खूब रोई थीं। करण जौहर के लोकप्रिय चैट शो कॉफी विद करण में एक्ट्रेस ने कहा, फिल्म कल हो ना हो के बारे में दूसरों से पता चला तो मैं बहुत दुखी हुई। मैंने किसी और से यह सुना तो मुझे लगा कि करण आकर मुझे क्यों नहीं ले गया? उसने मुझसे बात

क्यों नहीं की, तुम जानते हो मेरा और तुम्हारा रिश्ता कैसा है। मुझे याद है कि मैं इस बात को लेकर आमिर खान के सामने जाकर फूट फूट कर रोई थीं। बता दें कि कल हो ना हो में शाहरुख खान, सैफ अली खान के साथ प्रीति जिंटा लीड रोल में नजर आई थीं।

2 शादियां 5 रिलेशनशिप में रहे चुके सुपरस्टार की बेटी, पिता के स्टारडम से थीं परेशान, बिना सोचे ही बदल लिया था असली नाम

सुपरस्टार कमल हासन की बेटी श्रुति हासन ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने माता-पिता के स्टारडम से निपटने वाली चुनौतियों के बारे में बात की है। इस दौरान उन्होंने कई मजेदार खुलासे भी किए। एक्ट्रेस ने बताया है कि उन्होंने अपने पिता की वजह से अपना नाम भी बदल लिया था।

कमल हासन वाणी गणपति से शादी करने से पहले एक्ट्रेस श्रीविद्या के साथ रिलेशनशिप में थे। उन्होंने शादीशुदा रहते हुए सारिका को डेट किया और बाद में सारिका से शादी भी की। सुपरस्टार के रोमांटिक जिंदगी का असर उनकी बेटी और एक्ट्रेस श्रुति हासन

पर भी पड़ा, 2 शादियां और 5 अफेयर का असर कहीं ना कहीं कमल की बेटी पर भी देखने को मिला था। एक्ट्रेस ने बताया कि जब उनसे उनके स्टार पिता कमल हासन के बारे में लोग लगातार सवाल पूछते थे तो वह परेशान हो जाती थीं।

हवा-हवाई

फिर से अइयो बदरा बिदेसी.... तेरे पंखों पे मोती जड़ूंगी... भरके जइयो हमारी तलैया...मैं तलैया किनारे मिलूंगी...

बूढ़े हाथों की कंपकंपाती उंगलियों ने ट्रांजिस्टर की आवाज को कम कर दिया। एक तपती उमस भरी रात में आंगन में लेटी नन्हीं सी आवाज ने अपने दादा से कहा, पता हौ बाबा हमारे क्लास में एक लड़का कह रहा था कि अब केवल दो मौसम होत हैं, गर्मी और ठंडी का। कह रहा था कि बारिश का मौसम न होत।

ऊंघती हुई बूढ़ी आवाज ने कहा, सही कही उसने..!

बच्ची ने पूछा, पर हमारी किताब में तो चार मौसम लिखो है।

बूढ़ी आवाज ने बस इतना कहा, पहले चार मौसम होत थे।

बच्ची ने पूछा, तो अब काहे नहीं होत..?

एक चुप्पी पसर गई फिर मानो किसी बहुत ही गहरे गड्ढे से आती आवाज से दादा ने कहा, हवा!

बच्ची नाराज हो गई, आप के पास तो हर सवाल का एक ही जवाब है... हवा।

बूढ़ी आवाज ने कहा, हवा से तो बादल आत है, बारिस आत है... हमार जमाने में चार दिशा से खुशबू लेकर आत थी वो... सुनना चाहोगी हवा की कहानी तो सुनो... हवा तब रेडियो से निकलकर आती और आंगन-गली से होते हुए घर-खेत में फैल जाती थी। एकदम ठंडी, मुलायम और मीठी हवा... और महक तो ऐसी कि बस पूछो मत... हवा...!

कहते हुए बूढ़ा एकाएक पुराने दिनों में खो गया। पुराने दिन, जब उसकी बाकी सारी चीजें नईं थीं। एक अदद नई सी साइकिल, नई पैंट, नई कमीज, हाथ में नई घड़ी और साइकिल के सामने की टोकरी पर रखा चमचम रेडियो! और हां साइकिल के पीछे बैठी उसकी नई दुल्हन। रेडियो में गाना बज रहा है, हवा में उड़ता जाय... मेरा लाल दुपट्टा मलमल का... ओजी...ओजी...।

गीत तो वह भी गुनगुना रहा है। हौले से एकबार पीछे मुड़कर कर अपनी दुल्हन को देखने की कोशिश करता है। दुल्हन शरमाकर गठरी बन जाती है पर हौले से डांटती है, सामने देख के चलिए न!

अरे हम तो बस देख रहे थे कि तुम बैठी हो न! दूल्हा बोलता है। तब तक रेडियो से आवाज आती है, ऐ हवा मेरे संग-संग चल... मेरे दिल में हुई हलचल...! दुल्हन के थोड़ी पास आकर बैठने की कोशिश में कच्ची पगडंडी पर साइकिल डगमगा जाती है। दूल्हा हौले से डांटता हुआ कहता है, अरे-अरे! सीधी बैठी रहो... अभी हम लगबगा कर गिर ही जाते और खूब जगहंसाई होती।

तब तक आशा भोंसले की आवाज में फिल्म दो बदन का गाना बज उठता है, जब चली ठंडी हवा... जब घटी काली घटा... मुझको ऐ जाने वफा... तुम याद आए...।

दूल्हा-दुल्हन ने नन्हें सपनों को जमीन में रोप दिया। पहली बारिश आई। रेडियो में बज उठा फिल्म मिस्टर एंड मिसेज 55 का गाना। संगीत ओपी नय्यर की और गीत के बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने... ठंडी हवा... काली घटा... आ ही गई झूम के...।

देखते-देखते नन्हीं सी जमीन पर झोपड़ी उग आई। अपने कामकाज में मगन दुल्हन ने गुनगुनाते हुए सुर मिलाया, प्यार लिए डोले हंसी नाचे जिया घूम के...। दीवार पर लटके बीते साल मेले में खरीदे छोटे से शीशे को देखकर कंघी करते हुए युवा किसान नजर बचाकर दुल्हन का अक्स देखता और मन ही मन शर्माता कि हो न हो यह गाना केवल उसके लिए ही गाया जा रहा है!

दिन वाकई इसी तरह जा रहे थे। इलाके में बारिश होती तो थी पर कम होती थी इसलिए जमीन तनिक रूखी-रूखी रहती। प्यास से तो इंसान रूखा हो जाता है, फिर जमीन क्या चीज है? हां, बारिश के दिन जब आसमान बादलों की मोटी चादर ओढ़ लेता तो एकाएक झमाझम बारिश शुरू होती। सूखी जमीन खूब छककर पानी पीती। कुछ पानी वह अपने तालाब-पोखरों के जेबों में जमा कर लेती।

देर रात किसान और उसकी दुल्हन दूर कहीं देखते रहते। रेडियो में फिल्म दिल का ठग का गाना बजता, ये रातें... ये मौसम... नदी का किनारा... ये ठंडी हवा...। कभी तलत महमूद का गाया फिल्म संगदिल का गीत बजता, ये हवा... ये रात... ये चांदनी...।

एक बार किसान ने गाने गुनगुनाने की कोशिश की पर उसका सुर इतना बुरा था कि दोनों हंस पड़े। उनकी हंसी के बुलबुले उनके आंगन से उड़े और चांदनी रात में दूर-दूर तक उड़ते चले गए। फिर कुछ बहुत बुरा हुआ और वह भी बहुत तेजी से। कहते हैं कि किसी की नजर लग गई इलाके को।

बूढ़ी आवाज ने कहा, पहले गांव को और फिर नन्हीं जमीन पर उगे हमारे घर को। हवा से ठंडक जाती रही। पहले जो हवा बदन में गुदगुदी पैदा करती थी अब वह तप रही थी। बीमार होने पर जैसे हम तपते हैं न ठीक उसी तरह। पहले हमारी हवा को बुखार आया। फिर जमीन को और फिर तेरी दादी को। दादी के इलाज में खेत बिक गए पर वह न बची। जब इंसान ही नहीं बचे तो फिर जमीन और हवा की बीमारी के बारे में कौन सोचता। बारिश हमारे इलाके का रास्ता भूल गई। तपती धूप ने जमीन को आवारा धूल में बदल दिया। पोखर-नदी-नालों की जेब में रखे पानी की आखिरी बूंद भी खत्म हो गई। खेती खत्म हो गई। जमीन तो जमीन किसान भी धूल में बदल गए और गांव छोड़-छोड़ कर उड़ गए और दूर-दराज के अनजाने शहरों-कस्बों में जाकर कभी किसी अमीर के दरवाजे में पहरेदार बनकर चिपक गए तो कभी रिक्शा-वाला या दिहाड़ी का मजदूर बने और अपने ही पसीने में घुलकर कर सड़क का कीचड़ बन गए।

इतनी देर तक बोलते रहने से बूढ़ी आवाज अब हांफने और खांसने लगी थी। बूढ़ी उंगलियों ने पहले खटिये के नीचे पानी खोजने की कोशिश की। वहां पानी नहीं था। उसने आंगन में पानी खोजा। पानी वहां भी नहीं था। घड़े सूख चुके थे। उसने गांव-शहरों में पानी ढूंढा। पानी वहां भी नहीं मिला। उसने आसमान से लेकर जमीन के अंदर पानी खोजना शुरू कर दिया पर पानी कहीं पर भी नहीं था। प्यास से उसका हलक सूखा जा रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा कर चीखने की कोशिश की, पर एक घुरघुरती हुई आवाज आई, हवा!!!...हवा है तो बादल आत है, बारिश आत है...।

रेडियो से आवाज आई, आइए सुनते हैं फिल्म मिस्टर इंडिया का गाना जिसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति ने बिजली गिराने मैं हूं आई... कहते हैं मुझको हवा-हवाई...।

● **अनाम**

mycem cement

HEIDELBERGCEMENT

mycem power

Trusted German Quality

Over 150 Years

Send 'Hi' 7236955555

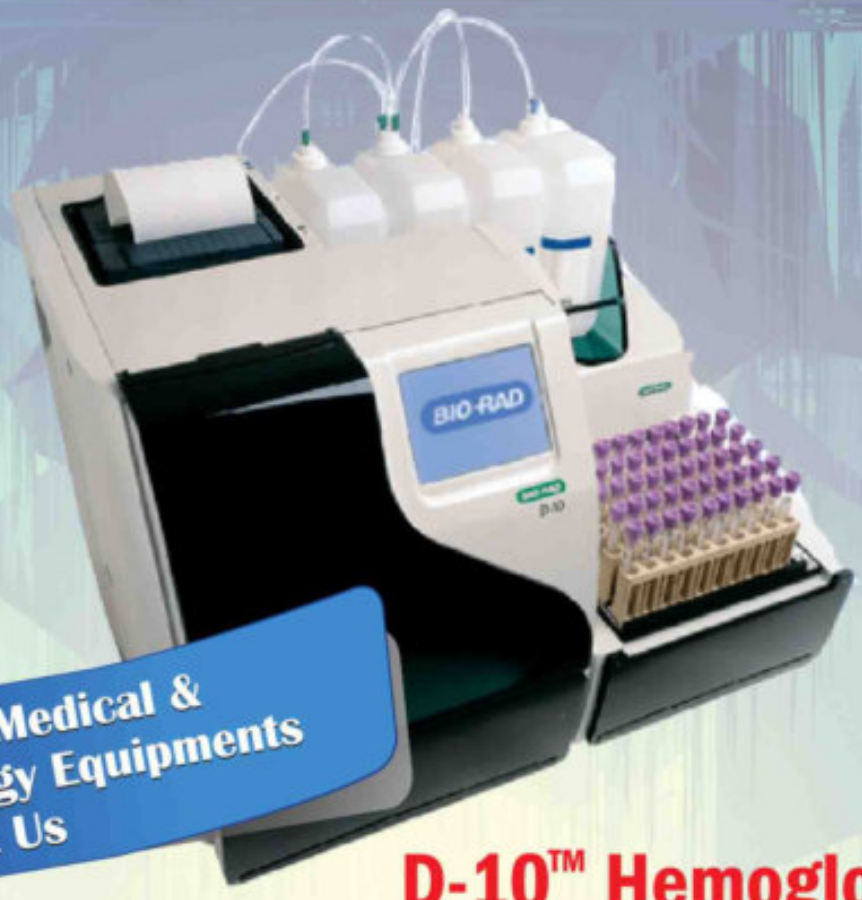

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687